R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 16
16 से 31 मई 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

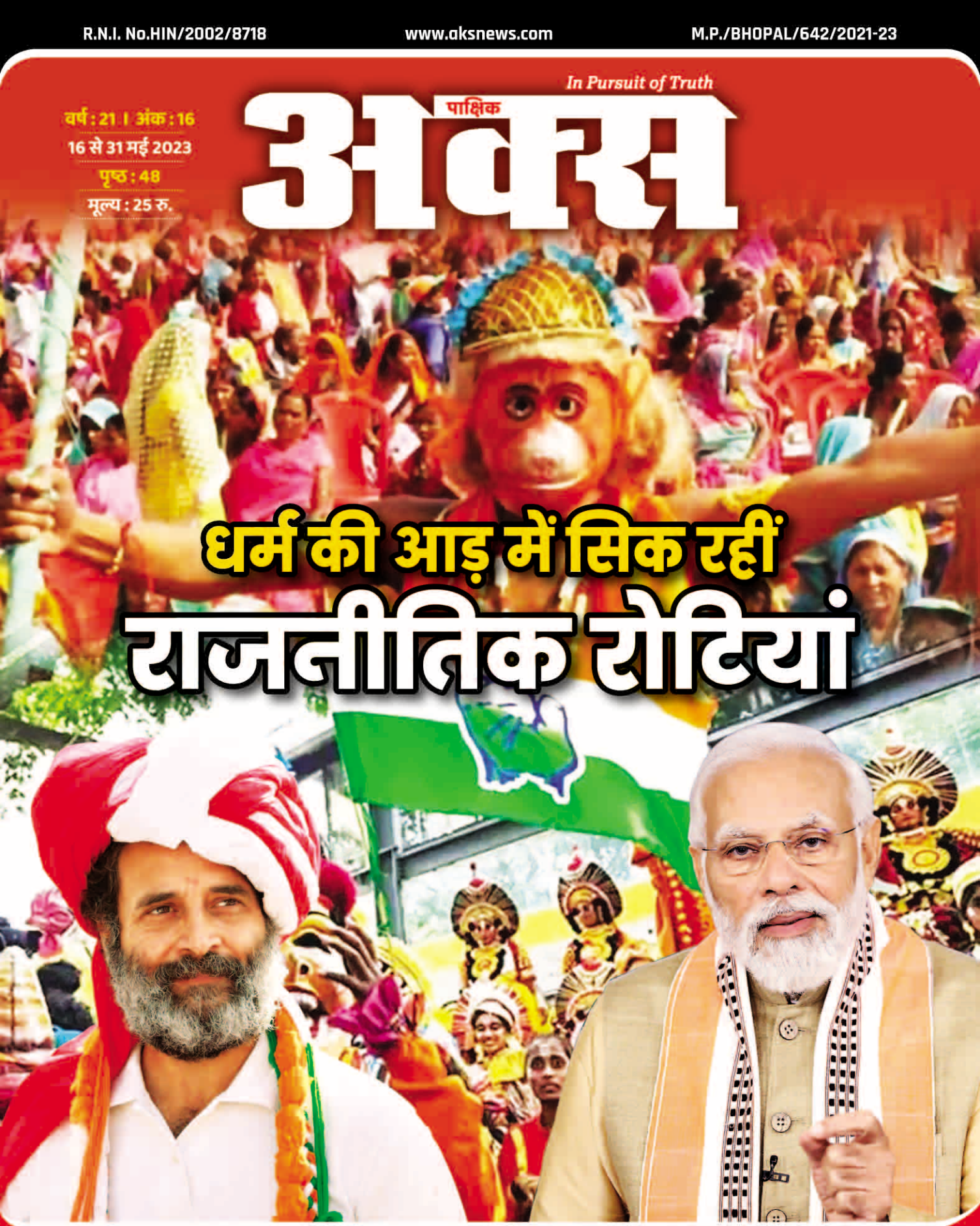

धर्म की आड़ में सिक रहीं राजनीतिक रोटियां

राम-कृष्ण और बजरंगबली कब तक बनेंगे चुनावी मोहरा

गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की किसी को चिंता नहीं

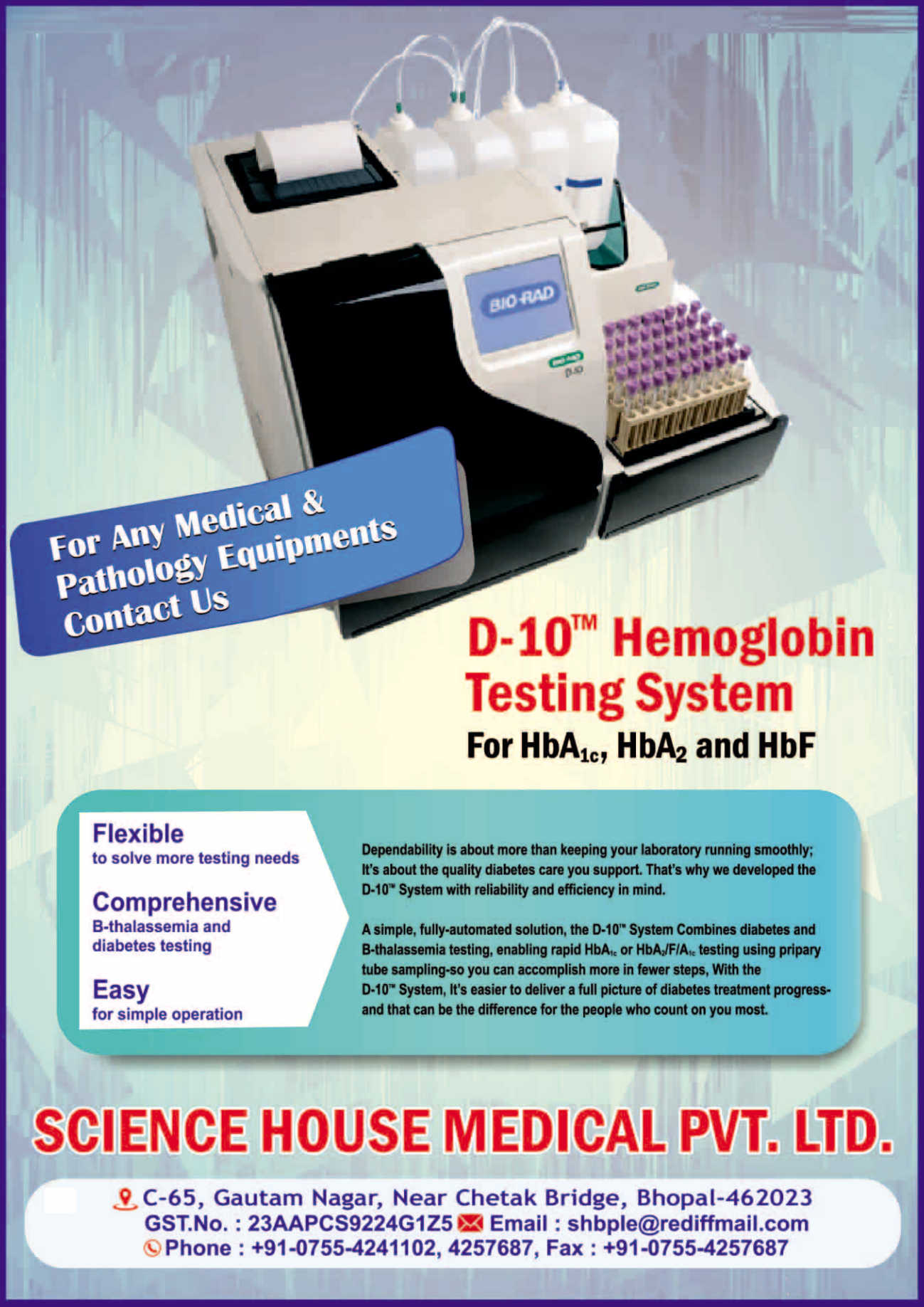

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

वल्लभगाथा

9 | अब दिल्ली दूर नहीं...

चुनावी साल में प्रशासनिक अफसरों की एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि शासन और प्रशासन के मुखिया ने यह सूची तैयार कर ली है। सूची को विधानसभा चुनाव में जमावट के अनुसार तैयार किया गया है।

राजपथ

10-11 | जीत का बना फुलप्रूफ प्लान

मप्र में 5 महीने बाद चुनावी मैदान में घमासान शुरू हो जाएगा। इस घमासान में उतरने से पहले भाजपा की पूरी कोशिश है कि वह एक ऐसी रणनीति के साथ काम में जुटे जिससे आसानी से जीत मिल सके। इसके लिए भाजपा ने...

व्यवस्था

14 | हैदराबाद की तर्ज पर मप्र...

मप्र को यहां की सरकार देश का सबसे विकसित राज्य मानती है। इसके लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मप्र के शहरों का अनियोजित विकास हो रहा है। खासकर राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर...

मप्र कांग्रेस

18 | कानूगोलू ने संभाला मोर्चा

कांग्रेस ने मप्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को आकार देने में मदद करने के लिए, प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी, चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू को शामिल किया है, जहां सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को भाजपा द्वारा सत्ता से बेदखल कर...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत को भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन आज यह विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी कई समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनेता समस्याओं को दूर करने की बजाय धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बजरंगबली, तो कभी किसी अन्य...

राजनीति

30-31 | क्या रूकेगी हेट स्पीच?

एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, और खाने के लिए कुछ और होते हैं। इसी तरह देश में जो ज्यूडिशियरी है वह भी आपस में बंटी हुई है। यह दिखता नहीं है लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया का बेल लगा तो अभिषेक मनु सिंघवी...

महाराष्ट्र

35 | आखिर क्या पका रहे पवार?

शरद पवार रोटी पलट रहे हैं। शरद पवार रोटी पलटते रहते हैं। मगर पवार की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि पवार की राजनीतिक थाली की ये आखिरी रोटी नहीं है। तो फिर पक क्या रहा है? या आधी रोटी कहां तक सिक गई है। वैसे तो शरद पवार के दिमाग को पढ़ पाने वाले कोई भी...

बिहार

38 | मुजरिमों पर मेहरबानी

कहते हैं राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। समय और परिस्थिति के आधार पर दोस्त और दुश्मन तय होते हैं। इसके लिए यदि विचारधारा से भी समझौता करना पड़े, तो ऐसा करने से राजनीतिक दल परहेज नहीं करते हैं। इसका ज्वलंत...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

बहुत देर करती मेहरबां आते–आते...!

शा*यर दाग देहलवी का ये शेर तो आपने सुना ही हो...*

फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते।
न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबाँ आते आते।।

ये पंक्तियां भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर सटीक बैठती हैं। दरअसल, भारत के लिए पदक जीतने वाली कुछ महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। पहले तो दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करने में देरी की, और अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। जबकि काफी दबाव के बाद उन पर पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लेकिन समझ में से नहीं आया कि आखिर मामला दर्ज करने में दिल्ली पुलिस इतनी जलालत क्यों उठाती रही? एक छोटी सी घटना पर प्राथमिकी दर्ज करने में कभी इतनी देर नहीं लगाने वाली दिल्ली पुलिस किस खिंचाई का इंतजार करती रही? जिन्होंने अपना नहीं, बल्कि देश के मान–सम्मान और गरिमा को बुलंदियों पर पहुंचाकर हमें गौरवान्वित किया, उनके प्रति इतनी लापरवाही दिखाकर दिल्ली पुलिस और कितना गिरना चाहती थी? माना कि बाहुबली भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष अपने को प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के करीबी होने की डींगे हांकते रहे हों, लेकिन उन्हें यह अधिकार किसी ने नहीं दिया कि वह महिला खिलाड़ियों का यौन शौषण जैसा घृणित अपराध करें। 5 बार भाजपा और एक बार समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके 66 वर्षीय बाहुबली की गिरफ्तारी इस समय टालने के उद्देश्य के पीछे संभवतः वर्ष 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखा जा रहा है। इसलिए कि बाहुबली का थोड़ा इशारा हुआ नहीं कि भाजपा को पूर्वांचल की कई लोकसभा सीटों पर जोर का झटका लग सकता है। नेपाल बॉर्डर से लेकर सरयू–घाघरा नदी के क्षेत्र तक बाहुबली की तूती बजती है। पचासों आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण कई बार इन्होंने जेल यात्रा भी की है, लेकिन इस चुनावी कठिन वर्ष में बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजना भाजपा के लिए परीक्षा की घड़ी है। बृजभूषण शरण सिंह का थोड़ा इतिहास समझते हैं। टाडा की वजह से 1992 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल का शूटआउट था। दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम कासकर को अरुण गवली गैंग के शूटर्स ने मार दिया था। बदले में डी–कंपनी के छोटा राजन, छोटा शकील, सुभाष सिंह ठाकुर और अन्य ने 22 सितंबर, 1992 को जेजे हॉस्पिटल शूटआउट में गवली के शूटर्स शैलेश हालदनकर और विपिन की हत्या कर दी थी। इस शूटआउट में मुंबई पुलिस के दो सिपाही भी मारे गए थे। बृजभूषण और उप्र पुलिस के एक इंस्पेक्टर वीरेंद्र राय पर आरोप लगा कि डॉन दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को ठहराने का इंतजाम इन्हीं दोनों ने कराया था। बृजभूषण टाडा के तहत जेल में बंद रहे। टाडा मामले में अभियोग लगाए जाने के बाद बृजभूषण को टिकट से वंचित कर दिया गया था, तो उनकी पत्नी केकती देवी को भाजपा ने गोंडा से मैदान में उतारा था, और वह जीत गईं। अब पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने यौन शोषण के अलावा बृजभूषण पर तानाशाही और मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। जंतर–मंतर पर धरना कर रहे पहलवानों ने कहा कि वह मेंटल टॉर्चर से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी जनवरी 2023 में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान जंतर–मंतर पर जुटे थे और अपनी बात रखी थी। उस समय खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद पहलवानों ने प्रदर्शन वापस ले लिया था। तब एक कमेटी का भी गठन किया गया था। लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी।

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 16, पृष्ठ-48, 16 से 31 मई, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

तीसरा मोर्चा तैयार

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही दल-बदल का दौर भी शुरू हो चुका है। कई नेता ऐसे हैं, जिन्हें दोनों प्रमुख पार्टियों में भाव नहीं दिया जा रहा है, तो वो तीसरे मोर्चे के साथ जुड़ने की रणनीति बना रहे हैं।

● **अभिनव तिवारी,** रीवा (म.प्र.)

ठोस कदम उठाए सरकार

प्रदेश सहित देशभर में आज भी भ्रष्टाचार अपने पैर पसारे हुए है, जिससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य सहित केंद्र सरकार को इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे जनता को काम के लिए भटकना नहीं पड़े, और उसका काम पूरा हो जाए।

● **मीनाक्षी सोनी,** ग्वालियर (म.प्र.)

मेट्रो का इंतजार

राजधानी भोपाल में मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। वहीं इंदौर अभी इस मामले में पीछे है। जल्द ही राजधानी के लोगों को मेट्रो का सफर करने को मिलेगा। हमारी राजधानी भी मेट्रो सिटी कहलाएगी। हमें मेट्रो का बेसब्री से इंतजार है।

● **अहमद खान,** भोपाल (म.प्र.)

पृथ्वी को बचाना होगा

ग्लोबल वार्मिंग इस समय पूरी दुनिया में समस्या बनी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भले ही दुनिया सतर्क होने का दावा करती हो, लेकिन अब तक इसे रोकने के दिशा में उठाए गए कदम नाकाफी ही साबित हुए हैं। यही वजह है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इससे प्रतिवर्ष लोगों को भीषण गर्मी का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हमें इसके लिए पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए, सरकार को इसके लिए कानून बनाना चाहिए। और जो नहीं मानता उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही करनी चाहिए।

● **विपिन शर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

युवाओं को सक्षम बनाने बेहतर शिक्षा आवश्यक

पिछले कुछ समय से यह विमर्श सामने आया है कि देश की युवा आबादी का सही तरीके से नियोजन किया जाए तो भारत आर्थिक तौर पर एक महाशक्ति बन सकता है। मोदी सरकार युवा आबादी के नियोजन के लिए लगातार योजनाएं भी बना रही हैं। इन योजनाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती वह शिक्षा व्यवस्था है, जो पटरी से उतरी हुई है। यह ठीक है कि मोदी सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है, पर उसके नतीजे आने में समय लगेगा। आज अधिकांश जगहों पर जिस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, उससे युवा सक्षम नहीं बन पा रहे।

● **अनिल जाटव,** रायसेन (म.प्र.)

हादसों पर लगाम कब?

सड़क हादसों में जहां लोग अपनी जान गवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी छवि खराब हो रही है। इन हादसों को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। ट्रैफिक नियमों में कई बदलाव किए गए हैं, किंतु यदि और अधिक ठोस नियम बनेंगे तो काफी हद तक हादसे रुक सकेंगे। सरकार को दोपहिया और चार पहिया वाहनों की स्पीड लिमिट तय करनी चाहिए, जिससे ओवर स्पीड में वाहन चलाने वाले पर कार्यवाही की जा सके।

● **प्रदीप ठाकुर,** इंदौर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

भाजपा को भारी पड़ेगी उम्र सीमा!

देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ऐसी एकमात्र सियासी पार्टी है जिसने 2019 में अपने नेताओं के चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा का फॉर्मूला तय करते हुए इसे अमली जामा पहनाना शुरू किया था। लेकिन क्या भाजपा अगले लोकसभा चुनाव में टिकट देने के लिए 75 साल की अधिकतम उम्र सीमा के अघोषित नियम पर अमल करेगी या इसमें कुछ लचीलापन लाया जाएगा? भाजपा के 70 साल से ज्यादा उम्र के कई बड़े नेता इस नियम पर नजर रखे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर इस नियम पर अमल हुआ तो उनकी टिकट कट जाएगी। इस उम्र के कई नेता अभी से प्रतिस्पर्धा करने में लग गए हैं। छत्तीसगढ़ में पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय के पार्टी छोड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि उनकी उम्र 77 साल हो गई है और उनको लग रहा है कि अगले चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। पार्टी परिवार के किसी सदस्य को टिकट देगी इसमें भी संशय है। आखिर कर्नाटक में केएस ईश्वरप्पा की टिकट कटी तो उनके लाख चाहने के बाद भी उनके बेटे को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। जिससे पार्टी के कई उम्रदराज नेता परेशान हैं। उनको लग रहा है कि सबकी किस्मत गुलाबचंद कटारिया जैसी नहीं हो सकती है कि 75 साल की उम्र सीमा के दायरे में आने से पहले ही राज्यपाल बना दिए जाएं।

राघव पर कसता शिकंजा

दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले में हर दिन आम आदमी पार्टी के नए-नए नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर भी गाज गिरती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली शराब नीति मामले की चार्जशीट में राघव चड्ढा का नाम भी शामिल किया गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह मनीष सिसोदिया पर ईडी और सीबीआई ने शिकंजा कसा वैसे ही चड्ढा पर भी कस सकती है। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है। चार्जशीट में बताया गया कि जाली लेन-देन की साजिश रची गई। ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि मनीष सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में राघव चड्ढा मौजूद थे। अरविंद के बयान के मुताबिक बैठक में पंजाब के आबकारी आयुक्त वरुण रूजम, मामले के आरोपी विजय नायर और पंजाब आबकारी निदेशालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। इस बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता के पति डीआर अनिल कुमार भी मौजूद थे, इनका नाम इस चार्जशीट में सामने आया है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि के कविता, सरथ चंद्र रेड्डी, अरुण पिल्लाई और समीर महेंद्रू के साथ दिल्ली में शराब कारोबार पर चर्चा को लेकर एक बैठक हुई थी।

कोपभवन में केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों पूरी तरह से खामोश हो गए हैं। जबसे उनके सरकारी आवास की साज-सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च करने की खबर आई तब से वे चुप हो गए हैं। वे एक दिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं से मिलने जरूर गए थे। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों से दूर ही रह रहे हैं। यहां तक कि कर्नाटक चुनाव में प्रचार के लिए भी नहीं गए। एक समय वह भी था जब केजरीवाल और भगवंत मान एक साथ गुजरात में रैलियां कर रहे थे। इसी तरह अपने बंगले को लेकर चल रही कहानियों या उससे जुड़े रिकॉर्ड जब्त करने के उपराज्यपाल के आदेश या हर बार सुनवाई में मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने जैसे मसले पर भी वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। उल्टे उनके पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे अपने को आम आदमी बताकर सादगी से रहने की कसमें खा रहे हैं। उनका एक ट्वीट वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में 10 एसी लगे होने पर सवाल उठाया था और हैरानी जताई थी कि कोई कैसे इतने आलीशान घर में रह सकता है। अब उनके घर की साज-सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च होने के दस्तावेज सामने आ गए हैं।

एनडीए में कुशवाहा की वापसी!

बिहार विधानसभा का चुनाव अभी बहुत दूर है लेकिन राज्य की सियासत अभी से सुलगने लगी है। जेडीयू से अगल होकर नई पार्टी बनाने वाले आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे। कुशवाहा के साथ बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। इस सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही कुशवाहा की वापसी एनडीए में हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से अलग होने के बाद से ही यह कहा जाने लगा था कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का भाजपा के साथ गठबंधन हो सकता है, हालांकि न तो भाजपा और न ही कुशवाहा की तरफ से अब तक गठबंधन को लेकर स्पष्ट तौर पर कोई बात कही गई है। मगर पिछले दिनों कुशवाहा अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों का बाजार गर्म हो गया है।

अभिनेता से नेता बनेंगे सोनू सूद!

फिल्म अभिनेता सोनू सूद फिल्मों के अलावा अपनी दरियादिली के लिए भी जाने जाते हैं। अगर कोई उनसे मदद मांगता है तो फिर वह उसकी मदद जरूर करते हैं। कोरोनाकाल में सोनू सूद ने सबसे ज्यादा लोगों की मदद की थी। ऐसे में अटकलें लगती रहती हैं कि सोनू सूद क्या राजनीति में भी एंट्री करेंगे, जिस पर उन्होंने इंदौर में एक बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद चर्चा जोरों पर है कि सोनू सूद अब फिल्मी दुनिया के अलावा राजनीतिक दुनिया में नजर आ सकते हैं, क्योंकि सोनू सूद ने खुद राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की है। इंदौर में सोनू ने कहा- राजनीति भी बहुत कमाल की दुनिया है, राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखता लेकिन ऐसी चीजें हो जाती हैं कि शायद मुझे राजनीति में आना चाहिए। इंदौर दौरे पर पहुंचे सोनू सूद ने कहा कि इस दुनिया में वैसे तो राजनीति के बिना भी अच्छे काम किए जा सकते हैं, लेकिन हालात कभी ऐसे बन जाते हैं कि आपको राजनीति में आना पड़ता है।

...और बच गए साहब

कभी-कभी किसी व्यक्ति की कोई टिप्पणी ऐसी हो जाती है कि उसकी साख पर बन आती है। ऐसी ही एक विवादास्पद टिप्पणी प्रदेश के एक सबसे कमाऊ विभाग के बड़े साहब ने गत दिनों कर दी थी, जिससे साहब राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के निशाने पर आ गए थे। साहब को फंसता देख प्रशासनिक मुखिया ने मोर्चा संभाला और उन्हें छुट्टी पर चले जाने का सुझाव दिया। इसके पीछे प्रशासनिक मुखिया की मंशा यह थी कि अगर उक्त अधिकारी छुट्टी पर चले जाते हैं तो मामला धीरे-धीरे शांत हो जाएगा और उनके ऊपर आंच नहीं आ पाएगी। बताया जाता है कि प्रशासनिक मुखिया का सुझाव मानने से पहले साहब ने उनसे गुहार लगाई कि इससे अच्छा होता कि आप मुझे दिल्ली ही भेज दो। साहब की मंशा को भांपते हुए प्रशासनिक मुखिया ने भी काफी मंथन किया जबकि उक्त अधिकारी कई बार दिल्ली जाने का निवेदन कर चुके हैं। इस बार दांव उनका दबाव में चल गया और साहब ताबड़तोड़ में दिल्ली की तरफ कूच कर गए और उन्हें महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदारी से भी नवाज दिया गया। यहां यह बता दें कि साहब इसके पहले भी अपने मातहतों से विचार नहीं मिलने के कारण लिखा-पढ़ी कर चुके हैं। साफ सुथरी छवि वाले आईएएस अफसर इन दिनों किसी बीमारी से भी जूझ रहे हैं। इसलिए उनका दिल्ली जाना और महत्वपूर्ण हो गया था।

एक्सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं जाऊंगा मैं...

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में 1999 बैच के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन दिनों चर्चा में हैं। इसकी वजह यह है कि साहब अपनी मनपसंद जगह पर ही रहना चाहते हैं। मप्र के औद्योगिक संभाग की कमान संभालने वाले इन साहब ने कमर कस ली है कि अब वो या तो वहीं रहेंगे, या फिर देश की राजधानी में चले जाएंगे। साहब वैसे भी देश की राजधानी से आए थे। वैसे तो वह मप्र कैडर के आईएएस अफसर हैं, परंतु उनकी आधी नौकरी दिल्ली में ही बीती है। क्योंकि साहब दिल्ली में ही पढ़े-लिखे हैं और सत्तारूढ़ दल से ही दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका तबादला चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की राजधानी में होने जा रहा है। ऐसे में साहब अपनी मर्जी की नौकरी करना चाहते हैं और उनका मन फिर दिल्ली की तरफ हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि अभी तक अपने मन का काम करने वाले साहब को यह लगता है कि अगर वे राजधानी में चले गए तो उन्हें सत्ता और संगठन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसलिए साहब बिना लाग-लपेट के इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उन्हें या तो औद्योगिक संभाग में ही रखा जाए या फिर राष्ट्रीय राजधानी के लिए रिलीफ कर दिया जाए। अब देखना यह है कि साहब की मंशा इस बार दिल्ली वाले पूरी करते हैं या नहीं।

इंतेहा हो गई इंतजार की

शीर्षक की ही तरह हाल ही की डीपीसी में डीएसपी से एडिशनल एसपी बने अफसरों की स्थिति हो गई है। पुलिस विभाग में एक तो वर्षों बाद डीएसपी की डीपीसी हुई है। इस डीपीसी में जिन लोगों को एडिशनल एसपी बनने का मौका मिला है, उनको ये सौगात कब मिलेगी इसका अभी कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। वैसे भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित प्रमुख कार्यों को अंजाम देने वाला पुलिस विभाग हमेशा ही उपेक्षित रहता है। इस विभाग में अन्य विभागों की अपेक्षा हर काम मुश्किल से होता है। इसी तरह लंबे इंतजार के बाद डीएसपी के एडिशनल एसपी के लिए डीपीसी हो पाई थी। डीपीसी होने के बाद अफसरों को उम्मीद थी कि जल्द ही उन्हें एडिशनल एसपी के तौर पर पदस्थापना मिल जाएगी। लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कोई आदेश ही नहीं निकला है। एक-एक दिन गिनते-गिनते अफसरों के रात-दिन कट रहे हैं। पदस्थापना में हो रहे विलंब से अधिकारी परेशान हो रहे हैं। कभी-कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि पुलिस विभाग का कोई माई-बाप ही नहीं है। अगर यह कहा जाए कि पुलिस विभाग के मुखिया की तनिक भी नहीं चल रही है, तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। अगर पुलिस विभाग के मुखिया की चलती तो अफसर डीएसपी से एडिशनल एसपी बनने वाले अफसरों की पदस्थापना हो गई होती। क्योंकि पुलिस विभाग के मुखिया को मालूम है कि उनके विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री के निर्णयों से हमेशा ही नाखुश रहते हैं, जिसका खामियाजा विभागीय अधिकारियों को भोगना पड़ता है।

नहीं बनी बात

1991 बैच के एक आईएएस अधिकारी ने कोल इंडिया में ज्वाइनिंग के लिए खूब हाथ-पांव मारे लेकिन साहब की बात नहीं बन पाई। जबकि साहब को उम्मीद थी कि उनकी मनमानी वाला यह विभाग उन्हें जरूर मिल जाएगा। गौरतलब है कि साहब सरकार के नाक-कान माने जाते थे। उन्हें सरकार के सबसे पसंदीदा और करीबी अफसरों में गिना जाता था। साहब का जुगाड़ ऐसा था कि पूर्ववर्ती सरकार में भी उनकी खूब धाक थी। लेकिन वर्तमान में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। हालांकि साहब के पास वर्तमान में भी प्रमुख सचिव का पद है, लेकिन पहले वाली दमदारी नहीं बची है। साहब को उम्मीद थी कि अभी भी उनकी पुरानी वाली साख बरकरार होगी, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार के अंडर में आने वाले एक इस विभाग में महत्वपूर्ण कुर्सी पाने के लिए अप्लाई किया था। लेकिन साहब की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। यहां बता दें कि साहब बिहार के मूल निवासी हैं। अब साहब इस खोजबीन में लग गए हैं कि आखिरकार उन्हें इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल पाई है।

चर्चा में अपर आयुक्त

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों नगर निगम के अपर आयुक्त काफी चर्चा में हैं। दरअसल, साहब विंध्य क्षेत्र के अपने गृह जिले के वन क्षेत्र में एक रिसोर्ट बनवा रहे हैं। बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र में बन रहे रिसोर्ट की भव्यता देखकर हर कोई साहब की कमाई का अंदाजा लगा रहा है। यहां बता दें कि साहब अर्जुन सिंह सेवा से भर्ती हुए थे। इसमें से अब एक-आधा ही अफसर बचा हुआ है, जिनमें से साहब भी हैं। साहब ने नगर निगम सेवा में जमकर चांदी काटी है। वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनकी बीसों उंगलियां घी में हैं। अपनी अब तक जमापूंजी को साहब जंगल में मंगल मनाने वालों के लिए खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि साहब का रिसोर्ट जिस क्षेत्र में बन रहा है वह क्षेत्र बाघों के संरक्षण के रूप में आरक्षित है। इस क्षेत्र में रिसोर्ट की अनुमति मिलना भी साहब के रसूख को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपने कई चहेते लोगों को डायरेक्ट नगर पालिका अधिकारी में भर्ती कर दिया था। साहब को क्या पता था कि यह इस सेवा में रहकर इस तरीके के गुल खिलाएंगे।

पहली बार देख रहा हूं कि कोई अपनी ही पार्टी के सांसदों और विधायकों की आलोचना कर रहा है। भाजपा नेताओं की तारीफ और कांग्रेस नेताओं का अपमान मेरी समझ से बाहर है। यह पूरी तरह गलत है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है।

● **सचिन पायलट**

मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कई राज्य सरकारें और राजनीतिक पार्टियां फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध क्यों कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को पहले ही हरी झंडी दिखा दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहां तक कि केरल में भी फिल्म चल रही है, मप्र और मप्र सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री तक कर दिया है। फिल्म का विरोध कर नाहक विवाद बढ़ाया जा रहा है।

● **विपुल शाह**

आज मैंने भारत के लिए एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मैडल जीता है, इससे मैं काफी खुश हूं, लेकिन मणिपुर में जो दंगे हुए हैं, उससे मैं काफी दुखी हूं। हमारे गांव में कुकी समुदाय और हम सब मिलकर रहते हैं, कभी पता ही नहीं चला कि वे शेड्यूल ट्राइब के हैं। मैं चाहती हूं कि वहां फिर से शांति लौट आए।

● **बिंदियारानी देवी**

अकेला ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है। ये मात्र वो पड़ोसी नहीं है, जो आपको परेशान करता है, बल्कि वो तो इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान समझता है। ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जो पूरे विश्व के लिए घातक है।

● **बेंजामिन नेतन्याहू**

रणबीर एक शांत स्वभाव वाले इंसान हैं, उनके पास संत जैसा दिमाग और मन है। मुझे उनकी इस खासियत से शिकायत होती है। वहीं दूसरी तरफ मैं बात-बात पर गुस्से में आ जाती हूं। हालांकि रणबीर को यह बात बिलकुल पसंद नहीं आती है। वे लगातार कोशिश करते रहते हैं कि मैं गुस्सा न करूं। उनकी सलाह पर मैं भी गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूं। इन सबके बावजूद हम दोनों की जिंदगी खुशहाल और मजे में गुजर रही है। दोनों एक-दूसरे के पूरक बनकर काम करते हैं। मेरी लोगों को सलाह है कि वे भी इसी तरह मिलजुलकर परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ाएं।

● **आलिया भट्ट**

वाक्युद्ध

कांग्रेस की लगातार कोशिश रही है कि भारत में हिंदू समुदाय उपेक्षित रहे। इसीलिए कभी भगवान राम को कैद करके रखा और अब बजरंग बली पर भी पहरा बैठाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने दिखा दिया कि उसकी नजर में हिंदू भारत में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इसे हम कैसे बर्दाश्त करें।

● **संबित पात्रा**

बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है, यह भाजपा ने दर्शा दिया है। बेवजह का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताने का षड्यंत्र किया जा रहा है। जबकि यह पूरा देश जानता है कि भाजपा धर्म की राजनीति कर अपनी रोटियां सेंकती रहती है। अब इसी कड़ी में भगवान हनुमान को मुद्दा बनाया जा रहा है।

● **रणदीप सुरजेवाला**

अब दिल्ली दूर नहीं...

चुनावी साल में प्रशासनिक अफसरों की एक बड़ी सर्जरी होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि शासन और प्रशासन के मुखिया ने यह सूची तैयार कर ली है। सूची को विधानसभा चुनाव में जमावट के अनुसार तैयार किया गया है। बताया जाता है कि उस सूची में तीन-चार संभाग के कमिश्नर और कलेक्टर का भी नाम शामिल है, जिनका तबादला किया जाना जरूरी है। इन अफसरों के अलावा कुछ विभागों के प्रमुख सचिवों का तबादला होना भी निश्चित है। इन अफसरों में से एक हैं प्रमुख सचिव पल्लवी जैन। वे दिल्ली जाने के लिए बोरिया-बिस्तर बांधकर तैयार बैठी हैं। बस इंतजार कर रही हैं कि कब दिल्ली से कागज आए और वे मप्र से रवानगी डालें। यह तो निश्चित है कि मैडम का

दिल्ली जाना सुनिश्चित है, क्योंकि उनके पति और आईएएस अधिकारी अरुण गोविल कुछ माह पहले ही दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। उक्त दंपत्ति पहले भी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में रह चुके हैं और वहीं पढ़े-लिखे भी हैं। उन्हें दिल्ली सुहाता है। हालांकि मैडम तो दिल्ली जाने के लिए बहुत पहले ही आवेदन कर चुकी हैं। उक्त अधिकारी बेहद ईमानदार और साफ-सुथरी छवि के अधिकारी हैं।

● **कुमार विनोद**

आखिर क्या गलती हो गई?

प्रदेश की एक तेजतर्रार महिला आईएएस अधिकारी का दिल्ली प्रेम सभी जानते हैं। मैडम सालों से केंद्र सरकार के प्रमुख विभागों में काम कर रही हैं। अभी हाल ही में वे देश के सबसे उल्लेखनीय और प्रमुख विभाग में सचिव के पद पर पदस्थ थीं। लेकिन बताया जाता है कि विभागीय मंत्री के सामने उनकी एक गलती उजागर हुई और उन्हें रातोंरात विभाग से चलता कर दिया गया। ये आईएएस अधिकारी हैं। 1990 बैच की अलका उपाध्याय। मैडम भारत सरकार में सचिव सड़क परिवहन विभाग का जिम्मा बखूबी से निभाने वाली मैडम को गडकरी जी ने अपने विभाग से चलता कर दिया। क्या कारण है कि मैडम को रातोंरात उक्त जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए लूपलाइन में पटक दिया। जानकारों का कहना है कि कोई बड़ी गलती ट्रांसपोर्ट विभाग में हो गई है, जो नितिन गडकरी को बर्दाश्त नहीं हुई। गौरतलब है कि पिछले 8 सालों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है, उसमें सबसे अधिक सड़क परिवहन विभाग का ही काम दिख रहा है। आज पूरे देशभर में सड़कों का मजबूत और बेहतरीन जाल बिछा है। उसमें इस विभाग के अफसरों की बड़ी भूमिका रही है। खुद विभाग के मंत्री नितिन गडकरी एक-एक योजना और परियोजना की लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में विभाग में छोटी सी गलती भी सामने आ जाती है, जिसे मंत्री गंभीरता से लेते हैं।

नई जिम्मेदारी क्यों नहीं संभाल रहे साहब?

मप्र के सबसे तेजतर्रार और योग्य आईएएस अफसरों में शुमार 1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को हाल ही में सचिव सड़क परिवहन विभाग बनाया गया है। लेकिन अभी तक उन्होंने नए विभाग में जिम्मेदारी नहीं संभाली है। इससे मप्र सहित दिल्ली की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में कयासों का दौर शुरू हो गया है। उनके पदभार ग्रहण करने में हो रही देरी को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल, वे लगातार छुट्टी पर चल रहे हैं। हालांकि उनका मप्र आना दूर की बात है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जैन नए विभाग में ज्वाइनिंग से क्यों कतरा रहे हैं। गौरतलब है कि खुद प्रधानमंत्री उन्हें नाम से जानते हैं। जानकारों का कहना है कि जैन फाइनेंस सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। शायद इसलिए वे नई पदस्थापना में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं। गौरतलब है कि अनुराग जैन अभी तक उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव के रूप में कार्यरत थे।

आखिर क्या कमी है महिला आईएएस अफसरों में?

एक ही तरह की शिक्षा, एक ही तरह की परीक्षा, एक ही तरह की ट्रेनिंग होने के बाद भी महिला आईएएस अफसरों को कमतर आंकने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जबकि महिला अफसरों ने कई बार अपनी प्रशासनिक क्षमता को शासन-प्रशासन को दिखा दिया है। उसके बाद भी विडंबना यह है कि प्रदेश के महानगरों भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में कभी महिला आईएएस अधिकारियों को कलेक्टर की जवाबदारी नहीं दी गई है। हालांकि जबलपुर में एक बार छवि भारद्वाज को कलेक्टर बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने बेहतर प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन भी किया था। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कई महिला आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन भी किया है। लेकिन सरकार ने हमेशा ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में महिला अफसरों को कलेक्टर बनाने में परहेज किया है।

मप्र में गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए भाजपा की त्रिमूर्ति यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने फुलप्रूफ प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि 51 फीसदी वोट के साथ 200 सीटें जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे आसानी से पा लिया जाएगा। इस प्लान को 3-एस फॉर्मूला नाम दिया गया है। यानी सरकार, संगठन और संघ तीनों एकसाथ मिलकर चुनावी मोर्चे पर काम करेंगे।

जीत का बना फुलप्रूफ प्लान

मप्र में 5 महीने बाद चुनावी मैदान में घमासान शुरू हो जाएगा। इस घमासान में उतरने से पहले भाजपा की पूरी कोशिश है कि वह एक ऐसी रणनीति के साथ काम में जुटे जिससे आसानी से जीत मिल सके। इसके लिए भाजपा ने 3-एस का फॉर्मूला तैयार किया है। यानी इस बार सरकार, संगठन और संघ तीनों मिलकर मिशन 200 को पूरा करेंगे। इसके लिए तीनों एक संयुक्त रणनीति बनाकर काम करेंगे। इससे पार्टी को उम्मीद है कि इस बार मप्र में भाजपा गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत प्राप्त करेगी।

दरअसल, 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए अपने गढ़ को सुरक्षित रखने के लिए सरकार, संगठन के साथ अब संघ भी पूरी तरह से चुनावी मैदान मे आ डटा है। वहीं चुनाव से पहले भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए सरकार की ओर से इन दिनों निगम मंडलों से लेकर बोर्ड में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। इसके साथ ही जिलों के प्राधिकरणों में भी भाजपा नेताओं को एडजस्ट किया जा रहा है। जिसमें चुनाव में नेताओं की दावेदारी को कम किया जा सके। चुनाव में भितरघात और कार्यकर्ताओं के नाराजगी से होने वाले डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए उन्हें पदों पर नवाजा जा रहा है।

प्रदेश में करीब 18 साल से भाजपा की सरकार है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन 15 माह बाद ही उसकी सरकार गिर गई। इसके बाद से फिर भाजपा सत्ता में है। पार्टी के लोगों का मानना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। सत्ता पर अफसरशाही हावी है। सरकार की तरफ से निकाली गई विकास यात्रा को कई जगह लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं सड़क नहीं तो कहीं पानी नहीं होने को लेकर लोगों में नाराजगी है। भाजपा के सर्वे में कई पुराने नेता और कार्यकर्ताओं के भी नाराज होने की बात सामने आई है। इसके लिए भाजपा ने 14 नेताओं को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कारण जानने और फीडबैक लेने के लिए सर्वे कराया था। कई पुराने नेताओं की पूछ परख नहीं हो रही है। अब उनको अपनी अगली पीढ़ी के रास्ते भी पार्टी में बंद दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते नेता बगावती हो गए हैं। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं।

नागपुर के बाद संघ का मप्र में बड़ा आधार है। इसलिए संघ यहां सत्ता गंवाना नहीं चाहता है। यहां हर जिले में शाखाएं लग रही हैं। संघ चाहता है कि उसका विस्तार इसी तरह जारी रहे। इसके लिए प्रदेश में भाजपा सरकार जरूरी है। इसलिए 2018 की गलती को संघ और भाजपा दोहराना नहीं चाहते। गौरतलब है कि मप्र संघ और भाजपा की प्रयोगभूमि है। इसलिए संघ की लगातार कोशिश रहती है कि मप्र में भाजपा हमेशा मजबूत स्थिति में रहे। इसके लिए शाखा कार्य विस्तार के अलावा संघ आदिवासियों के बीच डीलिस्टिंग आंदोलन, जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ाने के लिए शिवगंगा जैसे अभियान, आदिवासियों को धार्मिक और सामाजिक, सांस्कृतिक पर्वों से जोड़ने का अभियान, आदिवासी युवाओं को रोजगार तथा उनकी शारीरिक क्षमता को देखते हुए क्रीडा इत्यादि गतिविधियों से युवाओं को जोड़ने का अभियान भी संघ चला रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यद्यपि राजनीति में हिस्सा नहीं लेता लेकिन उसकी गतिविधियों और उसके अभियानों का लाभ भाजपा को मिलता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मप्र का लगातार प्रवास कर रहे हैं। उनके अलावा पिछले दिनों भैयाजी जोशी भी मप्र में सक्रिय दिखे। भैयाजी जोशी के अलावा मौजूदा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, और सह सरकार्यवाह अरुण कुमार भी मप्र के दौरे करते रहते हैं। जबकि एक अन्य सह

संघ ने संभाली चुनावी कमान

मप्र में पांचवी बार भाजपा को सत्ता में लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनावी कमान संभाल ली है। पिछले दिनों इंदौर में हुई संघ की समन्वय बैठक में चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद सहित संघ के अनुषांगिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। संघ की इस बैठक में सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करने के साथ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश तय किए गए। संघ मप्र चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लगातार मप्र आ रहे हैं। अप्रैल महीने में दो बार संघ प्रमुख मप्र का दौरा कर चुके हैं। वहीं मार्च के आखिर में भी संघ प्रमुख मोहन भागवत एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे थे। विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता और अलग-अलग अंचलों में कार्यक्रम में शामिल होने को संघ की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

सरकार्यवाह डॉ. मनमोहन वैद्य का मुख्यालय समिधा कार्यालय यहां है इस कारण से मप्र की गतिविधियों को डॉ. मनमोहन वैद्य मॉनीटर करते हैं। इसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत लगातार मप्र का दौरा करते रहते हैं। वहीं उन्होंने संघ के सभी पदाधिकारियों को मप्र में कार्यक्रम बनाकर काम करने का निर्देश दे रखा है। यही कारण है कि यहां सालभर संघ की गतिविधियां चलती रहती हैं। वहीं संघ के पदाधिकारी हर पखवाड़े संघ प्रमुख को रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं। जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना बनाई जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मैदान में डटे हुए हैं और चुनाव में गेमचेंजर के तौर पर देखी जा रही लाड़ली बहना योजना में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। मुख्यमंत्री का पूरा फोकस लाड़ली बहना योजना के लिए प्रदेश में 48 फीसदी महिला वोटरों को साधना है। गौरतलब है कि जनवरी में मप्र चुनाव आयोग ने जो नई वोटर लिस्ट जारी की उसमें नए वोटरों में महिलाओं ने नए नाम जोड़े हैं।

वहीं प्रदेश के 52 जिलों में 41 जिले ऐसे हैं जहां पर महिला वोटरों के नाम ज्यादा जुड़े हैं। प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या 7.07 लाख बढ़ी है जबकि नए पुरुष मतदाताओं की संख्या 6.32 लाख बढ़ी है। वहीं प्रदेश चुनाव में युवाओं वोटरों की बड़ी भूमिका होने जा रही है। युवा वोटर की ताकत को इससे समझा जा सकता कि प्रदेश में 18 से 21 साल के वोटरों की संख्या 30 लाख है। वहीं प्रदेश में 18 से 39 साल के उम्र के युवाओं की संख्या 2.83 करोड़ है जो कि प्रदेश के कुल मतदाताओं की संख्या का 52 फीसदी है। चुनाव में युवा वोटरों की इस बड़ी संख्या को साधने के लिए सरकार रोजगार देने पर खासा फोकस कर रही है। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के लिए 1 लाख 24 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। वहीं युवाओं को खुद का रोजगार लगाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना बनाई गई है। वहीं युवाओं को साधने के लिए पिछले दिनों सरकार ने युवा

नीति लाकर कई नए ऐलान किए हैं। वहीं सरकार मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना जून से प्रदेश में लॉन्च करने जा रही है। जिसमें युवाओं को ट्रैनिंग के दौरान हर महीने 8 हजार रुपए दिए जाएंगे। योजना के लिए एक जून से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और एक जुलाई से पैसा मिलने का दावा किया जा रहा है।

चुनाव से पहले भाजपा जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। गत दिनों प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई बड़ी बैठक में प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद पूरे देश की नजर मप्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना पर रहेगी। इसलिए चुनाव की दृष्टि से हम तैयारियों में जुटे हैं। बूथ को मजबूत करने के लिए भाजपा संगठन ने 4 से 14 मई तक पूरे प्रदेश में बूथ विजय संकल्प अभियान चलाया। जिसमें प्रत्येक विधानसभा में 10 बूथों पर एक कलस्टर का गठन किया गया और कलस्टर के सभी कार्यकर्ता अभियान के दौरान आयोजित होने वाले खेल, वैचारिक और पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसमें जिला, विधानसभा, मंडल और नीचे स्तर तक संचालन समितियां भी बनेंगी। हर बूथ से 10 लोग इसमें शामिल होंगे। गौरतलब है कि 51 प्रतिशत वोट शेयर के साथ अजय होने का संकल्प लेकर भाजपा ने 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। मप्र में पार्टी ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशती वर्ष में बूथ विस्तारक योजना तैयार की थी। इसके तहत बूथ स्तर पर काम की निगरानी और संदेश आदि पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया गया। इतना ही नहीं, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जानकारी, उनसे जुड़े डेटा का डिजिटलाइजेशन भी किया गया। इसके अच्छे परिणाम देखकर पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर इसके प्रशिक्षण की योजना बना रही है। इसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सहित पन्ना प्रभारियों तक की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। इसके तहत केंद्र एवं प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर भाजपा के पक्ष में अभी से माहौल बनाने की तैयारी है। पार्टी ने स्मार्ट बूथ पर जो काम शुरू किया है, उसके अनुसार अब बूथ स्तर के कार्यकर्ता को भी नई पहचान मिल सकेगी। पार्टी प्रदेश के 65 हजार बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बूथ एजेंट को पार्टी संगठन में विशेष तवज्जो देने जा रही है। भाजपा पिछले कुछ वर्षों में वृहद स्तर पर सदस्यता अभियानों के बाद खुद को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताती आ रही है। इसका श्रेय किसी बड़े चेहरे या पदाधिकारियों के बजाय लाखों कार्यकर्ताओं को दिया जाता है, लेकिन उन्हें अलग से विशेष पहचान की कमी महसूस होती रही है। बूथ के तीन पदाधिकारियों अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, जिन्हें संगठन में त्रिदेव की संज्ञा दी गई है, उन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। इस पर यूनिक नंबर के साथ कार्ड पर उनका पूरा परिचय होगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

एक-एक बिंदु पर मंथन

केंद्र व मप्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए 2023 और 2024 चुनौतीपूर्ण हैं। हालांकि, भाजपा पूरी तरह आशान्वित है कि दोनों चुनाव में पार्टी आसानी से जीत प्राप्त कर लेगी। लेकिन मातृसंस्था संघ चुनावी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए संघ ने मप्र में भाजपा को गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत दिलाने के लिए अपने सभी अनुषांगिक संगठनों को चुनावी मोर्चे पर सक्रिय कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि संघ के बड़े पदाधिकारी खुद चुनावी तैयारियों की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। राजधानी भोपाल स्थित मध्य क्षेत्र के मुख्यालय समिधा से भाजपा के चुनाव अभियान की मॉनीटरिंग हो रही है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने 51 फीसदी वोट के साथ 200 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है उसे अमलीजामा पहनाने के लिए संघ के अनुषांगिक संगठन और स्वयंसेवकों ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। वहीं संघ के दिशा-निर्देश पर सत्ता और संगठन लगातार चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एक-एक बिंदु पर मंथन कर रणनीति बना रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित करा रहे हैं।

मप्र के अफसरों को लुभा रही सियासत

मप्र के अफसर राजनीति में किस्मत आजमाना चाहते हैं। छतरपुर के लवकुशनगर की एसडीएम निशा बांगरे के बाद अब आईपीएस अधिकारी पवन जैन के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जैन की नजर राजस्थान के राजखेड़ा सीट पर है। ऐसी चर्चा है कि वे चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी पवन जैन राजस्थान के धौलपुर की राजखेड़ा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उन्होंने भाजपा से टिकट की दावेदारी की है। पार्टी ने कहा तो वे वीआरएस लेने के लिए भी तैयार हैं। जानकारी के अनुसार पवन जैन लंबे समय से भाजपा के बड़े नेताओं के करीबी हैं। प्रदेश में करीब दो दर्जन सीटें ऐसी हैं, जहां पर इस बार पूर्व नौकरशाह भाजपा व कांग्रेस के लिए चुनौती देने की तैयारी में लगे हुए हैं। यह नौकरशाह पहले तो इन दोनों ही दलों से प्रत्याशी बनना चाहते हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिला वे अन्य दलों से भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में गुपचुप लगे हुए हैं। ऐसे में यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार सत्ता बचाने को बेकरार भाजपा और सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली कांग्रेस इन्हें कितनी तवज्जो देती है। इन नौकरशाहों में डिप्टी कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर और रिटायर्ड आईपीएस तक शामिल हैं।

चुनाव में उतरने के लिए इन नौकरशाहों की अपनी अलग-अलग रणनीति है। कुछ पद पर रहते हुए राजनीतिक दलों से बनाए गए संबंधों का उपयोग अपने टिकट पाने के लिए कर रहे हैं तो कुछ जातिगत और सामाजिक संगठनों की गतिविधियों में सक्रिय होकर टिकट पाने के लिए जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की राजनीति की बात करें तो पहले भी कई ब्यूरोक्रेट्स चुनाव लड़कर विधायक ही नहीं बल्कि मंत्री तक बन चुके हैं। कुछ अभी भी सक्रिय हैं। मुरैना सीट से राकेश सिंह भाजपा की ओर से टिकट मांग रहे हैं। उनके पिता आईपीएस रहे और प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे। पिता के बड़े कद और नाम के सहारे राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसी ही एक महिला अधिकारी भी अब नौकरी छोड़कर राजनीति में आने को आतुर हैं। यह हैं छतरपुर में पदस्थ एसडीएम निशा बांगरे। वे वैसे तो बालाघाट की रहने वाली हैं। उनके पिता रविंद्र बांगरे एजुकेशन विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। चुनाव में उतरने के लिए निशा द्वारा आमला में मकान भी बनाया जा चुका है। वे यहां पर मतदाता भी बन चुकी हैं। वे पूर्व में बैतूल जिले में साढ़े तीन साल तक एसडीएम रह चुकी हैं। इसकी वजह से उनके द्वारा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर चुनाव भी कराया जा चुका है। इसके बाद से ही वे इलाके में लोगों से मेलजोल बढ़ाने के साथ ही सामाजिक स्तर पर भी सक्रिय बनी हुई हैं। हालांकि वे अभी इसे छिपा रही हैं कि किस पार्टी से चुनाव में उतरेंगी। उनका कहना है कि अभी इसका खुलासा करना सर्विस नियमों के खिलाफ होगा, लेकिन चुनाव लड़ सकती हूं। मेरे पास प्रशासनिक अनुभव है। पॉलिसी लेवल पर मैं बेहतर कर सकती हूं।

मंडला आरडी कॉलेज में हिंदी साहित्य के प्रोफेसर के पद से इस्तीफा देकर 2008 में कांग्रेस में शामिल हुए प्रो. संजीव छोटेलाल उईके 2013 में मंडला सीट से विधायक भी रह चुके हैं। उनके पिता भी 1980 से मंडला से सांसद और दो बार के विधायक रहे हैं। 2004 में कांग्रेस की रैली में जाते समय उदयपुरा के पास एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। वे छात्र राजनीति में यूथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। उनकी रामनगर में राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। उनका कहना है कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह और पिता के अधूरे कार्य और अपने निजी व पारिवारिक हितों को परे रखकर राजनीति में सक्रिय हुए हैं। इसी तरह से सारंगपुर क्षेत्र के रहने वाले महेश मालवीय राजगढ़ में ग्राम सेवक थे। अक्टूबर 2018 में इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए। पिछली बार पत्नी कला मालवीय को सारंगपुर से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा चुके हैं। इस बार खुद दावेदारी कर रहे हैं। कबीर भजन गायक के तौर पर उनकी क्षेत्र में पहचान हैं। वे कहते हैं कि मैं जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आया हूं।

इसी तरह से मंडला जिले के बम्हनी निवासी आईपीएस एनपी वरकडे अप्रैल 2018 में डीआईजी रीवा के पद से रिटायर हुए तो वे कांग्रेस में शामिल हो गए। दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडला-डिंडौरी की आठों विधानसभा सीटों से उनका और गुलाब सिंह उईके का नाम भी पैनल में था, लेकिन टिकट कमल मरावी को मिला था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें आगे ध्यान रखने की बात कही थी। उनका कहना है कि कुछ होता इससे पहले ही सरकार गिर गई। जिसके बाद से ही मैं मंडला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। बता दें, इससे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस बने वरदमूर्ति मिश्रा ने वीआरएस लेकर अपनी पार्टी बनाई है। वास्तविक भारत पार्टी नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। मिश्रा ने 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है।

● **सुनील सिंह**

इस्तीफा देकर बने भाजपाई

मंडला जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉ. मुकेश तिलगाम भी दो साल पहले इस्तीफा देकर भाजपाई बन चुके हैं। अब वे मंडला में खुद का नर्सिंग होम चलाते हैं। उनके द्वारा बीते माह ही भोपाल में शिवराज सिंह चौहान के सामने पार्टी की सदस्यता ली गई है। इसके बाद से वे लगातार मैदानी स्तर पर चुनावी तैयारियों के तहत सक्रिय हो चुके हैं। इसी तरह से डिंडौरी जिला अस्पताल में पदस्थ डॉ. देवेंद्र सिंह मरकाम एमपीपीएससी के सदस्य बनाए जा चुके हैं। वे संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे इसी साल रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट के बाद भाजपा में शामिल होकर जिले की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैंने सार्वजनिक जीवन में लोगों की सेवा की, रिटायरमेंट के बाद भी इसी मंशा से राजनीति में शामिल होना है। इसी तरह से बैतूल जिले के भैंसदेही निवासी हेमराज बारस्कर अभी इटारसी में जीएसटी ऑफिसर हैं। वे छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़े रहे। पिता गेंदू बारस्कर और भाई मनीष बारस्कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वास्ता रखते हैं। उनके पिता की अध्यक्षता में बैतूल में हुए बड़े हिंदू सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो चुके हैं। वे बीते दो चुनाव से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। इसी तरह से छिंदवाड़ा की पांडुर्णा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले डॉ. प्रकाश उईके अभी दमोह में मजिस्ट्रेट हैं। वे लगातार आदिवासी इलाके में सक्रिय बने हुए हैं। उनकी संघ और जनजातियों के बीच अच्छी पकड़ है। वे निशुल्क कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। जनजातीय विषय, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर वे काम कर रहे हैं।

जल्द खुलेगी पदोन्नति की राह

चुनावी साल में सरकार प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति की सौगात देने जा रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर पदोन्नति शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जून से सितंबर के बीच पदोन्नति शुरू कर देगी। सरकार ऐसा करके विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों की नाराजगी दूर करेगी। हालांकि, पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। यानी न्यायालय का जो निर्णय रहेगा, अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वीकार होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में 7 साल से पदोन्नति पर रोक है। पिछले 7 साल में प्रदेश में करीब 70 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से करीब 39 हजार कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति मिलनी थी। हर साल 5 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यह कसक है कि वे जिस पद का अधिकार रखते हैं, वह नहीं बन पाए हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के दूसरे विकल्प के रूप में वरिष्ठ पद का प्रभार देना शुरू किया है। पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को 8 माह पहले यह लाभ दिया जा चुका है। अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रभार दिया जा रहा है, पर अधिकारी और कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि प्रभार देना अलग बात है और पदोन्नति अलग। वरिष्ठ प्रभार मिलने से पैसा तो मिल जाएगा, पर वह प्रतिष्ठा (हैसियत) नहीं मिलेगी। सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक से कर्मचारियों में भारी निराशा और असंतोष व्याप्त है। राज्य सरकार चुनाव से पहले पदोन्नति शुरू कर अधिकारियों-कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की पर विचार किया जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार जून से सितंबर के बीच पदोन्नति शुरू कर देगी। हालांकि पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। यानी न्यायालय का जो निर्णय रहेगा, अधिकारियों-कर्मचारियों को स्वीकार होगा। मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के सचिव उमाशंकर तिवारी और मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष एमपी द्विवेदी कहते हैं कि पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार है और यह मिलना ही चाहिए। इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं किए जाने से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है।

बता दें कि अप्रैल 2016 को जबलपुर उच्च न्यायालय ने मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 निरस्त कर दिया था। इसके विरूद्ध सरकार उच्चतम न्यायालय चली गई और तभी से मामला लंबित है। इस कानून में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद से प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। तब से अब तक 70 हजार से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इनमें कई ऐसे अधिकारी-कर्मचारी हैं, जो पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त हो गए। तभी से कर्मचारी संगठन सरकार से पदोन्नति देने की मांग कर रहे हैं। सरकारी आंकलन के तहत अगर कर्मचारियों को प्रमोशन मिलता है तो खजाने पर सालाना ढाई हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। उधर कर्मचारियों के प्रमोशन तो नहीं हो रहे हैं लेकिन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस समेत राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के प्रमोशन हो रहे हैं। कमलनाथ सरकार में ये मामला विधानसभा में भी उठा था। तत्कालीन स्पीकर ने निर्देश दिए थे कि जब तक प्रमोशन का फैसला नहीं हो जाता तब तक अफसरों को भी प्रमोशन ना दिया जाए। लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही ये निर्देश और कर्मचारियों की किस्मत भी फाइलों में कैद होकर रह गई। गौरतलब है कि प्रदेश में 2016 से सरकारी विभागों में प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसकी वजह हाईकोर्ट में 2002 में बनाए गए प्रमोशन नियम को रद्द किया जाना है। तर्क दिया गया है कि सेवा में अवसर का लाभ सिर्फ एक बार दिया जाना चाहिए। नौकरी में आते समय आरक्षण का लाभ मिल जाता है फिर पदोन्नति में भी आरक्षण का लाभ मिल रहा था। इसे लेकर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को आपत्ति थी। इसलिए हाईकोर्ट ने पदोन्नति का नियम ही खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से जो पदोन्नति हुई उन्हें रिवर्ट किया जाए। हालांकि अब सरकार चुनावी साल में अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रमोशन देने की तैयारी कर रही है। सबकुछ ठीक रहा तो जून से पदोन्नति की सौगात मिलनी शुरू हो जाएगी।

● **जितेंद्र तिवारी**

नाराज हैं अधिकारी और कर्मचारी

राज्य सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के दूसरे विकल्प के रूप में वरिष्ठ पद का प्रभार देना शुरू किया है। पुलिस और जेल विभाग के कर्मचारियों को 8 माह पहले यह लाभ दिया गया था। अब स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रभार दिया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी इससे असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रभार देना अलग बात है और पदोन्नति अलग बात है। उनका कहना है कि वरिष्ठ प्रभार मिलने से पैसा तो मिल जाएगा, पर वह प्रतिष्ठा (हैसियत) नहीं मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का कहना है कि पदोन्नति कर्मचारियों का अधिकार है, उन्हें यह मिलना ही चाहिए। इसे लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं किए जाने से कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है। सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने को लेकर दिसंबर, 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। कमेटी ने कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने के संबंध में जनवरी, 2021 में शासन को अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद अब तक तीन विभागों में ही कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार सौंपे जाने की कार्रवाई शुरू हो पाई है। प्रमोशन न होने से सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी हो गई है। दफ्तरों में प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। वल्लभ भवन में ही एक अधिकारी के पास दो से तीन बड़े विभागों का प्रभार है। इससे वे मूल पदस्थापना वाली जगह भी काम नहीं कर पा रहे हैं और प्रभार में जो विभाग मिला है, वहां तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव जीएडी विनोद कुमार का कहना है कि कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अंतिम निर्णय उच्च स्तर पर लिया जाएगा।

हैदराबाद की तर्ज पर मप्र के शहरों का विकास क्यों नहीं?

मप्र को यहां की सरकार देश का सबसे विकसित राज्य मानती है। इसके लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मप्र के शहरों का अनियोजित विकास हो रहा है। खासकर राजधानी भोपाल और व्यावसायिक राजधानी इंदौर में विकास एक तरफा हो रहा है। जबकि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद शहरों के विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड है। हैदराबाद में चारों तरफ विकास हुआ है। शहर के विकास के लिए रिंग रोड बनाई गई है। जिसके किनारे सुनियोजित विकास किया गया है। जबकि इंदौर और भोपाल में मनमाना विकास हुआ है। शहर में एक तरफा विकास के कारण कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि भोपाल और इंदौर का विकास हैदराबाद और बेंगलुरू जैसे शहरों की तरह किया जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि भोपाल में केवल होशंगाबाद रोड पर विकास हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है शहर का पहाड़, झील और जंगल से घिरा होना। अगर वाकई सरकार व्यवस्थित तरीके से शहर का विकास करना चाहती तो पहाड़ के अंदर बड़े-बड़े टनल बनाए जा सकते थे, जिससे होकर पहाड़ के उस पार विकास को गति दी जा सकती थी। लेकिन सरकार का इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया है। सरकार विकास के प्रति कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी में 2005 के बाद कभी मास्टर प्लान लागू ही नहीं हो पाया है।

रही इंदौर की बात तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा करते हैं कि इंदौर में इसी गति से विकास होता रहा तो आने वाले 10 साल में इंदौर शहर हैदराबाद और बेंगलुरू जैसे शहर को पछाड़ देगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तेजी से विकसित हो रहे इंदौर में अभी तक कोई रिंग रोड नहीं है। यह सभी जानते हैं कि शहर में फ्लाईओवर ब्रिज का जाल बिछ रहा है। सड़कें दुरुस्त हो रही हैं। इंदौर नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। इंदौर मेट्रो का कार्य तेज गति से हो रहा है, इंदौर मेट्रो का कार्य पूरा होने के बाद मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। लेकिन अभी शहर में जो भी विकास हो रहा है वह अनियोजित है। विडंबना यह है कि इंदौर के विकास का मास्टर प्लान 2035 बनकर तैयार है, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।

देशवासियों के बीच मप्र के इंदौर व भोपाल सबसे चर्चित विकसित शहरों में शुमार हैं। लेकिन दोनों शहरों में लंबे समय से कछुआ गति विकास चल रहा है, जिससे शहर कस्बाई छवि से बाहर नहीं निकल पाए हैं। भले ही फ्लाईओवर जैसी नई सौगात दामन में आ चुकी है किंतु अब भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। मसलन, सीवर लाइन प्रोजेक्ट से नगरवासियों ने जो आशा लगाई थी, वह अब तक पूरी नहीं हुई है। बावजूद इसके कि इस परियोजना में करोड़ों रुपए स्वाहा हो गए। लिहाजा, पड़ताल होनी चाहिए। अब तक कई क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन बहुत सारे आयाम अब भी विकास की बाट जोह रहे हैं। इसलिए समग्र विकास का मानचित्र बनाकर सुनियोजित विकास होना चाहिए। मास्टर प्लान के अनुरूप सभी कमियां दूर की जानी चाहिए। इससे जनता को लाभ होगा। साथ ही शहर की तस्वीर भी बदल जाएगी।

भोपाल और इंदौर को भौतिक विकास की दिशा में उसे **और अधिक सजाने-संवारने** की दरकार है। जनता लंबे समय से अपने शहर को दूसरे महानगरों जैसा देखने का सपना पाले हुए है। भोपाल प्रदेश का सबसे सुंदर शहर है। चारों तरफ नैसर्गिक दृश्यों की भरमार है। इसलिए यहां की धरोहरों को सहेजा जाना चाहिए। प्राकृतिक रूप से किसी तरह की छेड़छाड़ के बिना विकास होना चाहिए। विकास के मामले में भोपाल को लंबे समय से अन्याय सहना पड़ा है। वर्तमान में इंदौर हो या भोपाल दोनों शहरों में ढांचागत विकास खूब हो रहा है, लेकिन बिना मास्टर प्लान के हो रहे इस विकास से शहर ग्रामीण क्षेत्रों में घुस रहा है। इससे नगर निगम की सीमा से बाहर हो रहे विकास को वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो किसी शहर को मिलनी चाहिए। ऐसे में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वाकई सरकार को प्रदेश के दोनों बड़े शहरों को हैदराबाद की तरह विकसित करना है तो ठोस रणनीति के तहत काम करना होगा।

● **राकेश ग्रोवर**

स्मार्ट सिटी ने बिगाड़ा स्वरूप

केंद्र सरकार ने देश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चला रखा है। लेकिन विडंबना यह है कि स्मार्ट सिटी के कारण भोपाल और इंदौर दोनों शहरों का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। गौरतलब है कि 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके तहत इन शहरों को आधुनिक और सिटीजन फ्रेंडली बनाने का लक्ष्य तय किया गया था। करीब 7 साल बाद इनमें से 7 शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा। इनमें से 5 शहर उन राज्यों में हैं जहां इस साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समयसीमा जून 2023 में समाप्त होगी। अभी तक जो काम हुआ है, उस लिहाज से सिर्फ सात शहर ही अधिकतर प्रोजेक्ट्स पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें भोपाल पहले नंबर पर है। सरकारी दावों के अनुसार भोपाल में इस प्रोजेक्ट से संबंधित 92 फीसदी काम पूरे हो गए हैं। सूरत में 82.44, उदयपुर में 78 और भुवनेश्वर में 76 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। इसके अलावा इंदौर, वाराणसी और अहमदाबाद में 70 फीसदी काम पूरा हो सका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भोपाल में 940 प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें 862 पूरे हो गए हैं। सूरत में 1219 में 1005, उदयपुर में 947 में 739, भुवनेश्वर में 846 में 644, अहमदाबाद में 930 में 648, इंदौर में 1042 में 727 और वाराणसी में 997 में 700 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। जबकि मैदानी स्थिति यह है कि भोपाल और इंदौर में जिस क्षेत्र को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, वहां बसे बसाए शहर को तो उजाड़ दिया गया, लेकिन परियोजनाएं अभी भी अधूरी पड़ी है। लोग कहते हैं- ऐसा विकास किस काम का।

नई रेत नीति अधर में

मप्र में इसी साल से नई रेत नीति लागू होनी है। खनिज साधन विभाग ने नीति तैयार कर ली है, जो कैबिनेट की सहमति के लिए भेजी गई है। नई नीति में रेत की कीमत नियंत्रण के प्रयास किए गए हैं। इसमें प्रविधान किया है कि ठेकेदार रेत की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। वहीं उन्हें ठेके की आधी राशि अग्रिम जमा करनी होगी। अब तक उन्हें 25 प्रतिशत राशि जमा करनी पड़ती थी। बता दें कि वर्षाकाल के बाद प्रदेश में नई रेत नीति के अनुसार खदानें नीलाम की जाएंगी। ज्यादातर रेत खदानों की ठेका अवधि पूरी होने में दो महीने से भी कम समय बचा है, पर खनिज विभाग अब तक नई रेत नीति पर कोई निर्णय नहीं कर सका है। साल 2019 की रेत नीति लागू होने की बाद कोरोनाकाल में विभाग और ठेकेदारों के बीच तमाम कानूनी विवाद उत्पन्न हो गए थे।

जानकारी के मुताबिक विभाग को फरवरी तक रेत नीति को फाइनल करके मई और जून में टेंडर प्रक्रिया पूरी करनी थी। रेत नीति का ड्राफ्ट जनवरी में ही तैयार कर लिया था। हालांकि अब तक ड्राफ्ट को ही स्वीकृति नहीं मिल सकी है। सूत्रों की मानें तो विभाग चुनावी वर्ष में रेत नीति को फाइनल करके किसी वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। इसलिए होशंगाबाद सहित कुछ ठेकों को शार्ट टेंडर पर और कुछ ठेकों को नवीनीकृत करके वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक ठेकों की अवधि कुछ महीने बढ़ाकर विधानसभा चुनाव तक नई रेत नीति को टाला जा सकता है। डायरेक्टर (माइनिंग) राजीव रंजन मीणा ने स्वीकार किया कि नई रेत नीति पर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। उन्होंने साथ ही कहा कि मई माह में खनिज विभाग इस विषय पर कोई न कोई निर्णय ले लेगा।

मप्र खनिज निगम ने रेत खदानों की खनन योजना (माइनिंग प्लान) के लिए निविदा जारी कर दी है। इसके लिए 26 समूह बनाए गए हैं। ठेका लेने वाली कंपनी को प्रदेश के 48 जिलों में स्थित 1405 रेत खदानों की खनन योजना बनानी होगी। इसके आधार पर ही अगले वित्त वर्ष में रेत खदानों की नीलामी होगी। वहीं नर्मदा नदी के किनारे स्थित पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में फैली रेत खदानों की खनन योजना बनाने के लिए कंपनी को दो माह और पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की खदान की खनन योजना बनाने के लिए एक माह का समय दिया जाएगा। खनन योजना के साथ ही पर्यावरण स्वीकृति का जिम्मा भी निजी कंपनियों को ही सौंपा जा रहा है। पर्यावरण स्वीकृति के लिए जिला एवं प्रदेश स्तरीय पर्यावरण समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। ठेका लेने वाली कंपनी काम करेगी, पर उसे समयसीमा के बंधन में नहीं बांधा है।

दरअसल, पर्यावरण अनुमति समिति की बैठक पर निर्भर करेगी। खनन योजना बनाने का जिम्मा भी उन्हीं कंपनियों को सौंपा जाएगा, जिन्हें भारत सरकार के खान मंत्रालय ने अधिकृत किया है। खनन योजना तैयार करने पर खर्च होने वाली राशि की वसूली रेत खदान लेने वाले ठेकेदारों से की जाएगी। बता दें कि वर्तमान में खनन योजना और पर्यावरण स्वीकृति लेने की जिम्मेदारी खदान का ठेका लेने वाले ठेकेदार की ही है। अधिकतर मामलों में ठेकेदार छह माह से सालभर तक यह स्वीकृतियां नहीं ले पाते हैं। इस कारण खदान से रेत खनन शुरू नहीं हो पाता। जिससे उन्हें और सरकार को घाटा होता है। वर्ष 2019 में लागू की गई रेत नीति की अवधि समाप्त हो रही है। सरकार नई रेत नीति ला रही है, जो अक्टूबर में लागू की जा सकती है। नई नीति में ठेकेदारों का भी परामर्श लिया गया है। वहीं अधिकतर ठेकेदारों ने कहा है कि वर्तमान रेत नीति की अवधि एक साल बढ़ाई जाए। क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते वे करीब डेढ़ साल खनन नहीं कर पाए हैं।

वर्तमान में अलग-अलग महीने के हिसाब से और कम वर्षों के लिए ठेके दिए जाने का नियम है। नई रेत नीति 2023 में अन्य बदलाव की बात भी की गई है। सूत्रों का मानना है कि इस बार रेत चोरी और रॉयल्टी चोरी की जांच के लिए नाके लगाने का प्रावधान किया जाएगा। मप्र की सभी रेत खदानें नियम 2019 के अनुसार नीलाम की गई थी। हालांकि, पिछले तीन वर्षों में पूरी तरह से रेत खदानों की नीलामी नहीं हो पाई है। रेत खदानों की नीलामी नहीं होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले रेत की नई नीति को लागू किया जा सकता है। इस नई नीति में तहसील स्तर पर रेत खदानों के समूह बनाकर नीलामी की जाएगी। नीलामी स्थानीय स्तर पर होगी। जिसके पूरे अधिकार कलेक्टर को रहेंगे। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होगी। इसके लिए सीसीटीवी से निगरानी की जा सकती है। वर्षाकाल के बाद कलेक्टर रेत सहित जिले में मौजूद अन्य खनिजों के भंडारण की स्थिति का भी आंकलन शुरू कर सकते हैं।

● **डॉ. जयसिंह सेंधव**

नई नीति में होंगे बदलाव

दरअसल, बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए शिवराज सरकार हितग्राही को मुफ्त रेत देगी और मकान बनाने के लिए हितग्राही से रॉयल्टी भी नहीं ली जाएगी। इसमें 3 साल की जगह 5 साल का ठेका दिया जाएगा। नई रेत नीति में इसका प्रविधान किया जा रहा है और इसके लिए गठित मंत्री समूह ने इस पर सहमति भी दे दी है। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें लागू होंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो नई नीति के तहत हितग्राही को मकान बनाने के लिए 16 घन फीट रेत की पात्रता होगी। खनिज अधिकारी हितग्राही को पास जारी करेगा और इसी आधार पर हितग्राही रेत खदान से 16 घन फीट में रेत उठा सकेगा। वहीं इसमें रेत केवल उसी हितग्राही को निशुल्क दी जाएगी, जो स्वयं का मकान बनाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरों में बहुमंजिला इमारत बनाकर हितग्राही को फ्लैट दिए जा रहे हैं, ऐसे में फ्री रेत का लाभ शहर के हितग्राही को संभवतः नहीं मिल पाएगा। खबर है कि नई रेत नीति में शिवराज सरकार जिले में एकल ठेका देने के स्थान पर तहसील एवं पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे ठेके दे सकती है।

कोरोना महामारी, अंतराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में गिरावट, बढ़ती महंगाई के बाद भी मप्र ने तेजी से आर्थिक विकास किया है। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद मप्र का आर्थिक विकास आज देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार ने तमाम संकट के बीच मप्र की विकास दर को किस तरह बढ़ाया है इसका कई राज्य अध्ययन कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मप्र का जो अभियान चला रखा है उसने प्रदेश को और सशक्त बनाया है।

मप्र में तेजी से हो रहा औद्योगिक विकास

आज जिस तरह भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वैसे ही मप्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रदेश की विकास दर में 16.34 प्रतिशत की बढ़त हुई है। वर्ष 2002 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 71,594 करोड़ था, जो कि अब बढ़कर 13,22,000 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, साल 2002 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी। जो कि साल 2022-23 में बढ़कर 1 लाख 40 हजार 500 रुपए पहुंच गई है। सरकार ने साल 2003 के बाद से अब तक का विकास बताया है। अधिकांश आंकड़ों में 2003 और 2022 की तुलना की गई है। इसके पीछे कारण यह है कि 2003 के पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वर्ष 2018 में भले ही कांग्रेस सरकार बनी थी, लेकिन वह डेढ़ साल में ही गिर गई थी।

आज मप्र कृषि क्षेत्र में सर्वोपरि है, प्रदेश के औद्योगिक विकास को पंख लगे हैं, महिला स्वसहायता समूह, बिजली की उपलब्धता, सड़कों का जाल, लाड़ली लक्ष्मी योजना, जनजातीय बजट में 1620 प्रतिशत की वृद्धि, शिक्षा के लिए नवाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान, स्वच्छता का नवाचार, आयुष्मान भारत योजना, नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में देश के अन्य राज्यों से मप्र काफी आगे है। यह सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्पण, सक्रियता की वजह से संभव हो पाया है।

आर्थिक सवेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मप्र में औद्योगिक विकास दर तेजी से बढ़ी है। साल 2001-02 में औद्योगिक विकास दर -0.61 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है। मप्र देश के कई बड़े प्रोजेक्टस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन आया है। ग्वालियर से होकर जाने वाले ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (एनएच 27) को उत्तर भारत में प्रवेश करने के लिए मप्र का गेटवे कहा जाता है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए अटल प्रगति पथ बनाया जा रहा है, तो वहीं नर्मदा प्रगति पथ विकास की गतिविधियों को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। पथ के दोनों ओर औद्योगिक पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इंदौर-भोपाल के बीच 20 हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र मेगा इंवेस्टमेंट जोन प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में अधोसंरचना से लेकर बिजली, पानी, भूमि सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चौतरफा विकास के कारण निवेश के लिए अनुकूल यह राज्य बन गया है। सभी अनुमतियां एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, निश्चित समय सीमा में अनुमतियां नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई करने के साथ स्वमेव अनुमति प्राप्त होने का प्रविधान किया गया है। राज्य में 95 से अधिक

औद्योगिक इकाईयों का बड़ा हब मंडीदीप

राजधानी भोपाल से सटा हुआ मंडीदीप आज औद्योगिक इकाईयों के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है जहां ल्यूपिन, प्रॉक्टर एंड गैंबल, दावत फूड्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, एचईजी लिमिटेड जैसी कंपनियों की मौजूदगी है, जो हर साल यहां से करोड़ों रुपए के उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक निवेश की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ है जिसके बाद से यहां पर उद्योग स्थापित हुए हैं और कई निवेशक यहां उद्योग लगाने में अपनी रूचि दिखा रहे हैं। इसमें से भी 400 फैक्ट्री एमएसएमई कैटेगरी की हैं।

औद्योगिक क्षेत्र, सात स्मार्ट सिटी और परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। खेती एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे औद्योगिक निवेश के लिए माहौल बना है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक, आईटी, अक्षय ऊर्जा, पर्यटन, शहरी विकास ऐसे क्षेत्र हैं, जहां निवेश की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में ऑटो मोबाइल के क्षेत्र में निरंतर निवेश हो रहा है। 10 से अधिक उपकरण निर्माता और 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माता काम कर रहे हैं। इंदौर और भोपाल में भारत के अग्रणी ऑटो क्लस्टर हैं। पीथमपुर में साढ़े चार हजार हेक्टेयर में विकसित औद्योगिक क्लस्टर 25 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। इंदौर में एशिया के सबसे लंबे और तेज गति के टेस्टिंग ट्रेक नेट्रेक्स की स्थापना की गई है।

मप्र उद्यानिकी, मसालों, संतरा, अदरक, लहसुन, दलहन, तिलहन एवं डेरी उत्पाद में अग्रणी है। केंद्र सरकार से 7 बार प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। सिंचाई का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। 8 सरकारी और 2 निजी मेगा फूड पार्क हैं। जैविक खेती में अव्वल होने के साथ अब प्राकृतिक खेती की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावना है। मप्र फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इंदौर, देवास, भोपाल, मंडीदीप, मालनपुर और पीथमपुर में फार्मा क्लस्टर हैं। यहां 300 फार्मा एवं मेडिकल यूनिट से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। विक्रम उद्योगपुरी, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, ब्राजील, हालैंड सहित 160 से अधिक देशों में राज्य में बनने वाली दवाईयां निर्यात की जा रही हैं। वर्ष 2021 में राज्य से 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का फार्मा निर्यात किया गया। फार्मा सेक्टर के विकास और क्षमता को देखते हुए प्रदेश में फार्मा औद्योगिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण मप्र लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निवेश के लिए आदर्श राज्य है। देश की 50 प्रतिशत आबादी मप्र से जुड़ी हुई है। इससे विशाल उपभोक्ता बाजार पर नियंत्रण किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सहयोग से इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश स्टील साइलो निर्माण के क्षेत्र में भी अग्रणी है।

मप्र में इंडस्ट्री सेक्टर में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और हजारों की संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए एमएसएमई विभाग अगले 6 महीने के अंदर 100 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के प्लान पर काम कर रहा है। हर जिले में कम से कम एक क्लस्टर होगा, जिसमें एक ही तरह के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग होंगे। विभाग की योजना है कि पीएम क्लस्टर्स का उद्घाटन करें। विभाग के मुताबिक राज्य सरकार के अधीन प्रदेश में कुल 68 क्लस्टर्स प्रस्तावित हैं। 26 स्वीकृत, 24 प्रक्रियाधीन और 18 के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। इनके लिए कुल 1548 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है। इन क्लस्टर्स में कुल 3040 यूनिट्स लगेंगी। 1,76,981 लोगों को रोजगार मिलेगा। 13,836 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। केंद्र की एमएसई सीडीपी योजना के तहत कुल 13 क्लस्टर्स प्रदेशभर में स्वीकृत हो चुके हैं। 2-2 प्रक्रिया और प्रस्ताव के चरण में हैं, साथ ही 7 के लिए क्षेत्र आदि चयन किया जा चुका है। इनसे लगभग 27500 लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश में अब तक औद्योगिक विकास चुनिंदा क्षेत्रों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, पीथमपुर के आसपास होता रहा है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन रहा है, नए क्लस्टर खुलने से दूरदराज और छोटे शहरों, ब्लॉक तथा तहसील तक उद्योगों का विकास होगा। प्रगति की समीक्षा हर 15 दिनों में होती है। विभाग के पास एमएसएमई अधोसंरचना के लिए 129 करोड़ का बजट उपलब्ध है। भोपाल में 2 निजी क्लस्टर्स को मंजूरी मिल चुकी है। खाद्य प्रसंस्करण (बैरसिया) और मल्टी स्टोरी मेडिकल डिवाइस क्लस्टर (गोविंदपुरा) शामिल है। जबलपुर का रेडीमेड गारमेंट, शिवपुरी में नेहरू जैकेट, छतरपुर में 2 फर्नीचर क्लस्टर, इंदौर-रतलाम में कई नमकीन क्लस्टर, सागर-विदिशा में कृषि उपकरणों सहित कई जिलों में फूड प्रोसेसिंग के क्लस्टर शामिल हैं।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

एचईजी लिमिटेड औद्योगीकरण का दीया जलाने वाला पहला उद्योग

70 के दशक में मप्र मंडीदीप में औद्योगीकरण का दीया जलाने वाला पहला उद्योग एचईजी था। स्टील प्लांट्स के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनाने वाली एचईजी के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की मांग आज दुनियाभर में है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड उन इस्पात उत्पादकों के लिए एक कच्चा माल है जो पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया के बजाय इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट (ईएएफ) का इस्तेमाल करते हैं। मंडीदीप प्लांट से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीकी देशों को इसकी सप्लाई की जा रही है। मंडीदीप प्लांट एकड़ में फैला है, जिसके माध्यम से 1800 लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है। मंडीदीप, मप्र में एचईजी के पास 76.5 मेगावाट (दो थर्मल पावर प्लांट और एक हाइड्रोपावर प्लांट) की क्षमता वाले ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उत्पादन का कारखाना है। एचईजी लिमिटेड मंडीदीप के सीएमडी रवि झुनझुनवाला का कहना है कि मप्र में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में काम करने का बेहतरीन माहौल है। सरकार की औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है और मप्र निवेशकों के लिए उपयुक्त राज्य है। उनकी कंपनी की इकाई ग्रेफाइट एनोड के विनिर्माण के लिए प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। देवास जिले के ग्राम सिरसौदा में निवेश किया जाएगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 20 हजार मीट्रिक टन होगी। 1 जनवरी 2025 तक प्रथम चरण का उत्पादन शुरू होगा और एक जनवरी 2028 तक परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। प्रथम चरण में कंपनी द्वारा ग्रेफाइट विनिर्माण के लिए औद्यागिक क्षेत्र मंडीदीप स्थित इकाई परिसर में 1200 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से किए जा रहे विस्तारीकरण के बाद यह इकाई ग्रेफाइट उत्पादन के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी होगी।

कानूगोलू ने संभाला मोर्चा

कांग्रेस ने मप्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने अभियान को आकार देने में मदद करने के लिए, प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी, चुनावी रणनीतिकार सुनील कानूगोलू को शामिल किया है, जहां सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को भाजपा द्वारा सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। मप्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। कानूगोलू फिलहाल कर्नाटक में कांग्रेस के अभियान की अगुवाई कर रहे थे, हालांकि उनकी टीम मप्र में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद अब वह मप्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और राज्य में अपना कार्यालय स्थापित करेंगे। कानूगोलू ने पहले भाजपा के अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम किया था। बाद में उन्होंने कांग्रेस के लिए रणनीति बनाना शुरू किया। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी योगदान दिया। विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक पेशेवर रणनीतिकार की मदद काम आती है। मप्र की आंतरिक राजनीतिक स्थिति, जातिगत समीकरणों सहित, कार्य को और अधिक जटिल बनाती है। शायद कांग्रेस को अपना चुनाव प्रबंधन तंत्र बनाना चाहिए।

कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि कानूगोलू पार्टी के अभियान और सांसद को आकार देने में अहम भूमिका निभाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्होंने उप्र में भाजपा के लिए काम किया था और कहा जाता है कि उन्होंने 2017 में योगी आदित्यनाथ की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के मप्र विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस 230 सदस्यीय सदन में 114 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि भाजपा ने 109 सीटें जीतीं। भव्य पुरानी पार्टी ने कमलनाथ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई। हालांकि, राज्य के एक प्रभावशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह के कारण कांग्रेस के कई विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वे बाद में भाजपा में शामिल हो गए, जिससे शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का मार्ग प्रशस्त हुआ।

कानूगोलू का नाम चौंकाने वाला हो सकता है लेकिन देश के राजनीतिक गलियारों में जाना पहचाना हो चुका है। राजनीतिक चर्चा से पहले कानूगोलू के बैकग्राउंड को जान लेते हैं। कन्नड़ पिता और तेलुगु मां की संतान कानूगोलू ने जिंदगी का लंबा हिस्सा तमिलनाडु में बिताया है। उनकी ज्यादातर पढ़ाई चेन्नई में हुई। उन्होंने अंडरग्रेजुएट के तौर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। साल 2009 में अमेरिका से भारत लौटने के पहले सुनील ने फाइनेंस में एमएस और एमबीए की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की थी। इसके बाद सुनील पॉलिटिकल या इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर कई राजनीतिक दलों को सेवाएं दे चुके हैं।

नकुलनाथ के बंगले को बनाया वॉर रूम

कमलनाथ ने अपने बेटे और कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के भोपाल स्थित निवास को वॉर रूम बनाया है। बताया जा रहा है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही सुनील कानूगोलू की टीम ने भोपाल में डेरा डाल लिया है। यह टीम सोशल मीडिया, विधायकों का सर्वे और जमीनी फीडबैक जैसे काम भी करेगी। ताकि चुनाव तक पूरी तैयारियां की जा सकें। इसके अलावा सरकार की योजनाओं का जनता से फीडबैक लिया जाएगा, ताकि जनता से फीडबैक लेने के बाद काउंटर रणनीति बनाई जा सके।

फिलहाल कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना समेत मप्र विधानसभा चुनाव के लिए सुनील कानूगोलू को इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट बनाया है। सुनील के जिम्मे ग्राउंड रियलिटी के आधार पर इलेक्शन कैंपेन तैयार करना है। बताया जाता है कि सुनील साल 2014 में प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के साथ जुड़े थे। बाद में प्रशांत किशोर ने मोदी का साथ छोड़ दिया। लेकिन सुनील अपनी टीम के साथ भाजपा से जुड़े रहे। साल 2017 में उप्र विधानसभा चुनाव में सुनील ने इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने भाजपा को शानदार जीत दिलाकर योगी आदित्यनाथ के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ किया। उप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा, 2019 लोकसभा चुनाव में द्रमुक और 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नाद्रमुक की तरफ से सुनील मुख्य रणनीतिकार रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद साख मजबूत बनाकर पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय सुनील को दिया गया था। सुनील कर्नाटक चुनाव में काम शुरू कर चुके हैं। जल्द ही बाकी राज्यों में भी कांग्रेस के लिए वार रूम सेटअप तैयार करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी को घेरने के लिए सुनील ने एक यूनिक आईटी प्रोग्राम तैयार किया। 40 फीसद पेसीएम कैंपेन के माध्यम से उन्होंने भाजपा सरकार को भ्रष्ट जाहिर किया। उन्होंने एक क्यूआर कोड के बीच कर्नाटक मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर 40 फीसद कमीशन लेने वाला भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। व्यंग्यात्मक कैंपेन कर्नाटक के साथ पूरे देश में चर्चा का विषय बना। कहा जाता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रणनीति भी उन्होंने तैयार की थी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने का आइडिया भी कानूगोलू का था। सुनील फिलहाल कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस का चुनाव मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। सुनील के सामने कांग्रेस को आगामी मप्र विधानसभा चुनाव में विजय दिलाने की कई चुनौतियां हैं।

सुनील कानूगोलू के सामने कई चुनौतियां हैं। मप्र में ठंडे पड़े कांग्रेस के संगठन को सक्रिय करना, किसान कर्जमाफी योजना की विसंगतियों को दूर करना, भाजपा के 18 वर्षीय शासन का एंटी इनकम्बेंसी बनाना, भाजपा की लाडली बहना जैसी गेम चेंजर योजनाओं का काउंटर, प्रत्याशी चयन में जातीय और क्षेत्रीय भावनाओं का ध्यान रखना, स्थानीय मुद्दों की पहचान कर सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट करना, पार्टी के अंदर भितरघात को खत्म कर एकजुट बनाए रखना, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ समन्वय बनाकर काम करना, केंद्रीय नेतृत्व के एजेंडा के साथ राज्य नेतृत्व में सामंजस्य रखना और मोदी मैजिक और भाजपा के दुष्प्रचार को कांग्रेस के पक्ष में काउंटर करने जैसी कई चुनौतियां उनके सामने हैं।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

मप्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नवाचार कर रहे हैं, लेकिन इन नवाचारों का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसकी वजह है व्यवस्था में समाई भर्राशाही। इसका नजारा इस बार बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिला। एक तरफ शिक्षा माफिया लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही थी कि इसका असर परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा। जबकि परीक्षाओं के पेपर लीक होने से मेधावी छात्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

व्यवस्था पर नकेल कब?

मप्र में बहुचर्चित पेपर लीक मामले में शासन और शिक्षा विभाग की फजीहत के बाद एमपी बोर्ड सख्त हो गया है। पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा मंडल ने कड़ा कदम उठाया है। छात्र-छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यसमिति ने बड़ा निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार एमपी बोर्ड के पेपर आउट करने वालों पर अब रासुका (एनएसए) की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं इसके साथ ही 10 साल की सजा और 10 लाख का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। वहीं पेपर आउट करने वाले शिक्षकों की बर्खास्तगी होगी। बर्खास्तगी की कार्रवाई भी लंबित नहीं रहेगी बल्कि समय सीमा में होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बाद संभवत: एमपी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सजा के डर से भी लीक करने के पहले कई बार सोचना पड़ेगा।

इस बार हुई बोर्ड परीक्षाओं में हायर सेकेंडरी और हाईस्कूल दोनों की परीक्षाओं से पहले ही प्रश्नपत्र सोशल मीडिया के जरिए परीक्षा से कुछ देर पहले लीक हो गए थे। हालांकि उस वक्त बोर्ड के अधिकारी यही हवाला देते रहे कि यह पेपर आउट होने का मामला नहीं है, बल्कि परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचने के बाद पेपर की गोपनीयता भंग करने का मामला है। हालांकि उस दौरान अनेक शिक्षकों समेत कई गिरोह पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी।

माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने पर मप्र मान्यता परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार अब तक 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसके बाद भी दोषी बच निकलते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर सख्त नजर आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि बोर्ड परीक्षाओं के पेपर आउट करने वालों पर एनएसए लगाया जाएगा। 10 साल की जेल और 10 लाख का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। समय सीमा के भीतर शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। ताकि आने वाले सालों में बोर्ड परीक्षा के पेपर की गोपनीयता भंग ना हो सके।

माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष वीरा राणा और सचिव श्रीकांत बनोठ की उपस्थिति में कार्यपालिका की समिति की बैठक हुई। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य शिरोमणि दुबे, रामकुमार भावसार प्रवीण पाराशर, आयुक्त लोक शिक्षण अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव वित्त वक्की कार्तिकेयन, उप सचिव स्कूल शिक्षा प्रमोद सिंह सहित अन्य शामिल थे। मप्र परीक्षा अधिनियम 1937 की धारा 14 के प्रावधान में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने वालों के लिए केवल 3 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए बैठक में निर्णय लिया गया कि आगे इस तरह की गोपनीयता भंग ना हो इसके लिए सख्ती जरूरी है। उसके बाद सजा की अवधि बढ़ाने और एनएसए में कार्रवाई का फैसला लिया गया। मप्र में इस बार बोर्ड परीक्षा की शुरुआत में ही पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुए थे। 13 दिन के भीतर ही 10 से ज्यादा पेपर लीक कर दिए गए थे। वहीं अगर किसी परीक्षा का पेपर लीक करने में कोई शिक्षक भी शामिल पाया जाता है तो उक्त शिक्षक की बर्खास्तगी हो जाएगी। बर्खास्तगी की कार्रवाई को भी लंबित नहीं रखा जाएगा बल्कि समयसीमा में नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड को उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद संभवत: पेपर लीक नहीं होंगे। इसलिए सख्त सजा का डर बढ़ाने यह प्रस्ताव पारित किया गया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

19 से ज्यादा शिक्षक निलंबित

एमपी बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा में घोर लापरवाही बरतने के कारण 6 केंद्राध्यक्ष, 7 सहायक केंद्राध्यक्ष, 5 शिक्षकों, एक अन्य सहित 19 शिक्षकों को निलंबित किया है। इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़वानी केंद्र अध्यक्ष बल सिंह चौहान, सहायक केंद्र अध्यक्ष दिलीप सिंह अवास्या, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ रायसेन, केंद्र अध्यक्ष रमाशंकर अहिरवार, सहायक केंद्र अध्यक्ष निर्भय सिंह मवेदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपलिया कुलमी राजगढ़ केंद्र अध्यक्ष रेखा बैरागी, जीरापुर सहायक केंद्र अध्यक्ष राम सागर शर्मा, धनराज पाटीदार, न्यू आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल नरसिंह नगर चार शहर का नाका ग्वालियर केंद्र अध्यक्ष हुकुमचंद लचौरिया प्राचार्य, सहायक केंद्र अध्यक्ष विवेक कुमार लिटोरिया, शासकीय कन्या हाई स्कूल नालछा जिला धार केंद्र अध्यक्ष रमेश चंद्र भाबोर, सहायक केंद्र अध्यक्ष रविंद्र कोचली, मुकेश नायक लिपिक, मयंक इंदुलकर, सुमित यादव, विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल भानपुर, भोपाल केंद्राध्यक्ष राजकुमार सक्सेना प्राचार्य, सहायक केंद्र अध्यक्ष रेखा गोयल पवन सिंह, विश्वनाथ सिंह शामिल हैं।

आखिर प्रभारी मंत्री को किसने दिया अधिकार

मई महीने की 9 तारीख को खरगोन में रेलिंग तोड़कर एक बस 50 फीट नीचे सूखी नदी में जा गिरी। बस में 69 यात्री सवार थे। जिसमें से 25 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद देशभर में कोहराम मच गया। इस घटना के बाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आव देखा न ताव और बिना जांच के ही आरटीओ को दोषी करार देते हुए सस्पेंड कर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस हैसियत से प्रभारी मंत्री ने आरटीओ को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। जिले के प्रभारी मंत्री के पास कृषि विभाग है। ऐसे में बस हादसे के लिए मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री सख्त कदम उठाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने तत्काल प्रभाव से आरटीओ को सस्पेंड कर प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारों का कहना है कि बिना विभागीय व्यवस्था जाने बिना एक प्रभारी मंत्री द्वारा ऐसा कदम उठाना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दरअसल, प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। लेकिन परिवहन विभाग में अमला न के बराबर है। इसका आंकलन इसी से किया जा सकता है कि परिवहन विभाग में इंस्पेक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए 2011 में 45 पद स्वीकृत किए गए थे। लेकिन अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसके अलावा विभाग में अन्य पद भी खाली पड़े हैं। ऐसे में विभाग किस स्थिति में बसों या **अन्य वाहनों** की जांच कर पाएगा। अगर अपने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र या राजस्थान को देखें तो वहां परिवहन विभाग के पास पर्याप्त अमला है। महाराष्ट्र में 435 इंस्पेक्टर्स हैं। यानी मप्र से करीब 10 गुना ज्यादा।

वैसे देखा जाए तो प्रदेश में बस हादसे आम होते जा रहे हैं। हर सड़क हादसे के बाद व्यवस्था पर सवाल उठते हैं और जैसे-जैसे घटना पुरानी होती जाती है, सवाल भी कमजोर पड़ते जाते हैं। नतीजा, हर कुछ दिनों में एक्सीडेंट की खबर आती रहती है। सीधी में 16 फरवरी 2021 को यात्रियों से भरी बस नहर में गिरने से 53 लोगों की मौत हो गई थी। ड्राइवर ने नहर से सटे शार्टकट रास्ते से बस निकालने की कोशिश की। इसी दौरान वह स्टेयरिंग से नियंत्रण खो बैठा और बस फिसलकर पास में नहर में डूब गई। जुलाई 2022 में धार जिले के खलघाट में सवारियों से भरी बस ब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए नर्मदा नदी में गिर गई थी। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। यह बस इंदौर से पुणे जा रही थी। इंदौर में 5 जनवरी 2018 को बायपास पर डीपीएस स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें 5 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। सच्चाई यही है कि पूरे मप्र में बस संचालकों की मनमानी चल रही है। इनके लिए कोई नियम-कायदा नहीं है। अंध गति से बसें दौड़ती हैं। लोगों को भेड़-बकरियों की तरह ठूंस लिया जाता है। फिटनेस का ठिकाना नहीं होता। चालक कितनी प्रशिक्षित है, यह किसी को परवाह नहीं है। सवारियां बैठाने और एक-दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में बेकाबू होकर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। हर बस दुर्घटना के बाद सरकार की तरफ से औपचारिक बयान आता है, दुख जताया जाता है, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, और फिर वो ही ठाक के तीन पात। होना यह चाहिए कि सख्त नियम बनें और उनका पालन किया जाए।

दरअसल, प्रदेश में जो बसें चलाई जा रही हैं, वे नेताओं, अधिकारियों, उद्योगपतियों आदि की हैं। परिवहन विभाग कभी-कभार सख्त कार्यवाही की कोशिश करता है तो रसूखदारों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है, जिसके कारण बसों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती है। ऐसे में यह कैसे संभव है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। दरअसल, अफसर तो व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन नेतागिरी के कारण वे सख्त कदम नहीं उठा पाते हैं। यही कारण है कि मप्र अब सड़क हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई पर पुलिस का फोकस है। साल 2021 की तुलना में 2022 में चालानी कार्रवाई तेजी से बढ़ने के बावजूद भी सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आई। सड़क हादसे कम होने की जगह करीब 8 फीसदी बढ़ गए। अब नए साल में हादसों को रोकने के लिए नए सिरे से कवायद भी शुरू हो गई है। पीटीआरआई की ताजा रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड ना होने के साथ लापरवाही से हादसे बढ़ने की बात भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कबूली है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना जरूरी है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

अफसरों से खुन्नस

परिवहन विभाग प्रदेश के सबसे कमाऊ विभागों में से एक है। लेकिन सरकार ने इस विभाग में व्याप्त अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी को दूर करने का कभी भी प्रयास नहीं किया है। इस कारण विभाग में अमले की कमी है। जिसके कारण वाहनों की जांच नहीं हो पाती है। ऐसे में विभाग के अफसरों और

कर्मचारियों को दोष देना अफसरों के प्रति खुन्नस ही कहा जा सकता है। दरअसल, मंत्री और नेता समझते हैं कि परिवहन विभाग में जो अफसर हैं, वे केवल कमाई में लिप्त हैं। व्यवस्था पर उनका ध्यान नहीं है। शायद यही वजह है कि प्रभारी मंत्री ने हादसे के लिए सीधे-सीधे प्रशासनिक अधिकारियों, विशेषकर आरटीओ की लापरवाही बता दी। उन्होंने कहा कि 35 सीटर बस में 70-70 सवारी कैसे जा रही हैं। यह अधिकारी क्यों नहीं देखते हैं। यह उनकी लापरवाही है। इसलिए इसमें जो-जो दोषी होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्रीजी को यह कौन बताए कि किसी को दोषी करार देने से पहले उनको विभाग की स्थिति का भी जायजा ले लेना चाहिए था। लेकिन उनकी यह कार्यप्रणाली दर्शाती है कि उनके तथा अन्य मंत्रियों के अंदर कितना खुन्नस भरा पड़ा है। किसी भी हादसे के बाद व्यवस्था यह होती है कि उसकी जांच कराई जाए। फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही की जाए। लेकिन मंत्रियों को इससे शायद ही कुछ लेना-देना है। त्वरित वाहवाही लूटने के लिए मंत्री बिना सोचे-समझे कुछ भी आदेश-निर्देश दे देते हैं।

शस्त्र शौक पर लगाम जरूरी

बात ढ़ाई सौ साल पुरानी है। अमेरिका में बेहतर पुलिसिंग और सुरक्षा की गारंटी नहीं होने के कारण वहां के लोगों ने अपने पास बंदूकें रखना शुरू कर दी। सुरक्षा के लिए शुरू हुआ यह काम कब शौक और शौक से बड़ी इंडस्ट्री बन गया पता ही नहीं चला। सर्वे के मुताबिक आज अमेरिका में करीब 40 करोड़ बंदूकें हैं।

चौकानें वाली बात यह है कि अमेरिका की जनसंख्या महज 33 करोड़ है। यानि एक घर में यदि चार लोग हैं तो उस घर में कम से कम पांच बंदूकें मौजूद हैं। इससे बड़ी चौकानें की बात यह है कि इन बंदूकों का कोई केंद्रीयकृत रजिस्ट्री या रिकार्ड ही अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। आज अमेरिका का समाज सबसे असुरक्षित माहौल में जी रहा है क्योंकि किसी भी आम जगह, पब, स्कूल में किसी भी उम्र का व्यक्ति सेमी ऑटोमेटिक गन से लाशें बिछा देता है। गन कल्चर अब अमेरिकी समाज के लिए नासूर बन चुका है। प्रतिवर्ष 40 हजार लोग बंदूक की गोली से मारे जा रहे हैं। आज पूरा समाज छिन्न-भिन्न है। यह स्थापित सत्य है कि अमेरिका में गन कल्चर को बढ़ावा देने में वहां के राजनेताओं के साथ ही नेशनल रायफल एसोसिएशन की गजब जुगलबंदी है। घरों में बंदूकें रखने की होड़ समाप्त न हो और कोई गन पॉलिसी का कानून न बन सके इसलिए रायफल एसोसिएशन हर साल करीब 2 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है। देश सहित मप्र की स्थिति शस्त्र कानून होने के कारण नियंत्रित तो है लेकिन पिछले कुछ सालों में इस गन कल्चर में पंजाब, उप्र और मप्र में तेजी से उछाल आया है।

ग्वालियर में तो एक-एक मंत्री एक साथ 50-50 लायसेंस अपने कार्यकर्ताओं के बनवा रहे हैं। यही कारण है कि आज ग्वालियर प्रदेश में सर्वाधिक 35 हजार लायसेंस वाला जिला बन गया है। दूसरे नंबर पर भिंड और मुरैना के लोग हैं। एक पिस्टल के लायसेंस पर दो हथियार रखे जा सकते हैं तो हथियारों की संख्या इससे कहीं अधिक होगी। वैसे जो माननीय लायसेंस के यह सिफारिशी पत्र लिख रहे हैं वह खुद भी शस्त्र के गजब शौकीन हैं। चुनाव और नेताओं के चाल-चलन पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफार्म की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि बहुत कम नेताओं का शस्त्र एवं हथियार वाला कॉलम खाली है। लाखों की महंगी बंदूकों और विदेशी रिवाल्वरें उनके पास मौजूद हैं। हथियार रखने के मामले में देश में चौथे प्रदेश हो सकते हैं लेकिन इन हथियारों से जो वारदातें हो रहीं हैं असली चिंता का कारण वही है। गन कल्चर के लिए बदनाम पंजाब में आम लोगों के पास पुलिसबल से अधिक हथियार हैं। बताते हैं कि पूरे देश के कुल हथियारों का करीब 10 फीसदी अकेले पंजाब के पास हैं। गत वर्ष पंजाब में हुई युवा सिंगर सिद्धू मूसेवाला ही हत्या ने पंजाब के इस हैरत करने वाले हथियारों के शौक से पर्दा उठाया है। मूसेवाला खुद भी इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करता दिखाई देता था।

आबादी के मान से हथियारों के प्रयोग से घटनाओं का आंकड़ा मप्र की छवि खराब करने के लिए काफी है। जब हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पूरे देश में मप्र के समाज में गन और बंदूकों से संबंधित सर्वाधिक घटनाएं हुईं हैं। पिछले 5 वर्षों में औसतन प्रति 1 लाख आबादी पर, पंजाब में एक वर्ष में हथियारों से संबंधित 1.4 मामले दर्ज किए गए, जो राष्ट्रीय औसत 4.8 से लगभग 3-4 गुना कम है। वहीं मप्र में यह राष्ट्रीय औसत से तीन गुना ज्यादा और यह देश में सर्वाधिक है। हां उप्र से भी ज्यादा। यहां प्रत्येक 1 लाख लोगों के अनुपात से साल में हथियारों से जुड़े 14 मामले दर्ज होते हैं। इंदौर हथियारों से संबंधित मामलों में देश में दूसरे नंबर पर है। 2020 में इंदौर में 1,406 हथियार और उससे संबंधित मामले दर्ज किए गए, जो कि 32 लाख की आबादी के लिहाज से राष्ट्रीय औसत से कही अधिक है। आज जिस असुरक्षित और भयभीत अमेरिकी समाज को हम देख रहे हैं वह एक दो नहीं बल्कि ढाई सौ सालों में बना है। यदि बेहतर पुलिसिंग होने के साथ ही वहां हथियारों के शौक पर समय रहते रोक लगा ली जाती तो आज समाज और वहां के नेता हथियार इंडस्ट्री के इशारों पर नहीं नाच रहा होता, हजारों लोगों की जानें न जा रही होतीं। मप्र में भी जिस तरह से शौक, शान और लायसेंस से उपकृत करने का जो चलन शुरू हुआ है उस पर तुरंत रोक के गंभीर प्रयास होने ही चाहिए।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मप्र में तीन लाख से अधिक लायसेंस

इस वक्त मप्र में करीब तीन लाख से अधिक लायसेंस हैं जिनमें रिवाल्वर, .315 रायफल और 12 बोर बंदूक शामिल है। यानि हर ढाई सौ व्यक्तियों पर एक लायसेंस है। कभी बागियों का गढ़ रहे ग्वालियर-चंबल इलाके में भी अमेरिका वाली कहानी दोहराई जा रही है। यहां बागी और डाकू नहीं बचे लेकिन उनसे रक्षा के लिए शुरु हुआ हथियार रखने का सिलसिला अब शौक और शान में बदल गया है। यही हथियार आए दिन मुरैना के गांव में मास शूटिंग या शादी में हर्ष फायरिंग में लोगों की जान ले रहे हैं। यदि अमेरिका में बंदूक के लिए गन लाबी काम कर रही है तो प्रदेश में बंदूक रखना स्टेटस सिंबल और लायसेंस दिलवाना वोट पाने का जरिया बन गई है। प्रदेश के लगभग हर जिले के कलेक्टर दफ्तर की शस्त्र लायसेंस शाखा की फाइल माननीयों के सिफारिशी पत्रों से मोटी होती जा रही है।

भंवर में भविष्य

150 कॉलेजों का फर्जीवाड़ा पकड़ाया, केस किसी पर नहीं

बड़ा सवाल ये है कि एक ही व्यक्ति की डुप्लीकेट माइग्रेशन नंबर के आधार पर उसे अलग-अलग कॉलेज में काम करना दिखाया गया। ये फर्जीवाड़ा खुलने के बाद भी न तो शासन और न ही नर्सिंग कॉउसिंल ने संचालक और फैकल्टी मेंबर के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई। मप्र में कई जिलों में ऐसे नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं जहां एक ही बिल्डिंग में कई तरह के कॉलेज चलाए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है जिसके बारे में प्रशासन और अफसर बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसर इन कॉलेजों को मान्यता दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भोपाल के रातीबड़ में अखिल भारतीय कॉलेज है। इस कॉलेज में एक ही बिल्डिंग में पांच अलग-अलग तरह के कॉलेज संचालित हैं। हैरानी की बात ये है कि जिन कोर्सों की जानकारी कॉलेज ने दी है, वो कोर्स संचालित हो रहे हैं या नहीं इस बात की पुष्टि के लिए जब भी सरकारी अफसर कॉलेज पहुंचते हैं तो एंट्री गेट पर वही कोर्स संचालित होने का बोर्ड लगा मिलता है, जिसकी जांच होनी है। हर बार यह बोर्ड बदल जाता है। इस कॉलेज की बिल्डिंग में एक साथ पांच कोर्स चलाए जा रहे हैं। जिसमें नर्सिंग, फॉर्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड शामिल है। खास बात यह है कि नर्सिंग कॉलेज के संचालन के लिए यहां पर 100 बेड का अस्पताल होने की बात कही गई है। यह गड़बड़ी केवल इसी कॉलेज ने नहीं की है, बल्कि ऐसी गड़बड़ी कर अन्य कोर्सों का संचालन करने वाले कॉलेजों की संख्या प्रदेश में सैकड़ों में है। अब इसकी जांच राज्य सरकार के अफसर कर रहे हैं।

मप्र का नर्सिंग घोटाला व्यापमं घोटाले से भी बड़ा है। नर्सिंग घोटाला व्यापमं घोटाले के साथ ही शुरू हुआ था, जिस पर सरकार पर्दा डालती रही। कांग्रेस ने इस संबंध में 8 फरवरी 2007 को भी लोकायुक्त को शिकायत की थी और साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे। इसमें भाजपा नेताओं से जुड़े नर्सिंग कॉलेजों की सूची भी उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन लोकायुक्त की जांच किस नतीजे पर पहुंची और किसे दोषी पाया गया, आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री ने यह आरोप लगाए। यह नर्सिंग घोटाला नेताओं, अफसरों और शिक्षा माफिया के कॉकस का नतीजा है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, तत्कालीन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत बरबड़े और **घोटालेबाजों के रिश्तों** की जांच कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। साथ ही आरोप लगाया कि इस घोटाले में काले धन का उपयोग हुआ है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग होने के बावजूद ईडी और सीबीआई खामोश क्यों है। अग्निहोत्री ने बताया कि नर्सिंग घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब व्यापमं घोटाले पर तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को जेल और तत्कालीन राज्यपाल पर एफआईआर हो सकती है तो फिर मौजूदा मंत्री और अफसरों पर एफआईआर क्यों नहीं हो सकती। सरकार इन्हें क्यों बचा रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस तरह के घोटाले को संरक्षण देने के बजाय हाईकोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच सौंपे। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार यदि घोटालेबाजों को इसी तरह संरक्षण देती रही तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी।

ग्वालियर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ग्वालियर-चंबल के 35 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता की जांच कर रही है। इसमें से 10 कॉलेज पहले ही बंद हो चुके है। 25 कॉलेजों के आधे-अधूरे दस्तावेज सीबीआई ने नर्सिंग काउंसिल से जब्त कर लिए हैं। जिस तरह की गड़बड़ी इन कॉलेजों में हुई है, ठीक उसी तरह की गड़बड़ी प्रदेश के 600 नर्सिंग कॉलेजों में सामने आ रही है। इन कॉलेजों में 14 हजार में से 4500 ऐसी टीचिंग फैकल्टी रजिस्टर्ड हैं, जो कागजों में यहां पर पढ़ाने काम करती हैं। ये सारी फैकल्टी बाहरी राज्यों की हैं। इनका माइग्रेशन व रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउसिंल में किया गया है। इसमें से 500 फैकल्टी ऐसी हैं, जिनके माइग्रेशन, पंजीयन नंबरों को एक से अधिक बार फर्जी तरीके से अलग-अलग जनरेट कर प्रदेश के अलग-अलग कॉलेजों में मान्यता प्राप्त करने दर्शाया गया है। कॉलेज संचालकों ने यह धांधली इसलिए की, क्योंकि उन्हें 2020-21 और 2021-22 में नर्सिंग कॉलेज की मान्यता लेनी थी। इसके लिए उन्होंने माइग्रेशन नंबर फर्जी तरीके से जनरेट कर दिए। नर्सिंग काउंसिल ने भी इन फर्जी नंबरों का बिना देखे सत्यापन कर दिया। खास बात ये है कि ये 500 फैकल्टी ऐसी हैं, जिनके एक ही समय पर अलग-अलग कॉलेज संचालकों ने माइग्रेशन नंबर बनाए और एक ही साथ कई कॉलेजों में काम करना दिखाया गया। कई कॉलेजों में एक ही व्यक्ति के 15 तो कई के 18 से ज्यादा बार माइग्रेशन नंबर को अलग-अलग तरीके से जरनेट किया गया। इनको कॉलेजों में फैकल्टी के रूप में दर्ज कराया गया।

कॉलेज संचालकों ने एक ही व्यक्ति का माइग्रेशन नंबर जनरेट करने के लिए उसकी जन्म तारीख को बदल दिया। किसी के मार्कशीट में दर्ज पास होने की साल का नंबर बदल दिया तो कई के नाम और सरनेम को बदलकर उसका माइग्रेशन नंबर जनरेट कर दिया गया। अलग-अलग कॉलेज में एक ही व्यक्ति को अलग-अलग पद पर काम करना दिखाया गया है। लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मप्र के अध्यक्ष विशाल बघेल ने बताया कि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में कुल बाहरी राज्यों के 4500 माइग्रेशन नंबर रजिस्टर्ड हैं। इसमें से 1000 से ज्यादा डुप्लीकेट हैं। हाल ही में हमारी तरफ से 150 से ज्यादा फैकल्टी के डुप्लीकेट नंबरों के दस्तावेज हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच के समक्ष पेश किए गए हैं। एक ही विष्णु कुमार स्वर्णकार के वर्ष 2021-22 में 15 माइग्रेशन नंबर फर्जी तरीके से बनाए गए और पंजीयन कराया गया जिससे कि उसे एक साथ 15 कॉलेजों में कार्यरत दिखाया गया। उसकी जन्म तारीख और सरनेम बदलकर गड़बड़ी की गई। इसी तहर एक लीना नाम की टीचिंग स्टाफ के 18 माइग्रेशन नंबर जनरेट किए गए। कहीं पर उसका नाम सिर्फ लीना लिखा गया तो कहीं पर कुमारी लीना और कहीं पर लीना के अलावा कई सरनेम लिखे गए। उसकी जन्म तारीख को बदल दिया गया। अलग-अलग कॉलेज में उसका पद बदलकर दिखाया गया।

● **राजेश बोरकर**

उमा भारती खुश, जनता नाखुश

मप्र की शिवराज सरकार ने शराब नीति में बदलाव कर भले ही मप्र की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती को खुश करने का प्रयास किया हो, लेकिन मप्र की यह शराब नीति अब आम नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। दरअसल, नई शराब नीति के चलते अहाते बंद कर दिए हैं, तो वहीं स्कूल, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। स्थिति यह है कि अब स्कूल, अस्पताल के पास और रिहायशी इलाकों में शराब पीकर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। इन इलाकों में खुली शराब की दुकानों को लेकर राजधानी भोपाल में जमकर विरोध हो रहा है। लोगों ने शराब दुकानों के सामने ही सुंदरकांड पाठ किया और शराबियों को दूध के पैकेट भी बांटे।

बता दें कि मप्र में 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू हो गई है। इस शराब नीति के अनुसार रिहायशी इलाकों, अस्पताल और स्कूलों के पास शराब की दुकानें नहीं खुलनी थी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। राजधानी भोपाल में ही चार दुकानें ऐसी हैं जो स्कूल, अस्पताल के पास और **रिहायशी इलाकों** में खोली गई हैं। इन दुकानों की वजह से यहां रहने वाले लोग काफी असहज महसूस कर रहे हैं। इन इलाकों में महिलाओं का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इन शराब दुकानों का अब जमकर विरोध भी हो रहा है। लोगों ने शराब की दुकान के सामने ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया तो वहीं शराब की दुकानों पर शराब लेने आए लोगों को दूध के पैकेट बांटे। इतना ही नहीं शराब बेच रहे दुकानदारों को महिलाओं ने विरोध स्वरूप गुलाब के फूल भेंट किए। दरअसल, बीते दो-ढाई सालों से शराब की दुकानों को लेकर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जमकर विरोध दर्ज करा रही थीं। उमा भारती शराब की दुकानों को देखते ही पत्थर मार रही थीं, तो कभी शराब की मधुशालाओं को गौशालाओं में परिवर्तित कर रही थीं। उमा भारती के शराब अभियान को जनता का भी समर्थन मिल रहा था। उमा भारती के आक्रोश को देखते हुए मप्र की शिवराज सरकार ने उमा भारती को 1 अप्रैल से शराब नीति में बदलाव का आश्वासन दिया था। शिवराज सरकार ने किया भी वही, 1 अप्रैल से मप्र में सभी अहाते बंद कर दिए गए तो वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के पास और रिहायशी इलाकों में शराब दुकानें नहीं खोले जाने के निर्देश भी दिए। हालांकि मप्र सरकार के इन आदेशों का सही ढंग से पालन आबकारी विभाग नहीं करा सका। प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही शराब की चार दुकानें गलत स्थानों पर खुल गई हैं।

राजधानी भोपाल में शराब की चार दुकानों का जमकर विरोध हो रहा है। इन दुकानों में शाहजहांनाबाद स्थित रामनगर की शराब दुकान है। वहीं कोलार रोड के नयापुरा क्षेत्र में बीते चार दिन से शराब की दुकान टेंट में चल रही है। यह दुकान मेन रोड से महज 50 फीट की दूरी पर है। इधर करोंद चौराहे के पास भी यही हाल है। रिहायशी इलाके में यहां भी शराब की दुकान शिफ्ट हो गई है। चौथी दुकान शाहपुरा में टेंट और सड़क पर ही शराब बिक रही है। सड़क पर लग रही शराबियों की भीड़ की वजह से आवागमन अवरूद्ध हो रहा है। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों का विरोध लोगों ने धार्मिक रूप से किया है।

भोपाल के पुराना किला (कमला पार्क) की शराब दुकान पहले पॉलीटेक्निक चौराहा स्थित गांधी भवन के सामने और अब किलोल पार्क के पास शिफ्ट करने से फिर विवादों में घिर गई। गत दिनों अस्थायी दुकान बनाने के लिए निगम का अमला मौके पर पहुंचा था, जिसका कार्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और मलेरिया विभाग के कर्मचारियों के साथ रहवासी और पार्षद ने भी विरोध जताया था। उनका कहना था कि जिस जगह शराब दुकान शिफ्ट की जा रही है, उसके पास सरकारी दफ्तर, विसर्जन घाट और रहवासी इलाका है। पार्षद शबिस्ता जकी भी विरोध करने वहां पहुंचीं। मलेरिया विभाग के पास सरकारी बिल्डिंग में शराब दुकान खोलने की तैयारी थी। अस्थायी दुकान बनाने के लिए नगर निगम का अमला भी मौके पर पहुंचा गया था। तभी स्वास्थ्य एवं मलेरिया विभाग के कर्मचारी और रहवासी विरोध में सड़क पर उतर गए। उन्होंने नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस पार्षद और निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी भी शामिल हुईं। उन्होंने दुकान खोलने का कड़ा विरोध जताया। विरोध के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ताकि, कोई हंगामा न हो। मलेरिया विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि यह दुकान न सिर्फ किलोल पार्क और विसर्जन घाट के पास खुल रही है, बल्कि मलेरिया ऑफिस के ठीक सामने है। कर्मचारियों ने बताया कि जिस जगह दुकान बनाई जा रही है, उसके सामने ही मलेरिया विभाग के ऑफिस के दो गेट खुलते हैं। वैक्सीन स्टोर भी यहीं पर है। ऐसे में परेशानी खड़ी हो जाएगी। लोगों ने बताया कि यहां रहवासी इलाका भी है। इसी दुकान को पहले पॉलीटेक्निक चौराहा से 100 मीटर दूर प्रियदर्शनी पार्क के कॉर्नर पर खाली जगह में खोला जा रहा था। इसे लेकर लोगों ने विरोध जताया था। इसके चलते यह दुकान अब मलेरिया ऑफिस के सामने खोली जा रही थी। पूर्व में भी इसी दुकान को कमलापति ब्रिज और मलेरिया ऑफिस के पास शिफ्ट करने की कवायद हुई थी। तब भी विरोध प्रदर्शन हुए थे।

● **अरविंद नारद**

48 गुना अधिक कमाई के लिए खुलवा दी शराब दुकानें

टीन की शेड में दनादन शराब की दुकानें खुल रही हैं। नगर निगम को शराब दुकानों से सामान्य दुकानों की तुलना में 48 गुना ज्यादा कमाई हो रही है। निगम प्रशासन आबकारी विभाग से दुकान आवंटन संबंधी पत्र मिलते ही जगह आवंटित कर देता है। निगम शराब दुकानों के लिए कलेक्टर गाइडलाइन का दो फीसदी किराया प्रतिमाह तय करता है। सामान्य दुकान से ये 48 गुना है। सामान्य दुकान से कलेक्टर गाइडलाइन का 0.5 फीसदी प्रतिवर्ष शुल्क लिया जाता है। कोहेफिजा में स्टेट बैंक चौराहा से शराब दुकान बंद कर दी गई थी। ठेकेदार ने ब्रिज के नीचे टेंट लगाकर शराब बेचनी शुरू कर दी। तब निगम ने ब्रिज के नीचे ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी। नगर निगम ने मनीषा मार्केट के सामने ग्रीन वर्ज में दुकान आवंटित की है। दुकानदारों का विरोध दरकिनार कर दिया गया। पुराने शहर में जीएडी ब्रिज के नीचे दुकान बनवा दी गई। इसी तरह कोलार में टेंट में ही शराब की दुकान खुलवा दी थी, बाद में इसे हटाया गया। हालांकि, बाद में जगह आवंटित की गई।

धर्म की आड़ में सिक रहीं राजनीतिक रोटियां

भारत को भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन आज यह विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है। इस कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसी कई समस्याएं मुंह फैलाए खड़ी हैं। लेकिन विडंबना यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनेता समस्याओं को दूर करने की बजाय धर्म की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बजरंगबली, तो कभी किसी अन्य देवी-देवताओं और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया-भिड़ाया जा रहा है।

● राजेंद्र आगाल

करीब 600 साल पहले कबीरदास ने लिखा था... मौको कहां ढूंढे है रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा-कैलाश में। लेकिन विडंबना यह देखिए कि हमारे देश के लोग आज तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं। यही कारण है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में कभी राम मंदिर के नाम पर राजनीति होती रही, कभी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठा और अब कर्नाटक में तो बजरंगबली को चुनावी मोहरा बना दिया गया। चुनाव में हर बार उठने वाले धार्मिक मुद्दों से ऐसा लगता है कि इस देश में और कोई समस्या नहीं है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में समस्याओं की भरमार है, लेकिन हमारे राजनेता समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने और धर्म के नाम पर सत्ता पाने के लिए धर्म को चुनावी मोहरा बनाते हैं। जबकि कहा गया है कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए।

भारत एक ऐसा महान देश है जहां दुनिया के सभी धर्मों के लोग एक साथ जीवन व्यतीत करते हैं। एकता और एकजुटता इस देश को महान बनाती है। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अगर मोहब्बत के रंग-बिरंगे फूलों को देखना है तो दुनिया के नक्शे पर मौजूद भारत के गुलदस्ते को देखा जा सकता है। लेकिन इधर कुछ दशकों से इस गुलदस्ते की देख-रेख करने वाले मालियों ने इस पर से ध्यान हटा लिया है जिसकी वजह से यह सूखने लगा है। यह वही देश है जो विकास के अधिकतर पैमानों पर अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। यहां 20 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अभी भी अशिक्षित है। 25 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। अमीरों-गरीबों के बीच की खाई का मुंह और फैलता ही चला जा रहा है। यह वही देश है जो अभी-अभी महामारी की एक ऐसी लहर से निकला है जिसने पूरे देश को जैसे एक विशाल श्मशान घाट में बदल दिया था। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसके परिवार, संबंधियों, दोस्तों या परिचितों में से किसी के घर को भी मौत छूकर ना गई हो। लेकिन इन सारी आपदा-विपदा और समस्याओं को दरकिनार कर एक बार फिर से धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सिंकनी शुरू हो गई हैं। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां धर्म को हथियार बनाने में जुट गई हैं, जिसकी शुरुआत कर्नाटक विधानसभा चुनाव से हो गई है।

कट्टरवाद से सभी को नुकसान

वैसे यह बात सच है कि जिस भी धर्म में कट्टरवाद ने सर उठाया है उसने न केवल उस धर्म को नुकसान पहुंचाया है बल्कि पूरे समाज को दीमक की तरह खा गया है। आजकल भारत का भी यही हाल हो रहा है। आम लोगों के सामने जहां पहले से ही रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई ने समस्याएं खड़ी कर रखी थीं वहीं कोरोना महामारी ने तो आम लोगों को बे मौत मार दिया है। लोग दो वक्त की रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस बीच समाज में कुछ कट्टरपंथियों द्वारा घोले जा रहे जहर ने पहले से ही मौत के मुंहाने पर पहुंच चुके लोगों के लिए एक और मौत का कुंआ खोद दिया है। वैसे ऐसी स्थिति उस समय ज्यादा पैदा हो जाती है जब देश या किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में सारे धर्म खतरे में थे, सभी धर्मों के देवी-देवता खतरे में पड़ गए थे, धर्म स्थलों की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा था, हां एक बात है कि लोगों का पेट धर्म की रोटी, नफरत के चावल और चुनाव की बिरयानी से भर रहे थे। इसीलिए तो लोग सारी समस्याओं को भूलकर धर्म और धर्मस्थलों को बचाने में लग गए थे और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही सब सुरक्षित हो गए पर जनता भूखी रह गई।

अब मप्र सहित कई राज्यों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फिर से धर्म, धर्म स्थल और देवी देवता खतरे में पड़ने वाले हैं, लेकिन लोगों का पेट भरने वाला है, लोगों को धर्म और नफरत की रोटी मिलने वाली है और यह

कर्नाटक के चुनाव में छाए रहे बजरंगबली

कर्नाटक में कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीत गई है। वह सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरकर सामने आई है। चुनाव प्रचार के समय दोनों प्रमुख पार्टियों (भाजपा और कांग्रेस) के नेता एक-दूसरे पर बयानबाजी करने से हिचक नहीं रहे थे। कांग्रेस को भी पूरी उम्मीद थी कि वे इस बार कर्नाटक चुनाव में झंडे गाड़ेगी, हुआ भी ऐसा ही। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना। और भाजपा को हार झेलनी पड़ी। उल्लेखनीय है कि चुनाव प्रचार के समय हुई बयानबाजी कांग्रेस की उम्मीद पर पानी फेर सकती सकती थी। ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को लगता है कि चुनाव के समय बहुत सोचकर बोलना चाहिए और फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहिए। वरना वह जीती हुई बाजी हार सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कह कर अपने ही गले में आफत डाल ली थी, लेकिन इससे कर्नाटक की जनता को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने उसे भगवान शिव का सांप कहकर अपने गले में डाल लिया, लेकिन उससे भी भाजपा को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा। वहीं बजरंगबली भी कर्नाटक चुनाव में छाए रहे। दरअसल, कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में एक वादा ये भी किया है कि वो बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करने पर विचार करेंगे। पार्टी की तरफ से बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई। ये मुद्दा कांग्रेस पर बुरी तरह बैक फायर कर गया। भाजपा ने बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया और पूरा मुद्दा भगवान के अपमान पर आ गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान राम के बाद अब ये लोग बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। जिस हिंदुत्व कार्ड को भाजपा सही तरीके से नहीं खेल पा रही थी, इस मुद्दे के बाद उसे खुलकर सामने लाया गया। बजरंग बली के नाम पर ध्रुवीकरण की जमकर कोशिश हुई, लेकिन भाजपा के इस मुद्दे को ज्यादा तवज्जो नहीं मिल सकी और आखिर जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर पर बंध ही गया। वहीं द कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी को लेकर भी जमकर बवाल हुआ, इसे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक प्रोपेगेंडा बताया। चुनाव से ठीक पहले रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से इसका जिक्र किया और कहा कि केरल की असली सच्चाई फिल्म में दिखाई गई है। धर्म परिवर्तन और आईएसआईएस पर बनी इस फिल्म की गूंज चुनावी रैलियो में खूब सुनाई दी। भाजपा ने हिंदुत्व पॉलिटिक्स के एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया। हालांकि बजरंग बली से लेकर भगवान शिव और केरला स्टोरी जैसे मुद्दों का चुनावी नतीजों में खासा असर देखने को नहीं मिला।

क्या वह राजनीति के धर्म का हक अदा कर रहे हैं?

भारत देश जिसने पूरी दुनिया को सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया हो, जिसने विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार किया हो। वह भारत देश जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, जहां की गंगा-जमुनी तेहजीब की दुहाई दी जाती थी, जहां विश्वभर में सब से ज्यादा भाषाएं और धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हों, जहां की एकता और अखंडता इतिहास रचता हो, जहां की सभ्यता को दूसरे देशों में मिसाल बताया जाता हो। दरअसल भारत में राजनेताओं ने राजनीति का धर्म भुलाकर अपनी जिम्मेदारी के कर्ज को अपने से अलग कर दिया है। और धर्म की राजनीति करके देश, राज्य की सत्ता को हथियाकर मुखिया के रूप में आसीन होना चाहते हैं। देश का कोई भी नागरिक चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, किसी धर्म में आस्था रखता हो, उसको देश में किसी भी तरह का दंगा-फसाद, खून-खराबा स्वीकार नहीं होगा। जहां केवल और केवल मानवता और मासूम की जान जाती हो। क्या हम और आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी भावना संवेदना क्यों उन राजनेताओं के हाथों में है जो कभी भी देश में शांति नहीं चाहते। क्यों किसी को हिंदुत्व खतरे में लगता है, किसी को इस्लाम, किसी को ईसाईयत खतरे में लगता है।

रोटियां कोई और नहीं परोसेगा क्योंकि इसको बेहतरीन अंदाज में नेता और न्यूज चैनल स्पेशल थाली में परोसेंगे और जब तक चुनाव चलेगा जनता को एक मिनट के लिए भूखा नहीं रहने देंगे। वैसे यह रोटियां बननी शुरू हो गईं हैं। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जहां राजनीति का आधार शिक्षा, वैज्ञानिक सोच, बराबरी का व्यवहार और जन कल्याण होना चाहिए था, वहां स्वतंत्रता की तीन चौथाई सदी के बाद भी धार्मिकता, जातीयता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता का ही बोलबाला है। राजनीति के इन स्थायी हो चुके आधारों का विश्लेषण करना वर्तमान परिस्थितियों में जरूरी हो गया है।

धर्म का मुद्दा 3 दशक पुराना

देश की राजनीति से धर्म का मुद्दा पिछले तीन दशक से लगातार जुड़ा हुआ है। हालांकि असलियत में इस मुद्दे का सियासीकरण आजादी के एक साल बाद 1948 में ही शुरू हो गया था। तब इतिहास में पहली बार चुनाव में राम मंदिर का इस्तेमाल हुआ था और कांग्रेस ने एक बागी को हराने के लिए हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे थे। तब से लेकर आजतक राम मंदिर पर सियासत उप्र में समय-समय पर हलचल पैदा करती रही है। 1934 में कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी ने जन्म ले लिया था। इसमें राम मनोहर लोहिया से लेकर आचार्य नरेंद्र देव तक शामिल थे। इस वर्ग की मुख्य कांग्रेस से अक्सर टकराव रहती थी। 1948 आते-आते यह खींचतान और बढ़ गई और इस वर्ग ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। इतना ही नहीं सोशलिस्ट धड़े से 13 विधायकों ने उप्र विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। उपचुनाव में फैजाबाद हॉट सीट बन गई थी। यहां से समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव मैदान में थे, जो उन इस्तीफा देने वाले सोशलिस्ट विधायकों में शामिल थे। उस समय गोविंद वल्लभ पंत उप्र के मुख्यमंत्री थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री और सरदार वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री थे। आचार्य नरेंद्र देव फैजाबाद के ही रहने वाले थे और इस क्षेत्र में उनकी जबर्दस्त पकड़ थी। कांग्रेस के लिए उन्हें हराना

भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका एवं प्रभाव

भारतीय राजनीति के निर्धारण में धर्म ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रयोग विभिन्न जातियों में कटुता की भावना पैदा करने के लिए भी किया गया है। दूसरी ओर धर्म का प्रयोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए भी किया गया है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों का निर्माण किया गया है, सांप्रदायिक आधार पर मत मांगे जाते हैं, राजनीतिक निर्णय सांप्रदायिकता के रंग में रंगे होते हैं। मतदाताओं से मत प्राप्त करने की अपील धार्मिक आधार पर की जाती है। विरोधी दलों द्वारा यदि सांप्रदायिकता के विष का वमन किया जाता है तो सत्तारूढ़ दल भी उन्हें सुविधाएं प्रदान करने में किसी से पीछे नहीं है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दलों के संगठन का आधार उनकी विचारधाराएं तथा आदर्श होने चाहिए थे, भारतवर्ष में राजनीतिक दलों का गठन धर्म के आधार पर किया गया। मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, रामराज्य परिषद्, हिंदू महासभा आदि ऐसे ही राजनीतिक दल हैं, जो कि धर्म और सांप्रदायिकता के विघटनकारी आधार पर खड़े हैं। भारतवर्ष में अधिकांश राजनीतिक दल तथा नेता जनता की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं। निर्वाचन के समय धार्मिक आधार पर मत मांगे जाते हैं। वोट बटोरने के लिए मठाधीशों, इमामों, पादरियों और साधुओं से सांठ-गांठ की जाती हैं। सन् 1961 के आम चुनाव में शंकराचार्य, सन् 1977 तथा सन् 1980 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली के शाही इमाम की भूमिका को इस परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से समझा जा सकता है। शाही इमाम ने अपने धार्मिक पद का दुरुपयोग करते हुए एक विशेष राजनीतिक दल को मत देने की अपील राजनीतिक मंच से की। धार्मिक केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिमंडलों का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान अवश्य प्राप्त हो जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, सिक्खों तथा ईसाइयों को अवश्य ही प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है। भारतवर्ष में राज्यों की राजनीति किस प्रकार से धर्म से आच्छादित है इसके लिए पंजाब का उदाहरण ही पर्याप्त होगा, जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते हैं और अकाली दल पंजाब की राजनीति को।

चुनौती बन गया था। तब हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति का जन्म हुआ और आचार्य के मुकाबले कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बाबा राघव दास को खड़ा किया। ये वही राघव दास हैं जिनके नाम पर गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज है। महाराष्ट्र में जन्मे बाबा राघव दास की कर्मभूमि पूर्वी उप्र थी। देवरिया के बरहज कस्बे में उनका आश्रम है। वैसे बाबा राघव दास की पहचान किसी धार्मिक संत की नहीं बल्कि एक गांधीवादी और समाजसेवक की थी। उन्हें पूर्वांचल का गांधी और संत विनोबा के भूदान आंदोलन का हनुमान कहा जाता है।

बाबा राघव दास ने सौगंध ली कि वह राम जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराएंगे। उपचुनाव से पहले अयोध्या में पोस्टर लगे जिसमें आचार्य नरेंद्र देव को रावण की तरह दिखाया गया और कांग्रेस प्रत्याशी बाबा राघव दास को राम की तरह पेश किया गया।

बाबा राघवदास ने जितनी जनसभाएं कीं उसमें उन्होंने खुलकर रामजन्मभूमि के लिए संकल्प लिया और कहा कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो विधर्मियों से अयोध्या को मुक्त कराएंगे। चुनाव हुए और आचार्य नरेंद्र देव महज 1,312 वोटों से हार गए, जबकि राम मंदिर के कार्ड पर खेलते हुए बाबा राघव दास जीत गए। आचार्य नरेंद्र देव को इस चुनाव में 4,080 वोट मिले जबकि राघव दास को 5,392 वोट। यह घटना आज इतिहास में दर्ज है। जब आचार्य नरेंद्र देव हार गए तो राघव दास अपना संकल्प पूरा करने में जुट गए। अयोध्या में साधु-संतों के साथ उनकी एक बैठक हुई। इसके बाद दिसंबर 1949 में बाबा राघव दास और अवैद्यनाथ समेत 5 लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने सरयू में स्नान किया और राम की मूर्ति लेकर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। मस्जिद का ताला खोलकर वहां भगवान राम की मूर्ति रख दी गई और भजन-कीर्तन शुरू हो हुए। अगली सुबह काफी हंगामे भरी रही। अयोध्या में जो कछ हो रहा था, पूरे देश के लिए सनसनीखेज था। उस वक्त केके नायर फैजाबाद के डीएम थे। अयोध्या के हालातों से परेशान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद वल्लभ पंत को पत्र लिखा। इस खत में कड़े शब्दों में कहा गया कि इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता कि वहां पर मूर्ति रख दी गई है। अगर यह सच है तो बहुत गलत चीज है। कांग्रेस तो वहां (उप्र) पर विभाजित है। इस तरह के कदम रोके जाने चाहिए। तत्काल रूप से मूर्तियां हटवानी चाहिए। गोविंद पंत ने पत्र के आधार पर डीएम को मूर्ति हटाने के निर्देश दिए लेकिन केके नायर ने मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया यह कहकर कि मूर्ति हटाई गई तो हिंसा हो जाएगी, खून-खराबा होगा। मामला फंसा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि अयोध्या में बड़ा गलत हो रहा है। इस बार पटेल ने पंत को पत्र लिखा कि प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं और इस मामले का विकल्प देखा जाए। पंत ने डीएम पर दबाव डाला तो केके नायर ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। यहां से हुई थी राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत, जिसे 90 के दशक से भाजपा ने भुनाया और फिर हर चुनाव से पहले यह मुद्दा उभरता गया। लगभग हर दल ने अयोध्या के नाम पर जमकर सियासी रोटियां सेंकी। यानी यह आंदोलन शुरू किसी ने किया, बीच में पकड़ा किसी और दल ने और अब अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है जिसके नाम पर आगामी चुनाव लड़े जा रहे हैं।

मानवता का धर्म

सभी धर्मों से ऊपर जो मानवता का धर्म है उसकी फिक्र किसी को भी नहीं है। कहीं धर्म तो कहीं नस्लवाद की लड़ाई जारी है। भारत में धर्म और नस्लवाद की लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की जनता की आंखें तरस गई इस बात के लिए कि जिस नेता को अपना बहुमूल्य वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया, कभी वो जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरकार से लड़ाई करता, कभी वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सस्ती शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जीवन सुरक्षा के मसले हल न होने के कारण अनशन करता। आज देश के हर कोने में हर धर्म को लेकर बहस छिड़ी हुई है, इस लड़ाई में आज तक अनगिनत जानें जा चुकी हैं और न जाने कितनी और जानें जाती रहेंगी। आज हर कोई मानवता के लिए बड़ी-बड़ी बातें तो करता है, मगर कभी ईमानदारी से उसी मानवता की सेवा के लिए अपनी सोच बदलने की कोशिश की? कभी नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता में व्योहारवाद ही नहीं है। हम एक ऐसे माहौल में जीते हैं जहां परंपराओं को तोडकर उससे आगे की सोचना हमारे आचरण में नहीं है। या अंधविश्वास की बंदिश से आजाद होना हमारे बस में नहीं। यही कारण है कि हम अपने असली धर्म और उसकी परिभाषा को भूल गए हैं। इस समय धर्म की राजनीति को लेकर तमाम सवाल, आरोप-प्रत्यारोप उठ रहे हैं। एक राजनीतिज्ञ को धर्मिक होना जरूरी है। धर्म के बिना समर्थ और सार्थक राजनीति नहीं हो सकती। हमारे राजनीतिज्ञ को राजनीति के धर्म का पालन करना होगा ऐसा न हो कि धर्म की राजनीति की जाए। भारतीय राजनीति के इतिहास में देश की आजादी के बाद से अब तक जिस तरह से देश में राजनेताओं ने राजनीति की है, वह सोचनीय है।

धर्म गोलबंदी का आधार

भारतीय राजनीति में सबसे पहले अपना धर्म आता है जिसे मानता और उसके अनुसार चलता हर कोई है लेकिन दिखलाता यही है कि वह धर्म के आधार पर कतई कोई भेदभाव नहीं करता। इसे कथनी और करनी में अंतर कह सकते हैं। जब बात धर्म की रक्षा करने की आती है तो उसके लिए कैसी भी कुर्बानी देने या कहें कि शरारत करने की छूट मिल जाती है। धर्म को अफीम की संज्ञा दी गई है, अर्थात् धार्मिकता एक ऐसी लत है जो अगर लग जाए तो इंसान उससे अधिक किसी चीज को नहीं मानता। यह जो आज जेलों में बहुत से कथित साधु-संत, महात्मा

अपने दुराचार और बलात्कार तथा हत्या के आरोप में बंद हैं, उनके कट्टर अनुयायी यह मानते ही नहीं कि इन लंपटों का कोई दोष भी है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें धर्म की अफीम चटा दी जाती है और वे उसके नशे से मुक्त नहीं हो पाते। हमारे सभी राजनीतिक दलों के लिए ये लोग बहुत काम के होते हैं और इनसे सांठ-गांठ किए रखना इन दलों के सुनहरे भविष्य की गारंटी है। धार्मिक उन्माद को भड़काना बहुत आसान है, छोटी-सी चिंगारी प्रदेश से लेकर देश तक को दंगों की आग में झुलसा सकती है क्योंकि धर्म है ही ऐसी चीज जो अगर चाहे तो एकता की डोरी को अटूट बंधन में बदल दे और अगर न चाहे तो उसका असर भारत विभाजन की त्रासदी जैसा भी हो सकता है। राजनीति का दूसरा मजबूत स्तंभ जातियों के बीच समन्वय बनाए रखकर जनता को उनकी जाति के आधार पर बांटकर रखने की कला का नाम ही जातीयता है। जात-पात के आधार पर चुनाव लड़ना और जीतने के लिए अपनी जाति को आधार बनाना आजादी के बाद हुए पहले चुनाव से लेकर आज तक बदस्तूर जारी है।

आपने अक्सर देखा होगा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं और उम्मीदवार बनाने की शुरूआत होती है तो जातियों का समीकरण बिठाया जाने लगता है। जातियों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की संख्या के आधार पर प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं। ऐसे नेताओं का दलबदल भी कराया जाता है जिनका उस क्षेत्र में अपनी जाति का वोट बैंक हो। कुछ दल तो जातीयता को ही मुद्दा बनाकर सत्ता पर काबिज हो पाए हैं। ये जातियां भी कमाल की चीज हैं, इनके आगे किसी अन्य योग्यता की जरूरत नहीं रह जाती। अनपढ़, गंवार से लेकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग भी जाति पर अपनी मजबूत पकड़ होने से बार-बार चुने जाते हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में हत्या, बलात्कार, हिंसा भड़काने के आरोपी केवल जातीयता के बल पर ही देश के संविधान रक्षकों और कानून बनाने वालों की जमात में शामिल हो

जाते हैं जबकि उनकी जगह जेल में होनी चाहिए।

राजनीति का तीसरा स्तंभ संप्रदायों के बीच नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना है। हमारे देश में जनता के बीच उनके संप्रदाय के आधार पर विभाजक रेखा बनाए रखकर राजनीति करने का चलन आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था जो कम होना तो दूर, अपनी जड़ें गहरी करता जा रहा है। देखा जाए तो जातीयता और सांप्रदायिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अंतर केवल इतना है कि जाति का दायरा सीमित है और संप्रदाय का बहुत विशाल। राजनेताओं के लिए संप्रदाय के आधार पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाना उनका मूलमंत्र है। क्षेत्रीयता का अर्थ अपने इलाके की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना है, जिसके इशारा करते ही पूरा माहौल बदल जाए अर्थात् कल तक जो आसमान की बुलंदी पर थे, वे धड़ाम से नीचे गिरे दिखाई दें और जिसे कोई जानता तक न हो, उसके हाथों में शासन की लगाम आ जाए। क्षेत्रीय दलों के क्षत्रप राष्ट्रीय दलों के बड़े-बड़े नेताओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। क्षेत्रीयता के दायरे में अधिकतर वे राजनीतिक दल आते हैं, जिनका आधार पारिवारिक होता है। इनका प्रभाव छोटे राज्यों में अधिक होता है और वहां सत्ता का परिवर्तन आम तौर पर दो दलों के बीच होता रहता है। इनका प्रभाव इतना अधिक होता है कि अपने को राष्ट्रीय दल कहने का दंभ भरने वाले इनके आगे पानी भरते दिखाई देते हैं। ये दल जोड़-तोड़ करने में माहिर होते हैं।

क्षेत्रीय दल अपनी सुविधा के हिसाब से किसी से भी गठबंधन कर लेते हैं, उनके लिए सिद्धांत या नीति और यहां तक कि अपनी गरिमा बनाए रखना कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता बशर्ते कि सत्ता सुख में कोई कमी न हो। इस तरह राजनीति के ये चार स्तंभ हमारे देश के राजनीतिक दलों तथा उनके कर्णधारों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। इन्हें देश की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से कोई मतलब नहीं होता। इन चारों स्तंभों की मजबूती का एकमात्र कारण राजनीतिक दलों द्वारा देश में शिक्षा का प्रसार न होने देना है।

धर्म के नाम पर चुकानी पड़ी है बड़ी कीमत

आज जो देश में आपाधापी, अविश्वास, गलाकाट प्रतियोगिता, किसी भी कीमत पर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना और कानून व्यवस्था के स्थान पर जिसकी लाठी उसकी भैंस का वातावरण है, उसका कारण धर्म, जाति, संप्रदाय और क्षेत्रीयता को राजनीतिक दलों द्वारा अपना नीतिगत सिद्धांत बना लेना है। इसमें परिवर्तन होना आवश्यक है वरना डर है कि देश को फिर से कहीं आजादी के पहले वाले हालात में हमारे वर्तमान नेता न पहुंचा दें। धर्म का कार्य है लोगों को सदाचारी और प्रेममय बनाना और राजनीति का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित में काम करना। जब धर्म और राजनीति साथ-साथ नहीं चलते, तब हमें भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और कपटी धार्मिक नेता मिलते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति, जो सदाचारी और स्नेही है, अवश्य ही जनता के हित का ध्यान रखेगा और एक सच्चा राजनीतिज्ञ बनेगा, एक सच्चा राजनीतिज्ञ केवल सदाचारी और स्नेही ही हो सकता है, इसीलिए उसे धार्मिक होना ही है। परंतु राजनीतिज्ञ को इतना भी धार्मिक नहीं होना चाहिए, जो दूसरे धर्मों की स्वतंत्रता और उनकी विधियों पर बंदिश लगाए। राजनीति और धर्म दोनों ही हर वर्ग के जीवन को प्रभावित करने वाले विषय हैं जो कभी भी एक-दूजे से अलग नहीं हो सकते, मगर राजनीति की दशा और दिशा के बारे में सोच बदलने की आवश्यकता है।

दिल्ली-मुंबई की यात्रा होगी सुविधाजनक

जिस राज्य में जितने इंटरचेंज, उसी हिसाब से दिए गए नंबर

एनएचएआई के रीजनल ऑफिसर आरके सिंह का कहना है कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे में जो साइनेज लगाए गए हैं, उनकी नंबरिंग क्रम से रखी गई है। मसलन, राजस्थान से मप्र सीमा में दाखिल होने पर वाहन चालकों को साइनेज पर एमपी-01 लिखा हुआ दिखेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि यह मप्र का पहला इंटरचेंज है। यही सिलसिला प्रदेश के आखिरी इंटरचेंज तक चलेगा और सबसे आखिरी इंटरचेंज का नंबर एमपी-07 रहेगा। ऐसा लोगों को रास्तों की पहचान आसान करने के लिए किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मप्र में बनाए गए हिस्सों के तीन फोटो फेसबुक पर शेयर किए। माना जा रहा है कि जल्द ही वे खुद इस हाईवे पर कार चलाकर इसका ट्रायल लेंगे। इस समूचे प्रोजेक्ट की लंबाई 1350 किलोमीटर और लागत 1 लाख करोड़ रुपए है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का काम तेजी से चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 1300 किलोमीटर से अधिक है और एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। मप्र में 244 किमी का 11 हजार करोड़ से अधिक लागत से बना इसका हिस्सा तैयार हो चुका है और विधानसभा चुनाव से पहले जून अंत तक यातायात दौड़ने लगेगा। मप्र से भी दिल्ली-मुंबई की यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर मप्र में तैयार हुए एक्सप्रेस-वे की जानकारी शेयर की है। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी कहना है कि मप्र से गुजरने वाला 244 का एक्सप्रेस-वे तैयार है। छोटे-मोटे कुछ काम बचे हैं और जून अंत तक यातायात चलने लगेगा। हालांकि इसके एवज में भारी-भरकम **टोल टैक्स** भी चार पहिया वाहन चालकों को चुकाना पड़ेगा। इस एक्सप्रेस-वे पर दो पहिया वाहन यानी मोटर साइकिल, स्कूटर से लेकर ट्रैक्टर का भी प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं फूड प्लाजा, ट्रामा सेंटर के साथ हेलीपेड की सुविधा भी दी गई है, ताकि आपातकालीन सहायता के दौरान एयरलिफ्ट की सुविधा भी मिल सके। इस एक्सप्रेस-वे पर चार पहिया वाहन बस-ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। दिल्ली-मुंबई के बीच दूरी 24 की बजाय 12 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। हालांकि इंदौर से भी इस एक्सप्रेस-वे को सीधे जोड़ने की कवायद चल रही है। देवास से उज्जैन होते हुए गरोठ तक हाईवे बनाया जा रहा है। देवास-गरोठ हाईवे से इंदौर-गरोठ की दूरी भी 190 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं इंदौर-अहमदाबाद हाईवे को भी दाहोत के पास एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की कवायद चल रही है। मप्र में 244 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेस-वे का हिस्सा तैयार हुआ है उस पर 11 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि केंद्र सरकार ने खर्च की है। अभी 31 मार्च तक ही इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जो हो भी गया है। अब केवल कुछ बचे हुए काम शेष हैं और संभवत: विधानसभा चुनाव से पहले ही इसे शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री से भी उद्घाटन कराने की तैयारी है।

मप्र में जो 244 किलोमीटर का दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे गुजरेगा उससे मंदसौर, झाबुआ, रतलाम को जबरदस्त फायदा होगा। सफर तो आसान होगा ही। मगर इससे लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी मुनाफा होगा। खासकर किसानों की फसलें तेजी से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच सकेंगी। झाबुआ में 51, रतलाम में 91 और मंदसौर में 102 किलोमीटर का हिस्सा इस एक्सप्रेस-वे में शामिल है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की खूबसूरत तस्वीरें ट्वीट करते हैं। यह देश का आठ लेन ग्रीन फील्ड अनूठा कॉरिडोर होगा, जिसमें अत्याधुनिक स्वचलित यातायात प्रबंधन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे एक्सप्रेस-वे पर 55 एयर स्ट्रीप बनाई जा रही है, जहां पर फाइटर जेट तक उतारे जा सकते हैं, जिसका सफल परीक्षण भी कुछ समय पूर्व सफलतापूर्वक कर लिया गया है।

केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का मप्र में करीब 244 किलोमीटर लंबा हिस्सा तैयार कर लिया गया है, जिसमें से केवल सात जगह इंटरचेंज बनाए गए हैं। इन्हीं इंटरचेंज की मदद से वाहन चालक एक्सप्रेस-वे में दाखिल हो सकेंगे और बाहर निकल सकेंगे। जहां से वे एक्सप्रेस-वे में दाखिल होंगे, वहां से टोल टैक्स लगना शुरू होगा और जहां से वाहन चालक एक्सप्रेस-वे से बाहर निकलेंगे, वहां तक के सफर का टोल टैक्स उनके अकाउंट से काट लिया जाएगा।

मप्र में यह हाईवे मंदसौर, रतलाम और झाबुआ जिलों से होकर गुजरेगा। मप्र में इसके निर्माण पर लगभग 11120 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस हाईवे में बनाए गए सात इंटरचेंज को पहचान के लिए एमपी-01 से लेकर एमपी-07 का नाम दिया गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) इससे पहले राजस्थान वाला हिस्सा बनाकर तैयार कर चुका है। अब मप्र की बारी है और यहां भी इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो गया है। फिलहाल फिनिशिंग वर्क चल रहे हैं, जिन्हें 31 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीतामऊ और गरोठ के पास बिजली की हाईटेंशन लाइन हटाई जा चुकी है। साथ ही सीतामऊ में ही चंबल नदी पर 400 मीटर लंबे 8 लेन चौड़े पुल की स्लैब भी डाली जा चुकी है। अब पुल समेत अन्य जगहों पर फिनिशिंग वर्क हो रहे हैं।

● **बृजेश साहू**

क्या रुकेगी हेट स्पीच?

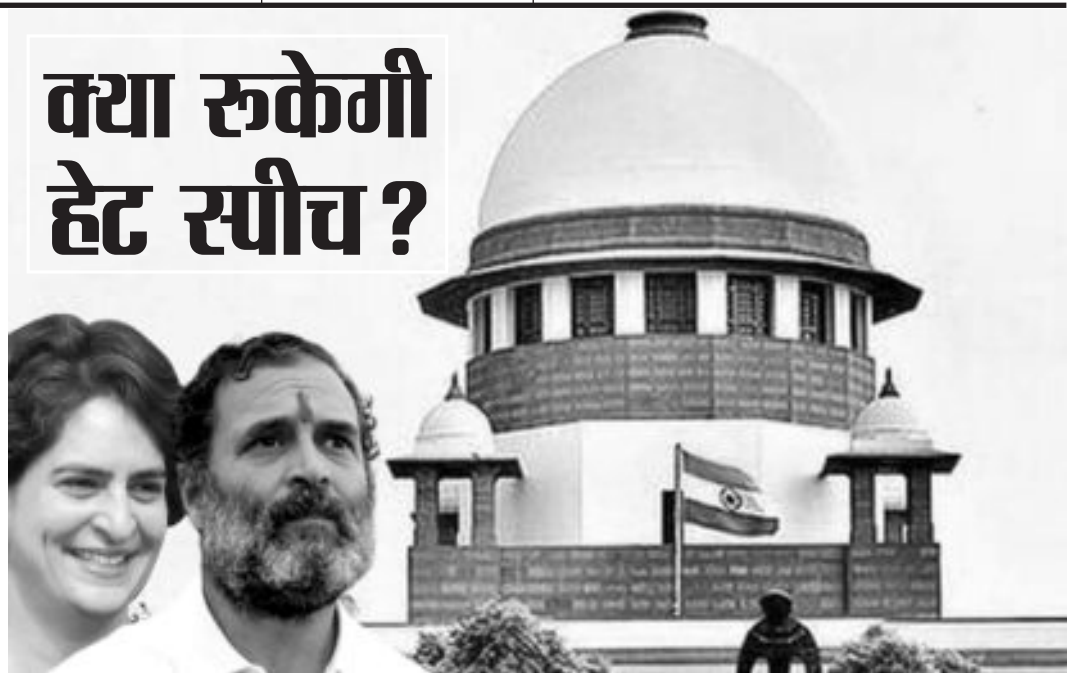

एक कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, और खाने के लिए कुछ और होते हैं। इसी तरह देश में जो ज्यूडिशियरी है वह भी आपस में बंटी हुई है। यह दिखता नहीं है लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया का बेल लगा तो अभिषेक मनु सिंघवी 50 लाख रुपए लेकर खड़े हो गए एक ही दिन में हियरिंग हो गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो तो ठीक है लेकिन इस पर कितनी कार्रवाई होगी यह कह पाना बहुत मुश्किल है।

सुप्रीम कोर्ट का 28 अप्रैल को आया हुआ फैसला हेट स्पीच पर रोक लगाने में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के मामलों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल एक्शन लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के एफआईआर दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा- ऐसे मामलों में कार्रवाई करते हुए बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और **केंद्र शासित प्रदेशों** को यह निर्देश दिए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उप्र, दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को ये आदेश दिया था।

अदालत ने यह भी कहा कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं? यह दुखद है। न्यायाधीश गैर-राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है और उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट देश के विभिन्न हिस्सों से दाखिल हेट स्पीच से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पहले पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर नफरत फैलाने वाले बयान देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, उप्र और उत्तराखंड की सरकारों को ऐसे मामलों में बिना शिकायत के केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने आज अपने आदेश का दायरा बढ़ा दिया है।

इससे पहले मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा था कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? उनकी यह भी राय है कि जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे। नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे। उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हम अपने हालिया फैसलों में भी कह चुके हैं कि पॉलिटिक्स को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा, वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर-दराज से इकट्ठा होते थे। हम

प्रियंका भी किसी से कम नहीं

प्रियंका वाड्रा तो सबसे आगे निकल गई हैं। उन्होंने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी गाली खाना सीख लें, क्योंकि कांग्रेसी उन्हें गाली देना बंद नहीं करेंगे। कर्नाटक की ही एक जनसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की खिल्ली उड़ाई है कि कांग्रेस उन्हें गालियां निकालती है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी 91 गालियों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, जबकि सार्वजनिक जीवन में गालियां खाने की हिम्मत रखनी चाहिए। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे भाई से कुछ सीखें, जो 10 साल से सारे देश से गालियां खा रहा है, लेकिन अभी भी राजनीति में डटा हुआ है। अब वह अपने भाई की हिम्मत की दाद दे रही थी या उनकी भी खिल्ली उड़ा रही थीं, यह समझने वाली बात है। अपने भाई की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा भाई देश की खातिर गोली खाने को भी तैयार है, उनके सारे परिवार ने गोलियां खाईं। लेकिन नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं। वह आपका दुख सुनने के बजाय अपना दुख बताते हैं। उनके इस बयान से भाई-बहन की राजनीतिक परिपक्वता का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है कि कौन 19 है और कौन 20।

कहां जा रहे हैं? लॉ के मुताबिक, जस्टिस केएम जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, राज्य नपुंसक हैं। वे समय पर काम नहीं करते। जब राज्य ऐसे मसलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का मतलब क्या है। पिछले कुछ सालों से देश में हेट स्पीच देने का चलन तेजी से बढ़ा है। समाज के घृणा फैलाने वाले बयान देकर नेताओं का प्रयास अपने समाज के वोटर का रिझाना होता है। एक छोटे से हित के लिए ये नेता भूल जाते हैं कि वे समाज के पारस्परिक सौहार्द को खराब कर रहे हैं। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद भाजपा के कुछ छुटभैया नेता बेलगाम नजर आए। उनके मन में जो आया, वह कहा। इसे लेकर कई जगह पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई। महाराष्ट्र में तो शिवसैनिक नफरती बयान देने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं।

कांग्रेस में भीतर ही भीतर एक मंथन चल रहा है कि अगर विपक्षी दलों को राहुल गांधी के नाम पर ऐतराज है, तो प्रियंका वाड्रा का नाम आगे किया जाए। यह सुझाव बुरा नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा को एक दशक से तुरुप का पत्ता बताते रहे हैं, शायद अब यह तुरुप का पत्ता चलने का वक्त आ गया है। लेकिन शायद कांग्रेसी खुद भूल गए हैं कि यह तुरुप का पत्ता वे पहले चल चुके हैं। उप्र विधानसभा चुनाव से पहले यह फीलर फेंका गया था कि प्रियंका वाड्रा कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। तब एक पत्रकार ने उनसे ही पूछ लिया था कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिवा कोई और दिखता है क्या? यह खुद उनकी तरफ से जनता में फेंका गया फीलर था, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने कुछ दिन बाद खुद कह दिया था कि वह तो मजाक कर रहीं थी। वह मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं हैं, तो यह तुरुप का पत्ता चला जा चुका है। एक समय था जब प्रियंका कांग्रेस में सक्रिय नहीं थीं, और राहुल गांधी राजनीति में पिट रहे थे, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस समर्थक मीडिया उन्हें कांग्रेस का तुरुप का पत्ता बताया करते थे। अब जब प्रियंका वाड्रा पिछले 5 साल से कांग्रेस में सक्रिय हैं, लोगों ने प्रियंका को देख सुन लिया है। अब लोग राहुल और प्रियंका की तुलना करते हैं, तो राहुल को बेहतर पाते हैं।

राहुल गांधी 15 साल से राजनीति में हैं, और उन्होंने काफी कुछ सीखा है। हालांकि अपने विरोधियों के बारे में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसमें दोनों 19-20 ही हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए खून का दलाल, चौकीदार चोर और सारे मोदी चोर कहकर अपना नाम कमा चुके हैं। चोकीदार चोर के मुद्दे पर तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मोदी को चौकीदार चोर कहा था। बाद में सारे मोदी चोर कहकर बुरी तरह फंस गए हैं और अब अदालतों के चक्कर काट रहे हैं।

गाली-गलौज कांग्रेस की भाषा में शामिल हो चुका है। हालांकि यह उनकी पारिवारिक विरासत नहीं है, क्योंकि वे खुद को फिरोज गांधी के वारिस नहीं मानते, खुद को नेहरू और इंदिरा परिवार के वारिस मानते हैं, इसलिए उस परिवार से उनकी तुलना करनी चाहिए। नेहरू और इंदिरा गांधी ने अपने विरोधियों के लिए गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। गाली-गलौज की भाषा सोनिया गांधी से शुरू हुई, जिनकी परवरिश इटली में हुई है। सोनिया गांधी ने सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। 2002 के दंगों पर बिना किसी अदालत का फैसला आए सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कह दिया था, जबकि किसी हत्यारे को भी तब तक हत्यारा नहीं कह सकते, जब तक उस पर आरोप साबित न हो जाए। इससे पहले सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। संसद सत्र के सत्रावसान पर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता का भाषण हुआ करता था, उसे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि विपक्ष की नेता के नाते समापन भाषण की मर्यादा भी सोनिया गांधी ने तोड़ दी थी। सोनिया गांधी की यह परंपरा कांग्रेस में दिन दोगुनी, रात चौगुनी प्रगति कर रही है। कांग्रेस का हर नेता हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा है। जब-जब कोई नई गाली निकाली जाती है, तब-तब लोग पुरानी बातें भी याद करते हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को जहरीला सांप कह दिया। इससे पहले गुजरात विधानसभा के चुनाव में उन्होंने मोदी को रावण कह दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी नेताओं की बदजुबानी को भुनाने का मौका क्यूं चूकें, सो वह हर बार उस मौके को भुनाते हैं। इस बार भी कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में उन्होंने बताया कि कांग्रेसियों ने उन्हें अब तक 91 गालियां निकाली हैं। कांग्रेस को हर चुनाव में मोदी के बारे अपशब्द कहना भारी पड़ता है। लेकिन अपनी गलतियों से कोई सबक नहीं सीखती।

● **विपिन कंधारी**

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का दिखेगा असर?

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए और 505 के तहत इस तरह का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई राजनेता धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव को बिगाड़ने के लिए प्रतिकूल भाषण बाजी करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज होगा। जहां तक सवाल सजा देने का है तो कानून में तो सभी के लिए एक तरह का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा के अंतर्गत किसी भी आरोपित व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या फिर कोई गरीब सबके लिए एक ही तरह की सजा का प्रावधान होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद भी हेट स्पीच का मामला कम नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर कानून कहता है कि अगर किसी को तीन साल की सजा से एक भी दिन ज्यादा की सजा होती है तो उसे पुलिस की कस्टडी में लिया जाएगा। लेकिन यही अगर वीआईपी व्यक्ति के मामले की बात होती है तो यह नहीं होता है। आप सलमान खान का मामला ले लीजिए, उन्हें 5 साल की सजा सुनाई जाती है लेकिन फिर भी उन्हें पुलिस की कस्टडी में नहीं लिया जाता है। आप इससे समझ सकते हैं कि जो लोगी वीआईपी हैं उनके लिए अगल ही कानून है अपने देश में। कहने का मतलब यह है कि दिखाने के लिए कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं लेकिन वीआईपी और राजनीतिक लोगों के लिए अलग है।

उच्च जातियों को बड़े विभाग

8 भाजपा शासित राज्यों में मंत्रिमंडलों का अध्ययन करने से पता चलता है कि मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलितों और ओबीसी का प्रतिनिधित्व सांकेतिक है, जहां भाजपा सत्ता में भागीदार है। पोर्टफोलियो में वे महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्सर कहा है कि 'सबका साथ-सबका विकास' केवल एक नारा नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए एक प्रतिबद्धता है। और पहली नजर में ऐसा लगता भी है कि पार्टी सत्ता में कई महत्वपूर्ण पदों पर पिछड़ी जातियों के लोगों को बिठाकर बस यही कर रही है। हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, या उसके द्वारा शासित राज्यों की शक्ति संरचना पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि सरकार में निचली जातियों के नेताओं का प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक ही है।

भाजपा शासित 8 राज्यों का विश्लेषण और जहां पार्टी सरकार में भागीदार है (इनमें कर्नाटक राज्य की बोम्मई कैबिनेट को भी शामिल किया गया है।), वे सभी राज्य जहां जाति राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उससे पता चलता है कि इसकी बहुप्रचारित नारे के बावजूद, जो लोग मुख्य पदों पर हैं वे उच्च जातियों के हैं। या वे एक प्रमुख जाति या समुदाय से संबंधित हैं, जो एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास, जिन्हें अक्सर इस शब्द की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, ने एक प्रमुख जाति को परिभाषित किया कि जो अन्य जातियों पर संख्यात्मक रूप से प्रबल होती है, और जब यह आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का भी इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा, एक बड़ा और शक्तिशाली जाति समूह अधिक आसानी से प्रभावी हो सकता है यदि स्थानीय जाति पदानुक्रम में इसकी स्थिति बहुत कम नहीं है।

किसी कैबिनेट में मुख्यमंत्री के पद के बाद गृह विभाग को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पुलिस को नियंत्रित करता है। यह प्रशासन में एक शक्तिशाली साधन माना जाता है। वित्त मंत्रालय हर मंत्रालय के लिए परिव्यय तय करता है और इसलिए इसकी बहुत मांग की जाती है। इसी तरह, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो माना जाता है क्योंकि सभी सड़क और एक्सप्रेसवे निर्माण, जो कि विकास के प्रतीक हैं, इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। राजस्व एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह भूमि से जुड़े मामलों से संबंधित है और भूमि किसी भी राज्य में सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। एक अन्य महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो स्वास्थ्य है, क्योंकि इसके पास मेडिकल कॉलेजों और प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों का नियंत्रण है, जो पारंपरिक रूप से भारी बजट आवंटन प्राप्त करते हैं।

विश्लेषण किए गए 8 राज्यों में 123 कैबिनेट मंत्रियों में से, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, 82 उच्च या प्रभावशाली जातियों से हैं और शेष

दलितों, आदिवासियों के पास क्या है?

दलितों और पिछड़ी जाति के मंत्रियों के पास छोटे पोर्टफोलियो हैं। उप्र में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो लोकसभा में 80 विधायक भेजता है, 18 सदस्यीय कैबिनेट में केवल एक दलित मंत्री है और वह हैं बेबी रानी मौर्य, जो महिला और बाल विकास का पोर्टफोलियो रखती हैं। ओबीसी नेता संजय निषाद के पास मत्स्य पालन का प्रभार है। राकेश सचान, एक कुर्मी (ओबीसी), सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम उद्योग मंत्रालय, उनके पास हैं, और अनिल राजभर (ओबीसी) श्रम और रोजगार मंत्री हैं। लोध जाति (ओबीसी) के धर्मपाल सिंह के पास पशुपालन है, जबकि लक्ष्मी नारायण चौधरी, एक जाट (उप्र में ओबीसी) के पास चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, एक अन्य ओबीसी मंत्री, ग्रामीण विकास रखते हैं। उत्तराखंड में दो दलित कैबिनेट मंत्री हैं- रेखा आर्य, जो महिला और बाल कल्याण, और खाद्य आपूर्ति देखती हैं, और चंदन राम दास, जिनके पास परिवहन, सामाजिक कल्याण और एमएसएमई हैं। हरियाणा में एक दलित कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हैं, जिनके पास अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभार है। गुजरात में एक आदिवासी कैबिनेट मंत्री, कुबेरभाई मनसुखभाई डिंडोर हैं, जिनके पास आदिवासी विकास और प्राथमिक, माध्यमिक और वृद्धावस्था शिक्षा का प्रभार है। मप्र में दो दलित मंत्री और तीन आदिवासी मंत्री हैं। तुलसी सिलावट के पास जल संसाधन, मत्स्य एवं मत्स्य विकास तथा प्रभुराम चौधरी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख हैं। बिसाहूलाल सिंह और मीना सिंह, दोनों एसटी, क्रमशः खाद्य आपूर्ति और एससी-एसटी कल्याण विभाग देखते हैं, जबकि कुंवर विजय शाह, एसटी, वन विभाग संभालते हैं। गोवा में, एसटी मंत्री गोविंद गौडे खेल, कला और संस्कृति और ग्रामीण विकास को संभालते हैं।

41 निचली जातियों, अनुसूचित जातियों (एससी), दलित, ओबीसी या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से हैं। इनमें कर्नाटक राज्य की बोम्मई कैबिनेट को भी शामिल किया गया है। जहां हाल ही में कांग्रेस को बहुमत मिला है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ओबीसी से आते हैं, क्योंकि राज्य में लिंगायतों को पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन लिंगायत, अपने सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव के मामले में, राज्य में एक प्रमुख समूह हैं। इसी तरह, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री के पद के अलावा, सभी बड़े पोर्टफोलियो उच्च जाति के सदस्यों के पास हैं। जबकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समय लगता है, दूसरों का मानना है कि पिछड़ी जातियां अभी तक उस चरण तक नहीं पहुंची हैं जहां वे बातचीत कर सकें और साथ ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सत्ता साझा करने में समय लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोशल इंजीनियरिंग राजनीति का एक संक्रमण है। सशक्तिकरण की प्रक्रिया में समय लगता है। धीरे-धीरे सत्ता शिफ्ट होगी और लोकतांत्रिक तरीके से बंटेगी। इसे रातोंरात नहीं किया जा सकता है। जब आरक्षण को संस्थागत रूप दिया गया, तो सामाजिक न्याय के माध्यम से पिछड़े समुदायों को धीरे-धीरे सशक्त किया गया। राजनीति में काफी मंथन हुआ है और यह आने वाले समय में भी जारी रहेगा।

8 मुख्यमंत्रियों में से छह ऊंची या दबंग जातियों से हैं। केवल मप्र के शिवराज सिंह चौहान ओबीसी से हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, एक लिंगायत (ओबीसी) हैं - जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, राज्य में एक प्रमुख समूह है। महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (बालासाहेबंची शिवसेना पार्टी के नेता, सरकार में भाजपा के सहयोगी) एक मराठा (उच्च जाति माना जाने वाला समुदाय) हैं, उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण हैं। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी राजपूत हैं, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर खत्री हैं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल पाटीदार हैं और गोवा के प्रमोद सावंत मराठा हैं। कैबिनेट में सबसे अधिक मांग वाले विभागों को रखने वालों पर एक नजर डालने से कोई आश्चर्य नहीं होता है। राज्यों में गृह मंत्रालय प्रमुख या उच्च जातियों के पास है। उप्र, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में गृह मंत्रालय संबंधित मुख्यमंत्रियों के पास है। हरियाणा के अनिल विज पंजाबी खत्री हैं, जबकि मप्र के नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण हैं।

यह वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे अन्य प्रमुख विभागों के लिए समान है। केवल मप्र में, दलित नेता प्रभुराम चौधरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मिला है। हालांकि माना जाता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके जुड़ाव के कारण उन्हें यह मिला है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालत भी बेहतर नहीं

यह प्रवृत्ति मोदी सरकार के केंद्रीय नेतृत्व में भी झलकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोध गाघची हैं, जो ओबीसी हैं। हालांकि, अन्य सभी महत्वपूर्ण विभागों, जैसे कि रक्षा, वित्त, गृह और सड़क मार्ग, उच्च जाति के सदस्यों के पास हैं। 28 सदस्यीय कैबिनेट में केवल दो दलित मंत्री हैं- वीरेंद्र कुमार जिनके पास सामाजिक न्याय मंत्रालय है, और पशुपति कुमार पारस जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रमुख हैं। राजनाथ सिंह (रक्षा), नरेंद्र सिंह तोमर (कृषि), गिरिराज सिंह (ग्रामीण विकास), अनुराग ठाकुर (सूचना और प्रसारण) और गजेंद्र शेखावत (जल संसाधन) सभी राजपूत हैं। एस जयशंकर (विदेश मामले), निर्मला सीतारमण (वित्त), नितिन गडकरी (सड़क और परिवहन), प्रह्लाद जोशी (कोयला और संसदीय मामले), और महेंद्र नाथ पांडे (भारी उद्योग) सभी ब्राह्मण हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डीआर साहू ने कहा, पिछड़ी जातियां अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंची हैं जहां वे सत्ता के लिए बातचीत कर सकें। हालांकि वे आ गए हैं, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि अधिक लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता साझा करने के लिए मजबूर करने में समय लगेगा। यह केवल उन जगहों पर है जहां आरक्षण अनिवार्य है जैसे संस्थानों में, नौकरियों के लिए, पिछड़े वर्गों ने पैर जमाए हैं, लेकिन जहां राजनीतिक दल या सत्ता संरचना में कोई आरक्षण नहीं है, वहां सत्ता उच्च या प्रमुख जातियों के पास रहती है।

वित्त मंत्रालय, सबसे अधिक मांग वाले विभागों में से एक है। किसी भी राज्य में शायद ही किसी पिछड़ी जाति के नेता के पास वित्त मंत्रालय है। कर्नाटक में बोम्मई के पास यह मंत्रालय था, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि लिंगायत राज्य में एक प्रमुख समूह हैं। हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में खुद यह पोर्टफोलियो रखते हैं। उप्र के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खत्री हैं। ब्राह्मण कनुभाई मोहनलाल देसाई गुजरात में पोर्टफोलियो रखते हैं और उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल एक वैश्य हैं। सिर्फ मप्र के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से हैं।

जहां तक पीडब्ल्यूडी की बात है, मप्र और उप्र दोनों में यह ब्राह्मण के पास है- क्रमश: गोपाल भार्गव और जितिन प्रसाद। सतपाल महाराज, एक राजपूत उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में सेवारत हैं, जबकि गुजरात के मुख्यमंत्री उस राज्य में पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है। गोवा में एक ईसाई नीलेश कैबरल इसे संभालते हैं।

उप्र, उत्तराखंड और गुजरात में, राज्य के मुख्यमंत्री ही राजस्व मंत्रालय भी संभालते हैं। मप्र में, गोविंद राजपूत, एक राजपूत राजस्व मंत्रालय संभालते हैं। गोवा के राजस्व मंत्री अतानासियो मोनसेरेट ईसाई हैं। भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जजपा) के दुष्यंत चौटाला के पास हरियाणा में यह पोर्टफोलियो है। वह एक जाट हैं, जो हरियाणा में ओबीसी का दर्जा मांगने वाला एक प्रमुख समूह है। महाराष्ट्र में फडणवीस के पास गृह, वित्त, ऊर्जा और जल संसाधन सहित कुल नौ विभाग हैं। शिंदे के पास शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी और 11 अन्य मंत्रालय हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल, एक अन्य मराठा, राजस्व मंत्रालय संभालते हैं, जबकि पूर्व भाजपा राज्य प्रमुख चंद्रकांत पाटिल भी एक मराठा हैं, जो उच्च शिक्षा और संसदीय मामलों के विभागों को संभालते हैं। गिरीश महाजन कैबिनेट में एकमात्र ओबीसी हैं और उनके पास चिकित्सा शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग हैं।

● इन्द्र कुमार

छत्तीसगढ़ में दलबदल

राजनीति की पढ़ाई में दो शब्द आते हैं- राजनीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान। फिलहाल हम इन दोनों की पढ़ाई या परिभाषा में नहीं जा रहे। हम तो राजनीति के मौसम विज्ञान की बात कर रहे हैं। मौसम में बदलाव तो आप देख ही रहे हैं। उसी तरह राजनीति के मौसम में भी एक बदलाव हुआ है, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में जोरों पर है। यह चर्चा है नंदकुमार साय के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में साय कद्दावर नेता हैं। साय तीन बार विधायक, तीन बार सांसद, दो बार राज्यसभा के सांसद और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। अविभाजित मप्र और छत्तीसगढ़ बनने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

साय लंबे समय से भाजपा में उपेक्षित थे, यह उनका आरोप है। हालांकि भाजपा का कहना है कि ऐसी कौनसी ऐसी जिम्मेदारी है, जो उन्हें पार्टी ने नहीं दी। इसके बाद उपेक्षा का आरोप गलत है। यहां मौसम विज्ञान की बात करें तो साय 77 साल के हो चुके हैं। भाजपा नए चेहरों को मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसमें 70 प्लस को चुनाव नहीं लड़ाने की भी बात शामिल है। ऐसे में भाजपा में उन्हें और मौका मिलने की उम्मीद कम ही थी, इसलिए वे कांग्रेस चले गए। वे खुद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे, लोगों में इस बात की भी चर्चा है कि वे अपने बेटे के लिए टिकट मांग सकते हैं। खैर, साय के कांग्रेस जॉइन करने के बहाने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में दलबदल करने वाले नेताओं के भविष्य को लेकर बहस छिड़ गई है। विद्याचरण शुक्ल से लेकर अरविंद नेताम और दर्जनभर वे विधायक भी जो जोगी शासन में भाजपा से कांग्रेस में गए थे। विद्याचरण शुक्ल छत्तीसगढ़ के ऐसे नेता हैं, जो राजनीति के शिखर पर भी रहे और दलबदल के कारण किनारे भी कर दिए गए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में उन्हें नंबर-2 माना जाता था। उनके रहन-सहन और शैली को लेकर कई किस्से हैं, लेकिन आज बात करेंगे दल बदलने पर। विद्याचरण शुक्ल, जिन्हें उनके समर्थक विद्या भैया कहकर बुलाते थे, सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर जन मोर्चा में गए। जनमोर्चा से जनता दल, फिर कांग्रेस में वापसी की। इसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से दुखी होकर एनसीपी का गठन किया। इसके बाद भाजपा में गए और अंत में कांग्रेस लौट आए। 2 अगस्त 1929 को उनका जन्म हुआ था। 11 जून 2013 को उनका निधन हो गया। झीरम घाटी कांड में उन्हें गोली लगी थी। आदिवासी नेताओं में अरविंद नेताम भी कद्दावर रहे। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। ऐसे मंत्री जो इंदिराजी से भी बस्तर के मुद्दों पर लड़-भिड़ जाते थे। इंदिरा गांधी उन्हें सुनती भी थीं और उनकी बातों को मानती भी थीं। इतना होने के बाद भी नेताम कभी खुद पार्टी छोड़कर गए तो कभी उन्हें निकाल दिया गया। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नेताम ने 1998 में कांग्रेस छोड़कर बसपा जॉइन की। फिर 2002 में एनसीपी चले गए। इसके बाद 2007 में लौटे, लेकिन पहले जैसा मान-सम्मान नहीं रहा। राष्ट्रपति चुनाव में पीए संगमा का समर्थन किया, जिसके कारण पार्टी से निकाले गए। 2012 में संगमा की पार्टी एनपीपी में गए। इसके बाद कांग्रेस में वापसी की। इस बीच में कुछ दिन भाजपा में ही रहे। हालांकि उनकी राजनीति हाशिये पर ही रही, जबकि सामाजिक स्तर पर उनका प्रभाव है।

छत्तीसगढ़ के नामी संत और कवि पवन दीवान भी ऐसे नाम हैं, जो अपने ज्ञान के साथ-साथ दलबदल के लिए भी चर्चित रहे। वे 1977 में जनता पार्टी से विधायक बने और मंत्री भी बनाए गए। 1980 में वे जनता पार्टी से अलग हो गए और खुद की छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया। मप्र में अर्जुन सिंह की सरकार थी, तब वे कांग्रेस में चले गए थे। बाद में सांसद भी बने। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले वे भाजपा में चले गए। 2012 में कांग्रेस में लौटे, लेकिन बाद में फिर भाजपा में चले गए। दलबदल करने वालों में एक और नाम उल्लेखनीय है। भारत रत्न अटलबिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला भाजपा से दो बार विधायक और एक बार सांसद रहीं। वे भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनीं। 2013 में उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली। इसके बाद 2014 में कांग्रेस ने उन्हें बिलासपुर से लोकसभा की टिकट दी। वहां हार हुई। इसके बाद 2018 में राजनांदगांव से डॉ. रमन सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ीं। इस बार भी हार का मुंह देखना पड़ा था। करुणा शुक्ला से जुड़े भाजपा के नेता याद करते हैं कि कभी उन्होंने अपनी करीबी हेमलता चंद्राकर के लिए एक फोन किया था और उन्हें समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। हालांकि वे खुद उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाईं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले भी नेता

छत्तीसगढ़ में ताराचंद साहू और अजीत जोगी जैसे नेता भी हैं। भाजपा के सांसद रहे साहू ने अपनी पार्टी छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच का गठन किया था। हालांकि वे सफल नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई। 5 विधायक भी जीते, लेकिन 2023 का चुनाव आते-आते अब 5 में दो ही बचे। मरवाही में खुद जोगी की सीट हाथ से निकल गई। इसके बाद खैरागढ़ में देवव्रत सिंह के निधन के बाद उपचुनाव में यह सीट भी चली गई। लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब डॉ. रेणु जोगी और प्रमोद शर्मा ही पार्टी में हैं। जोगी के निधन के बाद पार्टी की स्थिति भी पहले से कमजोर हो चुकी है। वैसे दल बदलने वालों में वर्तमान में भाजपा के विधायक सौरभ सिंह भी हैं। उनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा था। वे कांग्रेस से बसपा में गए और विधायक बने। इसके बाद भाजपा में आ गए। बसपा की विधायक रहीं कामदा जोल्हे अब भाजपा में हैं। धर्मजीत सिंह कांग्रेस से जोगी कांग्रेस में गए। उनके भाजपा और कांग्रेस दोनों में शामिल होने की चर्चा होती रहती है। इसी तरह बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा को लेकर भी चर्चाएं होती हैं। इस पूरे मसले पर पॉलीटिकल साइंस के प्रोफेसर डॉ. अजय चंद्राकर का कहना है कि छत्तीसगढ़ में दलबदल के मिश्रित प्रभाव देखने को मिले हैं। विद्याचरण शुक्ल या अरविंद नेताम दलबदल के बाद बड़े कैनवास पर नहीं उभर पाए लेकिन महेंद्र कर्मा ऐसे नेता थे, जो नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तरुण चटर्जी जैसे नेताओं का प्रभाव घट गया। हालांकि डॉ. शक्राजीत नायक अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जहां तक नंदकुमार साय की बात है तो उनकी छवि बड़ी है। पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, इसलिए वे कांग्रेस में आए। भाजपा के लिए यह क्षति है।

आखिर क्या पका रहे पवार?

शरद पवार रोटी पलट रहे हैं। शरद पवार रोटी पलटते रहते हैं। मगर पवार की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि पवार की राजनीतिक थाली की ये आखिरी रोटी नहीं है। तो फिर पक क्या रहा है? या आधी रोटी कहां तक सिक गई है। वैसे तो शरद पवार के दिमाग को पढ़ पाने वाले कोई भी राजनीतिक पंडित नहीं हुए हैं, मगर यह भी दुनिया की सच्चाई है कि जिस खेल को आप हर बार खेलते आ रहे हैं वो खेल आपके साथ भी हो सकता है। जग जीता हुआ इंसान अपनों से हार जाता है। अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि भतीजे अजित पवार वही खेल खेल रहे हैं जो खेल चाचा शरद पवार खेलते आ रहे हैं या चाचा-भतीजा साथ मिलकर खेल रहे हैं।

वैसे देखा जाए तो पवार रोटियां पलटने के माहिर खिलाड़ी हैं। पवार ने पहली रोटी तब पलटी जब कांग्रेस दो टुकड़ों में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने तय किया कि जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस के दोनों धड़े मिलकर सरकार बनाएंगे। शंकर राव चव्हाण मुख्यमंत्री के पद से हटे और वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। मगर पवार की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। उन्होंने अपने गुरू यशवंतराव चव्हान को आगे किया और 1978 में कांग्रेस (आई) फिर से टूटकर कांग्रेस (उर्स) बनी। पवार जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस (उर्स) की तरफ से 38 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पवार के गुरू यशवंत राव चव्हाण को अपनी गलती का अहसास हो गया और वो इंदिरा के साथ कांग्रेस में लौट आए, देवराज उर्स भी जनता पार्टी में चले गए। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार में लौटी। एआर अंतुले मुख्यमंत्री बने। पर बर्खास्त किए गए शरद पवार अपने गुरू यशवंतराव चव्हाण को छोड़कर अपनी पार्टी में 1983 में इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने। वे 1984 से बरामती से जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे पर दिल्ली में दिल नहीं लगा और एक साल बाद ही इस्तीफा देकर 1985 में फिर से विधानसभा पहुंचे। इस बार पवार की इंडियन नेशनल कांग्रेस सोशलिस्ट ने 54 सीटें जीतीं। इस बार इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए भाजपा, जनता पार्टी और दूसरी सभी क्षेत्रियों पार्टियों को इकट्ठा किया। फिर कांग्रेस हटाओ के नारे के साथ भाजपा को साथ लेकर महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष बने। इस बार पहली बार पवार और भाजपा साथ आए। मगर सबको झटका देते हुए 1987 में शरद पवार कांग्रेस में लौट आए। एक साल के अंदर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी को यह समझाने में सफल रहे कि शिवसेना को रोकने के लिए महराष्ट्र में वो जरूरी हैं। एक बार फिर से राजीव गांधी ने शरद पवार को 1988 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया और फिर से पवार ने शंकरराव चव्हाण को मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। मगर 1990 में शिवसेना और भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस को 254 में से 141 सीटें मिलीं। फिर भी 12 निर्दलीयों की मदद से शरद पवार तीसरी बार 1990 में मुख्यमंत्री बने।

राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हुई। पवार ने कहा- सबसे ज्यादा सांसद हमारे पास हैं। मगर पीछे हटना पड़ा और नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हाराव ने भी बदला लिया और उन्हें केंद्र में बुलाकर रक्षामंत्री बना दिया। उनकी जगह सुधाकर राव नाइक मुख्यमंत्री बने। पर मुंबई ब्लास्ट के बाद फिर से पवार सुधाकर नाइक को हटाकर मुख्यमंत्री बने। नरसिम्हा राव भी पवार के दिल्ली कांग्रेस में बढ़ते कद से डरे हुए थे, लिहाजा उन्हें वापस महाराष्ट्र भेजा। 1995 में भाजपा-शिवसेना से हार के बाद शरद पवार एक साल तक महाराष्ट्र नेता विपक्ष रहे और 1996 के लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सीताराम केसरी के खिलाफ लड़ा। 1998 के मध्यावधि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए महाराष्ट्र में पहली बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, आरपीआई समेत कई पार्टियों का गठबंधन बनाकर 48 में से 37 लोकसभा सीटें जीतीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता बने मगर 1999 में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर विरोध कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई। यानी शरद पवार की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने वक्त को पहचानते हुए रोटी पलटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस नए अवतार में फिर से आई। लेकिन 1999 में महाराष्ट्र में पावर में आने के लिए फिर से सोनिया गांधी की कांग्रेस के साथ आए। महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार में एनसीपी शामिल हुई और शरद पवार को यूपीए के दोनों कार्यकालों में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2014 में मोदी लहर में सरकार केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगहों से चली गई।

2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा-शिवसेना गठबंधन में दरार पड़ी। शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस से ज्यादा सीटें लेकर आई। शरद पवार कांग्रेस के बड़े भाई बन गए और कांग्रेस-उद्धव ठाकरे को साथ लाने में लगे रहे। इस बीच भाजपा ने सुबह अंधेरे में भतीजे अजित पवार से बगावत कराकर उन्हें उपमुख्यमंत्री बना दिया। पर पवार हिम्मत नहीं हारे और अजित पवार को निहत्था कर वापस आने पर मजबूर कर दिया। पवार तब और बड़े बन गए जब विद्रोही भतीजे को उपमुख्यमंत्री फिर से बनाया। मगर शिवसेना टूट गई और पवार की सातवीं रोटी चूल्हे पर छूट गई। लोग कह रहे हैं कि शरद पवार आठवीं रोटी पलटने में लगे हैं। मगर पवार की रोटी कब सिकेगी इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है।

● **बिन्दु माथुर**

चाचा-भतीजों में जंग

महाराष्ट्र में बेटे-बेटियों को अपनी राजनीतिक विरासत देने को लेकर चाचा बालासाहेब ठाकरे और भतीजे राज ठाकरे की जंग सबने देखी है। बेटे उद्धव को गद्दी मिली और राज को बनवास। चाचा गोपीनाथ मुंडे और भतीजे धनंजय मुंडे का झगड़ा भी राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए सबने देखा। गोपीनाथ मुंडे ने बेटी पंकजा को चुना और धनंजय ने पकड़ी एनसीपी की राह। कहीं इसी उथल-पथल से बचने के लिए शरद पवार ने यह इमोशनल दांव तो नहीं खेला है। इसमें सत्ता का बंटवारा बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार के बीच इस तरह से कर पाएं कि विवाद नहीं हो। अजित पवार पार्टी की कमान संभाल भी लें तो एनसीपी के सुप्रीमो की हैसियत से चौधराहट का हक शरद पवार के पास ही रहे। ऐसा कर वो एनसीपी के अध्यक्ष की हैसियत से कहीं ऊपर हो जाएंगे। सीनियर पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि अजित पवार इमोशनल है और सब जानते हैं कि शरद पवार इमोशन की राजनीति से ऊपर उठे नेता हैं।

चुनावी मैदान में नौकरशाह

विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस नेता तो टिकट की दावेदारी जता ही रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी पीछे नहीं है। इस बार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ब्यूरोक्रेट्स भी टिकट की लाइन में लग चुके हैं। कांग्रेस में शामिल हो रहे या फिर टिकट मांग रहे अधिकतर अधिकारी रिटायर्ड है। जिनमें आईएएस, आईपीएस, आरपीएस और आरएएस रहे अधिकारी शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं, जो अन्य राज्यों में बड़े पदों पर रह चुके है। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और रामलुभाया, कुंजी लाल मीना जैसे दिग्गज चुनावी समर में उतरने की सोच रहे हैं।

एक ऐसे ही अधिकारी है तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी एसआर जांगिड़। बाड़मेर के कवास के निवासी एसआर जांगिड़ को पूरा तमिलनाडु सिंघम के नाम से भी जानता है, इन्होंने कुख्यात और दुर्दांत बावरिया गैंग का सफाया किया था, इनके साहस के ऊपर चर्चित तमिल फिल्म थीरन बन चुकी है। तमिलनाडु के कई जिलों में एसपी रह चुके जांगिड़ को कई वीरता पदक मिल चुके हैं और राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है। अपनी माटी बाड़मेर से उनका जुड़ाव हमेशा रहा। वे यहां से लोकसभा के चुनावी समर में उतरना चाहते है। शानदार कद काठी, घनी मूछें और रौबदार चेहरे के धनी एसआर जांगिड़ का मन है चुनाव के जरिए समाज सेवा करने का। वहीं राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके निरंजन आर्य के भी चुनावी इरादे हैं, पाली इनका सियासी क्षेत्र है। आर्य की पत्नी संगीता भी सोजत से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी समर में उतर चुकी हैं। सोजत में सामाजिक कार्यों में इनकी सक्रियता देखी जा सकती है। संगीता आर्य अभी आरपीएससी की सदस्य है। आर्य दलित चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे समय से नजदीक रहे हैं।

राजस्थान में नए जिलों के सूत्रधार पूर्व आईएएस रामलुभाया के भी चुनावी समर में उतरने की चर्चा है। वे नए जिले अनूपगढ़ से विधानसभा या फिर श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते है। कांग्रेस के टिकट पर उतर सकते हैं। पिछले चुनाव में भी इनके नाम की चर्चा चली थी। पंजाबी भाषी रामलुभाया कुशल अधिकारी के तौर पर ख्याति प्राप्त हैं। वे नहरी क्षेत्र में जिला कलेक्टर के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। दलित चेहरे के तौर पर रामलुभाया सियासी चेहरे हो सकते हैं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के रेनवाल के निवासी हरी प्रसाद शर्मा पूर्व आईपीएस, फुलेरा से टिकट चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था। उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अच्छे संबंध हैं। उनकी कुशल अधिकारी की इमेज रही है।

उधर, दलित संगठनों में सक्रिय पूर्व पुलिस अफसर अनिल गोठवाल की चाहत भी सियासत करने की है। वे एससी रिजर्व सीट चाकसू या दूदू से चुनाव लड़ना चाहते है। पूर्व आईएएस केसी वर्मा जयपुर के संभागीय आयुक्त रह चुके हैं। वे निवाई से विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और भाजपा से उनकी नजदीकी है। राज्य के चर्चित दलित तेज तर्रार चेहरे, पूर्व आईएएस लाल चंद असवाल जयपुर नगर निगम के आयुक्त रहे हैं। दौसा समेत कुछ जिलों के कलेक्टर, राजस्थान में अंबेडकर कथा कराने के जनक, दूदू, बगरू, चाकसू तीनों जगह से इनका दावा है। अभी किसी दल में नहीं हैं। वहीं दिल्ली के पूर्व पुलिस अफसर मदनलाल शर्मा सीबीआई में डायरेक्टर स्पेशल पद पर आसीन थे। वे अलवर के रामगढ़ से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पूर्व पुलिस अधिकारी महेंद्र चौधरी की बाड़मेर में लंबे समय से सक्रियता है। किसान वर्ग के चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। वे जयपुर ग्रामीण, नागौर समेत कई जिलों के एसपी रह चुके हैं। वे भाजपा से टिकट लेने का प्रयास कर रहे हैं। उधर, राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के भाई पूर्व आरएएस अधिकारी जगमोहन मीणा एनपीपी के टिकट पर एक बार टोंक सवाई माधोपुर से लड़ चुनाव चुके हैं। इस बार फिर पूर्वी राजस्थान किसी सीट से चुनाव लड़ सकते है। आरएएस महावीर खराड़ी भारतीय आदिवासी पार्टी का भविष्य में चेहरा हो सकते हैं। वे वागड़ के आदिवासी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पत्नी प्रकृति खराड़ी भाजपा के टिकट पर आसपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रकृति पिछली राजे सरकार में एसटी आयोग की चेयरमैन थीं। महावीर खराड़ी आदिवासियों के बीच काफी सक्रिय हैं। प्रशासनिक अफसर मन्ना लाल रावत मेवाड़ और वागड़ के आदिवासी क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये भविष्य में भाजपा के आदिवासी फेस हो सकते हैं। केरल कैडर के आईएएस टीआर मीना केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी रह चुके हैं। वे बामनवास में खासे सक्रिय हैं और यहीं के मूल निवासी हैं। पूर्व आईपीएस विजेंद्र सिंह झाला जयपुर के ट्रैफिक एसपी रह चुके हैं। वे जोधपुर के बिलाड़ा से बतौर कांग्रेस बागी चुनाव भी लड़ चुके हैं, फिर वहीं से लड़ने का इरादा है। वहीं पूर्व आईएएस ओपी सैनी सामाजिक सियासत में सक्रिय हैं। करौली से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। अब फिर सक्रिय हैं। उधर, पूर्व आईएएस ललित मेहरा कांग्रेस में सक्रिय हैं। वे पीलीबंगा रिजर्व सीट से चुनाव लड़ना चाहते है। नहरी क्षेत्र में इनकी सक्रियता है। इनकी प्रदेश कांग्रेस की बैठकों में लगातार आवाजाही है। वहीं पूर्व आरएएस अकील अहमद ने ओवैसी के लिए ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी थी। वे राजस्थान में एआईएमआईएम के संगठन विस्तार से जुड़े है। अकील मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। पूर्व पुलिस अधिकारी केराम आईबी राजस्थान के प्रमुख रह चुके हैं। वे नागौर से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। अभी कांग्रेस में सक्रिय हैं। हाल ही में जाट महाकुंभ में सक्रिय थे।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

कुछ प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स कभी भी अपनी सेवाओं को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार

अजमेर विद्युत वितरण निगम के पूर्व एमडी पीएस जाट लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर बीपी मीणा, सुखपाल मीणा, अजय सिंह चित्तौड़ा, आरके मीणा, सियाराम मीणा, ओपी यादव और रिटायर्ड आईपीएस अफसर आरपी मीणा, गिरिराज मीणा, भारतीय रेल सेवा से हाल में रिटायर हुए किशनलाल मेघवाल लंबे समय से टिकट के प्रयासों में हैं। इतना ही नहीं कांग्रेस और भाजपा से टिकट की गारंटी मिलने पर कुछ प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स कभी भी अपनी सेवाओं को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।

उप्र में ट्रिपल इंजन सरकार

उप्र में नगर निकाय चुनाव के परिणाम 13 मई को जारी हो चुके हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों के पदों पर जीत हासिल कर एकतरफा महापौर का चुनाव जीता है। प्रदेश के 75 जिलों में 760 नगर निकायों के लिए दो चरणों में वोटिंग हुई थी। इनमें 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका में 199 सीटों में से 94 सीटें भाजपा व उसके सहयोगियों के दलों के खाते में गई हैं। सपा ने 39, कांग्रेस ने 4, बसपा ने 16 और अन्यों ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नगर पंचायत सीटों की बात करें तो भाजपा ने 196, सपा ने 91, कांग्रेस ने 14, बसपा ने 38 और अन्य ने 205 सीटों पर जीत दर्ज की है।

निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भाजपा की दांव पर लगी थी, क्योंकि शहरी इलाके हमेशा से भाजपा के गढ़ रहे हैं। पिछली बार भाजपा का मेयर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी। इस बार के चुनाव में भाजपा ने मेयर से लेकर नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष सीटों पर भी जीत का परचम फहराया है। निकाय चुनाव में अहम भूमिका सवर्ण मतदाताओं की रही। शहरी क्षेत्र में ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, पंजाबी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिसके चलते भाजपा का सवर्णों को मैदान में उतारने का दांव पूरी तरह सफल रहा। मेयर के लिए भाजपा ने पांच ब्राह्मण, चार वैश्य प्रत्याशी उतारकर शहरी सीटों के समीकरण को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। सवर्ण वोटर भाजपा का कोर वोटर है, जिसके चलते पार्टी ने एकतरफा जीत हासिल की है। शहरी इलाकों में भाजपा का प्रदर्शन हमेशा से बेहतर रहा है। भाजपा 2017 से पहले जब सत्ता से बाहर थी तब भी निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती रही है। भाजपा का राजनीतिक जनाधार शहरी इलाकों में हमेशा से रहा है, जिसके दम पर भाजपा निकाय चुनाव में जीत दर्ज करती रही है। मौजूदा समय में भाजपा सत्ता में रही है, जिसका सियासी फायदा भी उसे मिला है। पिछली बार 16 मेयर में 14 मेयर सीट पर जीत दर्ज की थी और इस बार क्लीन स्वीप कर दिखाया है।

भाजपा ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी 2022 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद ही शुरू कर दी थी। भाजपा ने अपने मंत्री और विधायक के परिवार के सदस्यों को टिकट न देकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा। इसके अलावा नगर निगम और नगर पालिका के लिए जिन सीटों पर मौजूदा मेयर और अध्यक्ष के खिलाफ माहौल नजर आ रहा था, उनका टिकट काट दिया। भाजपा की अपनी आधी से ज्यादा मौजूदा मेयर की जगह नए और युवा चेहरे को उतारकर सत्ता विरोधी लहर निपटने की रणनीति काम आई।

नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित सभी मंत्री पूरे दमखम के साथ जुटे थे। मुख्यमंत्री योगी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं कीं। उन्होंने 75 में से आधे से ज्यादा जिलों में चुनावी रैलियां कीं। इसके अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री, सभी मंत्री, विधायक, सांसद भी चुनावी रण में जुटे रहे। भाजपा ने विधानसभा और लोकसभा की तरह निकाय चुनाव लड़ा, जिसका उसे सियासी फायदा मिला। अखिलेश यादव ने कुछ चुनिंदा सीटों पर ही जाकर प्रचार किया, जबकि मायावती और प्रियंका गांधी नजर नहीं आईं।

भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में पहली बार 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे और उसमें 90 फीसदी पसमांदा मुस्लिम थे। नगर निगम में पार्षद उम्मीदवार, नगर पालिका की छह अध्यक्ष और सभासद सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट। इसी तरह नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की 38 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पश्चिमी उप्र की 18 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे। ब्रज क्षेत्र में 8, अवध क्षेत्र में 6, गोरखपुर क्षेत्र में 2 मुस्लिम चेहरों को प्रत्याशी बनाया। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में सभासद और पार्षदों के टिकट भी मुस्लिमों को दिए गए। यह प्रयोग सफल रहा और मुस्लिम बहुल बूथों पर जीत मिली। भाजपा ने आधी आबादी यानी महिला वोटर्स पर फोकस बढ़ाया था, क्योंकि निकाय चुनाव में 37 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके लिए पार्टी ने महिला मोर्चा को काफी पहले से काम के लिए जमीन पर उतार रखा था। भाजपा ने महिलाओं के लिए सहभोज का आयोजन किया। इस सहभोज में मुस्लिम और दलित महिलाओं को खास तौर पर बुलाया गया था। भाजपा की जीत में महिला मतदाताओं की अहम रोल रहा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

किसको कितना मिला?

आयोग के अनुसार, नगर निगमों में भाजपा ने सभी 17 मेयर, 813 पार्षद, नगर पालिका परिषदों में 89 अध्यक्ष और 1360 सभासद, 191 नगर पंचायत अध्यक्ष और 1403 वार्ड में सदस्य के पदों पर जीत हासिल की है। मुख्य विपक्षी दल सपा ने नगर निगमों में 191 पार्षद, 35 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष, 425 सभासद, 79 नगर पंचायत अध्यक्ष और 485 वार्ड सदस्य के पदों पर चुनाव जीता है। बहुजन समाज पार्टी ने नगर निगमों में 85 पार्षद, 16 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष और 191 सभासदों के अलावा 37 नगर पंचायत अध्यक्ष और 215 वार्ड सदस्यों के पदों पर विजय हासिल की। कांग्रेस ने नगर निगमों में 77 पार्षद, चार नगर पालिका परिषदों में अध्यक्ष, 91 सभासद और 14 नगर पंचायत अध्यक्ष, 77 वार्ड सदस्य के पदों पर चुनाव जीता। वहीं मैनपुरी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पर भाजपा की जीत को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नगर निगमों में 19 पार्षद, तीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और 30 सभासदों के अलावा छह नगर पंचायत अध्यक्ष पदों पर भी चुनाव जीतने में सफलता मिली है।

मुजरिमों पर मेहरबानी

कहते हैं राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। समय और परिस्थिति के आधार पर दोस्त और दुश्मन तय होते हैं। इसके लिए यदि विचारधारा से भी समझौता करना पड़े, तो ऐसा करने से राजनीतिक दल परहेज नहीं करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण इस समय बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह हैं, जिनके लिए बिहार सरकार ने जेल मेन्युअल में बदलाव करके रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। एक वक्त था जब आनंद मोहन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को फूटी आंख भी नहीं सुहाते थे। सही मायने में लालू की राजनीति का विरोध करके ही उन्होंने अपनी सियासत चमकाई थी। दूसरी तरफ जिस नीतीश कुमार ने उनके लिए जेल के नियम बदले हैं, उन्होंने पहले इसी नियम को बनाकर उनकी रिहाई का रास्ता रोका हुआ था। लेकिन आज वक्त बदलने के साथ ही दोनों उनके हितैषी बन चुके हैं।

इससे भी दिलचस्प बात ये है कि बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी आनंद मोहन की रिहाई का स्वागत करने पर मजबूर है। आनंद मोहन को बेचारा बताते हुए सारा दोष नीतीश सरकार के माथे मढने की कोशिश कर रही है। भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय सिन्हा का बयान सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं, सरकार का कदम दुर्भाग्यपूर्ण है। आनंद मोहन को राजनीतिक कारणों से तत्कालीन सरकार द्वारा फंसाया गया था, उनकी रिहाई स्वागत योग्य है। सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उनकी आड़ में अन्य 26 अपराधियों की रिहाई सूची में नाम देखकर बिहार के लोग स्तब्ध हैं। साल 2016 में जेल मेन्युअल में संशोधन आनंद मोहन पर बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए की गई थी। उसी संशोधन का परिणाम है कि पूरी सजा काटने के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी।

भाजपा नीतीश कुमार पर बिहार में अपराधियों के हौंसले को बढ़ावा देने का आरोप लगाती है। लोकसेवकों की जान को बढ़ते खतरे की चिंता जताती है, लेकिन आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल नहीं उठाती। हालांकि, आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश कुमार के इस फैसले का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग की है। पटना के पूर्व आईपीएस हाईकोर्ट में अर्जी भी डालने वाले हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नीतीश सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मियों के हौंसले टूटेंगे और बिहार में अपराधियों के हौंसले बढ़ेंगे। खैर, यहां बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में 80 लाख से ज्यादा राजपूत वोट बैंक को कब्जे में करने के लिए नीतीश आनंद मोहन को रिहा कर रहे हैं? क्या राजपूत वोटों के लालच में ही भाजपा आनंद मोहन की रिहाई का विरोध नहीं कर रही है? क्या ऐसा करके नीतीश कुमार बिहार में राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं?

आनंद मोहन का राजनीतिक वजूद

अब आते हैं उस सवाल पर कि आनंद मोहन सिंह आज सभी राजनीतिक दलों के लिए इतने अहम क्यों हो गए। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज वोट की राजनीति है। बिहार में इस वक्त जाति जनगणना मुद्दा बना हुआ है। सूबे की राजनीति में जाति का क्या महत्व है, ये सभी जानते हैं। नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने के बाद अगड़ा वोट पहले ही गवां चुके हैं। आरजेडी के साथ होने की वजह से यादव, मुस्लिम के साथ कुछ निचली जातियों का वोट उनके पास है, लेकिन सवर्णों के वोट के लिए उनको एक चेहरे की तलाश थी। आनंद मोहन राजपूतों और भूमिहारों के लिए रॉबिनहुड माने जाते रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने अगड़ों की राजनीति की है। ऐसे में यदि वो नीतीश-लालू के पाले में जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक फायदा दोनों दलों को होगा। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी गोटी फिट करने में लगे हुए हैं।

बिहार में 1924 के जेल मेन्युअल को 88 साल बाद 12 दिसंबर 2012 में नीतीश कुमार ने बदला था। इस मेन्युअल की धारा 481(1)-क में आखिरी लाइन थी कि ड्यूटी पर सरकारी सेवक की हत्या जैसे जघन्य मामले में आजीवन कैद की सजा पा रहे कैदी 433-ए सीआरपीसी के तहत तभी रिहा किए जाएंगे जब वो 20 साल की सजा पूरी कर लेंगे। उपरोक्त सवालों के जवाब जानने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर आनंद मोहन सिंह कौन हैं, जिनकी बिहार की राजनीति में अचानक इतनी अहमियत बढ़ गई है। जो पिछले दो दशक से हाशिए पर रहकर जेल में तन्हा जिंदगी जी रहे थे। बता दें कि आनंद मोहन को उत्तरी बिहार के कोसी क्षेत्र का बाहुबली नेता माना जाता है। उनका जन्म सहरसा जिले के पंचगछिया गांव में एक तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दादा राम बहादुर सिंह तोमर स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। इलाके में उनके परिवार की तूती बोलती थी। कॉलेज में जाने के बाद उनकी पहचान एक दबंग छात्र के रूप में होने लगी थी। धीरे-धीरे कॉलेज की राजनीति में सक्रियता भी बढ़ती गई। इसी बीच साल 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण देश में संपूर्ण क्रांति आंदोलन कर रहे थे। आनंद उनकी समाजवादी सोच से बहुत प्रभावित थे। वो उस आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसकी वजह से बीच में ही कॉलेज छोड़कर पूरी तरह सियासत में कदम रख दिया। जयप्रकाश नारायण के साथ राजनीति में सक्रिय हो गए। 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगने के बाद आनंद मोहन को जेल भेज दिया गया। वो करीब दो साल तक जेल में रहे। वापस लौटने के बाद समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर के संपर्क में आए। उनके विचारों से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरू बना लिया। ये वही समय था जब जेपी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में लगे हुए थे। बिहार में जाति की राजनीति शुरू हो चुकी थी। लालू ने खुद को यादवों, पिछड़ों और मुस्लिमों का नेता घोषित कर दिया था। उस वक्त मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ था, लेकिन 1989 में हुए भागलपुर दंगों में लालू के समर्थन की वजह से मुस्लिम उनकी तरफ चले गए। लालू अपने चुटीले अंदाज की वजह से नौजवानों में भी लोकप्रिय थे।

● **विनोद बक्सरी**

जेल, हत्या और हिंसा...

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। बीते मंगलवार शाम क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे थे। यहां से एनएबी के आदेश पर अर्धसैनिक रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। इसके बाद पाकिस्तान में हिंसा भड़क गई। इतना ही नहीं सबसे अधिक आबादी वाले प्रांत पंजाब में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। स्थानीय मंत्रालय ने कहा कि कानून व्यवस्था और शांति बहाल करने के लिए सेना जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी। इस बीच, पंजाब पुलिस ने कहा कि शांति भंग करने और हिंसा में शामिल होने के आरोप में पूरे प्रांत से 945 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का संयुक्त अरब अमीरात में निधन हो गया। मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान में कई मुकदमें चल रहे थे और इसी वजह से वह दुबई में निर्वासन में जी रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया था कि कारगिल घुसपैठ का कांड करने वाले परवेज मुशर्रफ भारत के साथ कश्मीर को लेकर बड़ी डील करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। भारत और पाकिस्तान सियाचिन और सरक्रीक को लेकर समझौता करने ही वाले थे कि मुशर्रफ के खिलाफ वकीलों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ था। अप्रैल 2018 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को आजीवन सार्वजनिक पद धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया था।

दरअसल, इस फैसले से एक साल पहले पनामा पेपर्स लीक मामले में नाम आने पर नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने कहा था- संवैधानिक खंड के तहत अयोग्य ठहराए गए व्यक्ति को जीवनभर के लिए प्रतिबंधित माना जाएगा। 1999 में निर्वासित होने के बाद सितंबर 2007 में पाकिस्तान लौटने पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को नजरबंद कर दिया था। शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने के लिए नवंबर 2019 में जमानत मिली और वह फिर कभी नहीं लौटे। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान पर शासन करने वाले तीसरे सैन्य कमांडर थे। उन्होंने 1999 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नवाज शरीफ सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने 2007 में संविधान को निलंबित कर दिया था और आपातकाल लगाया था। लेकिन जैसे ही 2013 में नवाज शरीफ की सत्ता वापस आई तो पूरा माहौल मुशर्रफ के खिलाफ हो गया। मुशर्रफ आम चुनाव में भाग लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे लेकिन कोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। नवाज शरीफ सरकार ने 2013 में मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था।

पाकिस्तान में वर्चस्व के लिए परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के बीच यह खुलेआम सियासी युद्ध का दौर था। क्योंकि उससे पहले 1999 में जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाया था, तो उन्होंने भी नवाज शरीफ पर देशद्रोह सहित कई आरोपों के मुकदमे चलाए थे। इस दौरान उन्होंने यह तर्क दिया था कि नवाज शरीफ ने 1999 के सैन्य तख्तापलट के दिन कोलंबो से लौटने पर परवेज मुशर्रफ के विमान की लैंडिंग में देरी करने की कोशिश की थी।

परवेज मुशर्रफ का शासनकाल चार बड़े कांड के लिए जाना जाता है। 2006 में बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या, 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या, 2007 में करीब 60 न्यायाधीशों की गिरफ्तारी और 2007 में इस्लामाबाद में बहुचर्चित लाल मस्जिद की घेराबंदी में एक मौलवी की हत्या कर दी गई थी। वास्तव में 1988 और 1990 के बीच 2 बार और फिर 1993 से 1996 तक प्रधानमंत्री बनने से पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को कई गिरफ्तारियों और जेल में कई शर्तों का सामना भी करना पड़ा था।

2007 में एक आत्मघाती हमलावर ने बेनजीर की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हत्या पाकिस्तानी तालिबान और अलकायदा के इशारे पर की गई थी। खास बात ये थी कि बेनजीर भुट्टो ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उनकी हत्या हुई तो मुशर्रफ जिम्मेदार होंगे। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानी राजनीति में एक प्रमुख शख्सियत थीं। भुट्टो ने 1988 से 1990 और 1993 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार सेवा दी थी। राजनीति में उनके ग्लैमरस व्यक्तित्व और बेबाक भाषणों के चलते पाकिस्तान के पुरुष राजनीतिज्ञ उन्हें अपने लिए चुनौती मानते थे। इससे पहले 1956 से 1957 तक पाकिस्तान के पांचवें प्रधानमंत्री हुसैन सुहरावर्दी को 1962 में गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने 1958 में जनरल अयूब खान के तख्तापलट का समर्थन करने से मना कर दिया था। हुसैन को 1962 में पाकिस्तान सुरक्षा अधिनियम 1952 के तहत जेल में डाल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें पाकिस्तान में राजनीति में भाग लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा

इसी तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में जनरल याह्या खान की जगह ली थी। उन्होंने 1973-1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। उनके शासनकाल में पाकिस्तान ने भारत के साथ शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। लेकिन जुलाई 1977 में एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से जनरल जिया-उल-हक ने सत्ता हड़प ली। भुट्टो को एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सितंबर 1977 में रिहा तो किया गया लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें अप्रैल 1979 में सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। वहीं शाहिद खाकान अब्बासी, जिन्होंने 2017 से 2018 तक प्रधानमंत्री के रूप में नवाज शरीफ की जगह ली थी, उनको भी कथित भ्रष्टाचार के लिए जनवरी 2019 में 12-सदस्यीय राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की टीम ने गिरफ्तार किया था।

क्या ब्रिटेन भी झेलेगा बंटवारे का दर्द...?

ब्रिटेन के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम ने एक बार फिर दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींची हैं। पिछले दिनों ब्रिटेन के राज्य स्कॉटलैंड में हमजा यूसुफ को राज्य का सर्वोच्च नेता यानी फर्स्ट मिनिस्टर चुन लिया गया। स्कॉटलैंड में पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी मुस्लिम नेता को प्रमुख चुना गया हो। पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ ने पद संभालते ही एक अलग देश स्कॉटलैंड की अपनी मांग को एक बार फिर हवा दे दी। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह की मांग दोहराई। इसे सुनक ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हमजा इस मसले पर उनका मत पहले से ही जानते हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। इसे नियति का चक्र ही कहेंगे कि भारत विभाजन के महज 75 वर्ष बाद आज ऐसा वक्त आया है, जब ब्रिटेन के बंटवारे की चर्चा होने लगी है। भारत का विभाजन करवाने वाले ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों, प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और वायसराय माउंटबेटेन ने शायद ही कभी कल्पना की होगी कि ऐसा वक्त आएगा और आएगा भी तो इतनी जल्दी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हो रहा है। इस बार जो बंटवारे का राग अलाप रहा है, उसके पूर्वज उस वक्त भी बंटवारे के हिमायती थे। हमजा यूसुफ, जिनका लखनवी परिवार धार्मिक आधार पर भारत को तोड़ने के लिए लड़ा था अब स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता पर जोर देकर ब्रिटेन को तोड़ने के लिए तैयार हैं जबकि उसको एकजुट रखने की जिम्मेदारी ऋषि सुनक पर है जिनके पूर्वज उस वक्त भी अलग देश के हिमायती नहीं थे।

ऋषि सुनक ने एक बातचीत में कहा, जब हमारे पूर्वज यहां आए तो इंग्लैंड में नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम में आए थे और हमारी परवरिश उसी माहौल में हुई है, जहां हमने एकता की ताकत की सीख ली है। ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड ने मुख्य रूप से स्कॉटलैंड के अलगाव पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तानी प्रवासियों के एक बेटे को अपने नेता के रूप में चुना है। पिछले 18 वर्ष से स्कॉटलैंड में रह रहे और वहां की राजनीति में सक्रिय ग्लासगो सिटी कॉलेज के प्रोफेसर ध्रुव कुमार कहते हैं कि हमजा स्कॉटिश लोकतंत्र के लिए फिट नहीं हैं और उनके चुनाव से स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र की विरासत सवालों के घेरे में है। उनके मुताबिक हमजा ने मुस्लिमों और लाभ चाहने वालों को भुनाया है। इसके अलावा, हमजा भारत विरोधी भी हैं और स्कॉटलैंड में रह रहे भारतीयों और हिंदुओं को पसंद नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों है कि हमजा यूसुफ अलग स्कॉटलैंड की मांग की ताकत से आज राज्य की सत्ता के शीर्ष पर हैं। अगर उनकी मांग और इच्छा पूरी हो गई तो इस्लामिक देशों से इतर किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले वे पहले मुस्लिम हो सकते हैं। क्या यह इतना आसान है?

अलग स्कॉटलैंड की मांग कोई नई नहीं है। सन् 1707 से स्कॉटलैंड यूनाइडेड किंगडम का हिस्सा है। 1800 में आयरलैंड के जुड़ने पर इसका नाम यूनाइडेट किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड हुआ, लेकिन जब 1922 में आयरलैंड का एक हिस्सा अलग हो गया तब से इस देश का नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नार्दन आयरलैंड है। इस देश में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दन आयरलैंड चार राज्य हैं। इंग्लैंड को छोड़ बाकी तीनों राज्यों में अंग्रेजी के अलावा उनकी अपनी भाषा भी है। यही वजह रही कि 1997 में स्कॉटलैंड के लिए अलग संसद की मांग को लेकर एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें स्कॉटलैंड की जीत हुई और स्कॉटिश पार्लियामेंट की स्थापना हुई। 1999 में ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर अपना कानून बनाने का अधिकार दे दिया, लेकिन विदेश नीति, रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर आज भी ब्रिटेन का ही अधिकार है यानी इन मुद्दों से जुड़े सारे फैसले ब्रिटिश सांसद लेते हैं।

हाउस ऑफ कॉमन्स यानी संसद में स्कॉटिश सांसद एक राज्य से केंद्र में आए सांसद की तरह होते हैं। 2014 में एक और जनमत संग्रह हुआ था। यह अलग स्कॉटलैंड की मांग को लेकर था, लेकिन 55 फीसदी जनता ने ब्रिटेन के साथ रहने की सहमति दी। एक बार फिर हमजा जनमत संग्रह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के इनकार के बावजूद अगर हमजा जनमत संग्रह करवाते हैं तो वो एक तरह से बगावत होगी, लेकिन यह हमजा युसूफ का अधिकार होगा और वे ऐसा करा सकते हैं। ब्रिटिश संसद उस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। फिर भी अगर मौजूदा हालात को देखें तो जनमत संग्रह के परिणाम हमजा के पक्ष में जाते हुए नहीं दिखते क्योंकि हमजा के विरोधियों का मानना है कि अभी आर्थिक तौर पर स्कॉटलैंड उस स्थिति में नहीं है कि वह ब्रिटेन से अलग होने का जोखिम उठाए। उदाहरण के तौर पर, स्कॉटलैंड के उत्पादन के 65 फीसदी हिस्से की खपत इंग्लैंड और वेल्स में ही होती है। ऐसे में स्कॉटलैंड के लिए यह जोखिम उठाना उचित नहीं होगा।

● **कुमार विनोद**

अलगाववाद के मुद्दों पर टिकी हमजा की राजनीति

हमजा की राजनीति अलगाववाद के मुद्दों पर टिकी हुई है। स्कॉटलैंड की आबादी तकरीबन 55 लाख है जिनमें से 15 लाख के करीब या तो सरकारी अनुदानों पर आश्रित हैं या शरणार्थी हैं। शरणार्थियों में सीरिया, मिस्र, अल्बानिया और दक्षिण अफ्रीकी देशों से आए लोगों की तादाद ज्यादा है और उनमें भी मुस्लिम समुदाय बहुतायत में है। हमजा उन्हीं लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने लिए एक नया और उनका अच्छा खासा वोटबैंक भी है। जब हमजा ने फर्स्ट मिनिस्टर बनने के साथ अपना कार्यभार संभालने वाले दिन ही अपने दफ्तर में मौलवियों के साथ नमाज अता की, तो स्कॉटिश समुदाय में एक नई बहस छिड़ गई। स्कॉटलैंड के एक मजदूर यूनियन के नेता ने बातचीत में कहा कि वे अलग देश तो चाहते हैं लेकिन अलग मुस्लिम देश नहीं चाहते। दिलचस्प यह है कि यूके के विभाजन की मांग करने वाला और उसे विभाजित होने से बचाने को तैयार दोनों व्यक्ति भारतीय मूल के ही हैं और इन सब पर एक और भारतीय मूल के व्यक्ति यानी आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो की नजर है। जिस भारत के टुकड़े कर अंग्रेजों ने भारत को कभी न खत्म होने वाला जख्म दिया है अब उन्हीं टुकड़ों के अलग-अलग हिस्सों से बाहर गए लोग अलग-अलग भूमिकाओं में ब्रिटेन की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। कह सकते हैं कि काल का एक चक्र पूरा हो रहा है।

इंटरनेट के मामले में फिसड्डी लड़कियां

भारत में स्त्री-पुरुष के बीच जो असमानता की खाई है, वो 21वीं सदी में भी जारी है। आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है। समाज में मौजूद यह भावना बच्चियों को आगे बढ़ने से रोक रही है। आज जब सारी दुनिया इंटरनेट के इर्द-गिर्द सिमट गई है उस दौर में भी देश में 100 लड़कों के मुकाबले केवल 61 लड़कियों के पास ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। जो कहीं न कहीं 15 से 24 वर्ष की इन लड़कियों को पंख फैलाने से रोक रही है। मतलब साफ है कि इंटरनेट के उपयोग और पहुंच के मामले में भी लड़कियां फिसड्डी हैं। हालांकि क्या उनके पिछड़ने के लिए वो खुद जिम्मेवार हैं या फिर इसके पीछे की वजह हमारा समाज और कमजोर मानसिकता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

यह जानकारी डिजिटल डिवाइड को लेकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा 27 अप्रैल 2023 को जारी नई रिपोर्ट ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड में सामने आई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक आज जब मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत बन गया है। उस दौर में भी यह लड़कियां, मोबाइल फोन रखने के मामले में भी लड़कों से पीछे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में एक समान आय वर्ग के लड़के और लड़कियों के बीच मोबाइल के मामले में 39.5 अंकों का अंतर है। मतलब की भारत में एक ही परिवार में रहने वाले लड़के की तुलना में लड़कियों के पास खुद का मोबाइल फोन होने की संभावना 39.5 फीसदी कम है। आंकड़ों के मुताबिक इस मामले में भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु की लड़कियों और महिलाओं की स्थिति तो कई अफ्रीकी देशों से भी बदतर है। उदाहरण के लिए जहां घाना में यह अंतर 17.5 अंकों का है। वहीं नाइजीरिया में 11.3, रवांडा में 9.2, जबकि सिएरा लियोन में तो केवल 5.7 अंकों का है।

यूनिसेफ ने अपनी इस रिपोर्ट में 15 से 24 वर्ष के युवाओं के बीच डिजिटल डिवाइड का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। रिपोर्ट मूलत: निम्न, निम्न-मध्यम और कुछ मध्यम-आय वाले देशों के इंटरनेट उपयोग, खुद का मोबाइल फोन और डिजिटल कौशल से जुड़े आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। लेकिन आपस में जुड़ी इस दुनिया में लड़कियां पीछे छूट रहीं हैं। देखा जाए तो यूनिसेफ द्वारा जारी यह रिपोर्ट ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करती है जो कहीं भी 21वीं सदी के कैनवस में फिट नहीं बैठती। जीएसएमए द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट कनेक्टेड वीमेन: द मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश में केवल 79 फीसदी पुरुष मोबाइल फोन रखते हैं, वहीं महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा केवल 67 फीसदी ही है। मतलब इनके बीच 15 फीसदी का जेंडर गैप है। जीएसएमए के मुताबिक विकलांग महिलाओं की स्थिति तो कहीं ज्यादा खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में केवल 5 फीसदी विकलांग महिलाओं के पास अपना खुद का मोबाइल फोन है।

इसी तरह यदि इंटरनेट की उपलब्धता को देखें तो जहां देश में 45 फीसदी पुरुष इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वहीं महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा केवल 30 फीसदी ही है। मतलब कि इनके बीच 33 फीसदी का अंतर है। ऐसा ही कुछ 2022 में ऑक्सफेम द्वारा जारी इंडिया इनक्वॉलिटी रिपोर्ट 2022 में भी सामने आया है जिसके मुताबिक देश में केवल 31 फीसदी महिलाओं के पास खुद का मोबाइल फोन है। वहीं 57 फीसदी पुरुषों की तुलना में केवल एक तिहाई यानी 33 फीसदी महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है।

डिजिटल डिवाइड की यह जो खाई है वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यूनिसेफ के मुताबिक कमजोर देशों में 90 फीसदी किशोर लड़कियां इंटरनेट से वंचित हैं। वहीं इसके विपरीत उनकी ही उम्र के युवा पुरुषों के ऑनलाइन होने की संभावना दोगुनी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट तक पहुंच को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, विश्लेषण किए गए अधिकांश देशों में, घर पर इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले युवाओं की संख्या, डिजिटल कौशल प्राप्त युवाओं की संख्या से कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार औसतन 32 देशों और क्षेत्रों में, लड़कों की तुलना में, लड़कियों के डिजिटल रूप से प्रवीण होने की संभावना 35 फीसदी कम है। इसमें फाइल और फोल्डरों को कॉपी-पेस्ट करना, ईमेल भेजना या फाइलों को इधर से उधर भेजना जैसी मामूली गतिविधियां शामिल हैं। ऐसे में रिपोर्ट का मानना है कि इसे दूर करने में शिक्षा और परिवार के वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण है।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

डिजिटल दुनिया में भी सफल हो सकें बच्चियां

देखा जाए तो एक ही घर में लड़कों की तुलना में लड़कियों को इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों तक पहुंच हासिल करने या उपयोग करने की संभावना काफी कम रहती है। इसी तरह विश्लेषण किए गए 41 देशों और क्षेत्रों में एक ही घर में लड़कों की तुलना में लड़कियों को मोबाइल फोन मिलने की संभावना कम ही होती है। यूनिसेफ का मानना है कि उच्च शिक्षा और श्रम बाजार के अवसरों तक पहुंच में मौजूद बाधाएं, भेदभावपूर्ण लैंगिक मानदंड और ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं लड़कियों के कौशल विकास और डिजिटल पहुंच को सीमित कर रही हैं। ऐसे में यूनिसेफ ने दुनियाभर में सरकारों से लैंगिक असमानता की खाई को भरने में मदद करने का आह्वान किया है, जिससे बच्चियां डिजिटल दुनिया में भी सफल हो सकें। इस बारे में यूनिसेफ के शिक्षा निदेशक, रॉबर्ट जेनकिंस का कहना है कि, लड़कों और लड़कियों के बीच असमानता की इस खाई को भरने के मायने, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी तक उनकी पहुंच से कहीं ज्यादा हैं। यह मुद्दा लड़कियों को इन्नोवेटर, निर्माता और लीडर बनने के लिए सशक्त करने के बारे में है। ऐसे में उनके अनुसार यदि हम श्रम बाजार में, विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को भरना चाहते हैं, तो हमें आज से ही युवाओं, विशेष रूप से लड़कियों को डिजिटल कौशल हासिल करने में मदद देने की शुरूआत करनी होगी।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

वापसी

अजय बाबू सिग्नल की बत्ती के हरी होने का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे उनके बेटे रोहन ने कहा, पापा, देखो बाइक में वह बच्चा कितना खुश है, मेरे नसीब में उसके समान खुशी क्यों नहीं है?

नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें तो हर चीज उपलब्ध है। घर में आया है, बढ़िया स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा दिया है। घर पर ट्यूटर भी आता है तुम्हें पढ़ाने। अजय बाबू ने रोहन को समझाने की कोशिश की।

लेकिन मां का प्यार तो नहीं है मेरे नसीब में। आपसे झगड़ा कर मां चली गई। क्यों नहीं रोका आपने मां को?

बेटे के इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे पाए अजय बाबू। उन्होंने झट मोबाइल निकाला और अपनी पत्नी को व्हाट्सएप किया, सॉरी सुरभि! असल में मैं बहुत तनाव में था और तुम्हारी बातों की अनदेखी कर दी। तुम अपनी बात मनवाने की जिद पर अड़ी रही और गुस्से में मैंने तुम पर हाथ उठा दिया। अपने रोहन के लिए कृपया वापस लौट आओ।

- निर्मल कुमार डे

अनोखा बंधन

रिया और मनीष सर्विस करते थे। रिया के साथ ऑफिस में काम करने वाले रोहित को मनीष पसंद नहीं करता था। जब वह रिया से बात करता तो मनीष को जलन होने लगती थी वह रिया और रोहित को गलत समझता था। जब भी रिया उसको समझाने की कोशिश करती वह उस पर विश्वास ही नहीं करता था। दिन पर दिन हालत खराब होते जा रहे थे। कल रक्षाबंधन था। रिया का कोई भाई नहीं था। रक्षाबंधन वाले दिन वह बैठी हुई थी। रिया किसी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल बजी, रिया ने दरवाजा खोला। भैया आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। उसने रोहित को राखी बांधी और मिठाई खिलाई और रोहित ने उसको गिफ्ट दिया। यह सब मनीष देख रहा था। आज वो खुश था आज उसने उन दोनों को अनोखे बंधन में देखा, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका रोहित के प्रति नजरिया जो बदल चुका था। वह रिया और रोहित दोनों से माफी मांगने लगा। उन दोनों ने उसको माफ कर दिया।

- पूनम गुप्ता

कांटों की पहरेदारी...

जब-जब आती मस्त बयारें,
तब-तब हम लहराते हैं।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

हमसे ही अनुराग-प्यार है,
हमसे मधुमास जुड़ा,
हम संवाहक संबंधों के,
सबके मन को भाते हैं।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

स्वागत-अभिनंदन हमसे है,
हमीं बधाई देते हैं,
कोमल सेज नई दुल्हिन की,
आकर हमीं सजाते हैं।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

तितली और शहद की मक्खी,
को पराग हम देते हैं,
अपनी मोहक मुस्कानों से,
भंवरों को भरमाते हैं।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

खुश हो करके मिलो सभी से।
जीवन बहुत जरा सा है,
सुख-दुख में हंसते रहने का,
हम तो पाठ पढ़ाते हैं।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

तोड़ हमें उपवन का माली,
विजयमाल को गूंथ रहा,
हम गुलाब हैं रंग-बिरंगे,
अपनी गंध लुटाते हैं।।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

रूप हमारा देख-देखकर,
जग मोहित हो जाता है,
हम कांटों में पलने वाले,
सबको सुख पहुंचाते हैं।
कांटों की पहरेदारी में,
गीत खुशी के गाते हैं।।

—

(डॉ. रूपचंद्र शास्त्री 'मयंक')

खेल संघों को राजनीतिज्ञों से मुक्त करने का समय

कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच महाजंग चल रही है। पहलवान बृजभूषण को कुश्ती संघ से खदेड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक बैकिंग इतनी ज्यादा मजबूत है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे। बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक योद्धा हैं, तो उनके सामने वे पहलवान हैं, जिन्होंने ओलंपिक और एशियन गेम्स में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कुछ महिला पहलवान चार महीने से बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह न सिर्फ उन्हें नकार रहे हैं, बल्कि चुनौती भी दे रहे हैं कि साबित करो। सरकारी अमला महिला पहलवानों के आरोपों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल रहा है। इसका कारण यह है कि बृजभूषण शरण सिंह लोकसभा के सांसद हैं। प्रशासन किसी सांसद पर हाथ डालने से डरता है, खासकर तब, जब सांसद सत्ताधारी पार्टी का हो।

पिछली बार कुछ पहलवान 18 जनवरी को धरने पर बैठे थे, तब बार-बार कहा जा रहा था कि यौन शोषण के आरोप झूठे हैं, ये लड़कियां एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती। तब लडकियों ने कहा था कि वे लोकलाज से डरती हैं। ऊपर से आदेश हुआ तो खेलमंत्री अनुराग ठाकुर बीच में पड़े थे, लगातार तीन दिन बैठकें होती रहीं। अंतत: कुछ मांगे मान ली गई थीं और यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए दो कमेटियां बना दी गईं थी। एक कमेटी मंत्रालय की थी और दूसरी ओलंपिक खेल एसोसिएशन की, जिसकी अध्यक्ष पीटी उषा हैं। इन दो कमेटियों का गठन होने के बाद धरना समाप्त हो गया था। इन कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन खेल मंत्रालय रिपोर्ट दबाकर बैठा है। 12 लड़कियां कमेटी के सामने पेश हुई थीं, लेकिन जांच कमेटियों ने खबर उड़ा दी कि किसी ने भी यौन शोषण के आरोप नहीं लगाए। उड़ती-उड़ती खबर आई कि कमेटियों ने बृजभूषण को क्लीन चिट दे दी है। पीटी उषा ने जिस तरह धरने के खिलाफ बयान दिया है, उससे भी उन खबरों की पुष्टि होती है कि रिपोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी गई है।

सरकार की इस लीपापोती शैली के खिलाफ आखिर लड़कियों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। 7 लड़कियों ने कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन जाकर बाकायदा यौन शोषण की शिकायत दर्ज करवाई। इनमें एक लडकी तो 17 साल की थी। यह पॉक्सो का गंभीर मामला था, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के भाजपा का सांसद होने के कारण तब एफआईआर दर्ज नहीं की गई। यह बात अखबारों में आ गई थी, लेकिन बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी आंखें बंद कर ली और कानों में रुई घुसा ली। राजधानी दिल्ली में यह हाल है, तो अंदाजा लगाइए कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हाल होगा। देश के शासक तब भी नहीं जाग रहे जब पीड़ित लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो यह कैसा कानून का शासन है। इससे अच्छा उदाहरण तो महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पेश किया, जिन्होंने शिकायत मिलते ही पुलिस को नोटिस जारी किया। पुलिस और बाल आयोग की अनदेखी के कारण धरने पर बैठी बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देनी पड़ी, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। क्या ऐसे हालात में इन माफियाओं से कोई मामूली आदमी टक्कर ले सकता है?

सुप्रीम कोर्ट को उस थाने के अधिकारी को तलब करके पूछना चाहिए कि उसने किस के कहने पर एफआईआर पहले दर्ज नहीं की थी। इस मामले में राजनीतिक संरक्षण देने वाले नेता भी बेनकाब होने चाहिए। यह राजनीतिक संरक्षण का ही नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद भी पुलिस धरना स्थल पर खाने का सामान नहीं जाने दे रही। जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ ऐसा सलूक हमारी राजनीति का सबसे घिनौना चेहरा है।

अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ महिला रेसलर्स की याचिका की सुनवाई ही बंद कर दी। अदालत ने कहा कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग बृजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की थी, जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इससे ठीक पिछली रात पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर डंडे भी बरसाए, जिसे देखकर राजनीति गर्मा रही है।

● आशीष नेमा

जातिवाद की जकड़न

देश का दुर्भाग्य यह है कि राजनीति में भयंकर जातिवाद घुसा हुआ है, जो अब खेल एसोसिएशनों में भी धड़ल्ले से घुस गया है। बृजभूषण पर लगे आरोपों को भी जातिगत नजरिए से देखा जा रहा है। क्योंकि धरने पर बैठे सारे खिलाड़ी जाट समुदाय से हैं, और बृजभूषण शरण सिंह ठाकुर हैं, इसलिए विपक्षी दलों के जाट नेताओं ने जंग में कूदकर इस अच्छाई और बुराई की जंग को जाट बनाम ठाकुर की लड़ाई बना दिया है। जातिगत राजनीति होने का एक सबूत यह भी है कि हरियाणा के गैर जाट खिलाड़ी धरने पर नहीं बैठे। जबकि मोदी के खिलाफ जंग का बिगुल बजा चुके जाट नेता सत्यपाल मलिक ने धरने पर जाकर इस जंग को जाट बनाम ठाकुर बना दिया, क्योंकि जब वह एक इंटरव्यू में पिछली सरकार के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ बोले थे, तब भी वह जाट बनाम ठाकुर बना रहे थे। प्रियंका गांधी और केजरीवाल ने धरने पर पहुंचकर बृजभूषण शरण के इस आरोप की पुष्टि की है कि इस धरने के पीछे विपक्ष का हाथ है। पिछली बार जब वृंदा कारत धरने पर पहुंची थीं, पहलवानों ने एक तरह से उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया था। लेकिन सत्यपाल मलिक, प्रियंका वाड्रा और केजरीवाल के साथ ऐसा नहीं किया गया। मोदी विरोधी मीडिया ने भी इसे मोदी विरोधी जंग बना दिया है, तभी एक बड़े न्यूज चैनल की एंकर जब घटना को कवर करने जंतर-मंतर पहुंचीं तो विपक्षी दलों के घुसपैठियों ने गोदी मीडिया कहकर उसके खिलाफ नारे लगाए। इससे शक पैदा होता है कि कहीं महिला पहलवानों का राजनीतिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। यह शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुसलमानों का और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ था। महिला पहलवान राक्षसी प्रवृति वाले नेताओं के खिलाफ अपनी जंग जरूर लड़ें, लेकिन खुद को किसी के राजनीतिक स्वार्थ का हथियार न बनने दें।

जब 90 करोड़ के कर्जदार हो गए थे अमिताभ बच्चन

लोगों का बदल गया था अंदाज, लेनदार दरवाजे पर बकते थे गालियां

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 90 के दशक में बैंकरप्ट हो गए थे। उनके साथ आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? क्यों कल तक उनके साथ अच्छे से बात करने वाले लोगों के अचानक तेवर बदल गए? कैसे उन पर 90 करोड़ का कर्जा हो गया था? उनके ऊपर 55 केस कौन से चल रहे थे? इन सारी बातों जवाब खुद महानायक ने दिया था।

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी लाइफ के सबसे खराब वक्त का जिक्र किया था। वीर सांघवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने 90 के दशक का वो दौर याद किया था जब वह बैंकरप्ट हो गए थे। वीर सांघवी के साथ एक पुराने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा, सारी की सारी संपत्तियां कुर्क की गईं। उन्होंने कहा, जब आप एक व्यक्तिगत गारंटी पर हस्ताक्षर करते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और इसलिए लगभग 90 करोड़ रुपए का मैं कर्जदार हो गया था। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा, जो लोग कल तक मेरी कंपनी से जुड़ने के लिए एक्साइटेड रहते थे, वो अचानक बदल गए। उनका दुश्मनी वाला रवैया हो गया था। वो काफी रूड और अपमानजनक हो गए थे। कुल मिलाकर ये मामला काफी खराब हो गया था। कर्ज देने वाले लोग दरवाजे पर आकर गालियां बकते थे और धमकियों के साथ अपने पैसे वापस मांगते थे। बिग बी ने अपने कर्ज के उन दिनों को याद कर आगे कहा, इसमें से कुछ कर्ज हमने सरकारी संस्थाओं जैसे प्रसार भारती और दूरदर्शन से लिया था। कुछ कर्ज बैंक और पर्सनल लोन से लिए थे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा मैंने और जया ने गलती से पर्सनल गारंटी भी दे दी थी। उस वक्त किसी ने हमें अच्छे से आर्थिक सलाह नहीं दी थी।

पहली नौकरी के बाद अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का पड़ा था अजीब नाम, मछली वाली से हो गईं थीं फेमस

बॉलीवुड एक्ट्रेस रहीं ट्विंकल खन्ना अब राइटर के पेशे में काफी खुश हैं। ट्विंकल ने राइटर से पहले कई फिल्मों में काम किया है। साल 2000 में आई फिल्म मेला के फ्लॉप होने के बाद ट्विंकल खन्ना ने शादी करने का फैसला लिया था। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्मों में काम नहीं किया। सुपरस्टार पिता राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना ने बचपन से फिल्मी माहौल देखा था।

ट्विंकल खन्ना ने एक्ट्रेस बनने से पहले एक नौकरी की थी। जिसमें ट्विंकल खन्ना मछलियों और प्रॉन्स की डिलेवरी करती थीं। इस काम के चलते ट्विंकल खन्ना को लोग मछली वाली कहकर भी बुलाने लगे थे। ट्विंकल खन्ना ने खुद इस किस्से का जिक्र किया है। हाल ही में ट्विंकल खन्ना ने अपने टॉक शो द आइकॉन्स में जॉनी लीवर को बुलाया था। इस टॉक शो में ट्विंकल खन्ना ने जॉनी लीवर से बात की। साथ ही अपनी पहली नौकरी का भी किस्सा बताया। दरअसल ट्विंकल खन्ना अपनी दादी की बहन की कंपनी में काम करती थीं। ट्विंकल खन्ना इस बारे में बताती हैं, मेरी दादी की बहन की एक फिश कंपनी थी। मुझे यहां काम करने का मौका मिला। मैं कंपनी में मछलियों और प्रॉन्स की डिलेवरी किया करती थी। मैं लोगों में इतना घुल मिल गई थी कि लोग मुझे मछली वाली कहकर भी बुलाने लगे थे। ट्विंकल खन्ना ने साल 1995 में फिल्म बरसात से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया।

कभी ट्रक के पीछे कपड़े बदलते थे मनोज बाजपेयी, अब 5 स्टार होटल में मिलता है स्टे, एक्टर ने याद किए पुराने किस्से

मनोज बाजपेयी ने अपने 30 साल के कैरियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। सिनेमा में मनोज बाजपेयी के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। मनोज बाजपेयी एक्टिंग की दुनिया के ऐसे चमकते सितारे हैं जिसकी दीवानगी हर छोटी-बड़ी फिल्मों में साफ देखी जा सकती है। आज मनोज बाजपेयी किसी सुपरस्टार से कम नहीं हैं।

मनोज बाजपेयी ने हाल ही में अपने पुराने दिनों को याद किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि कभी ऐसा भी समय था जब उन्हें शूट से पहले ट्रक के पीछे खड़े होकर कपड़े बदलने पड़ते थे। आज मनोज बाजपेयी किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं तो 5 सितारा होटल में उन्हें ठहराया जाता है। साथ ही मनोज को शूटिंग पर जाने के लिए 2 बड़ी कारें भी मिलती हैं। जिसमें एक कार में अकेले मनोज और दूसरे में उनका स्टाफ शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता है। मनोज बाजपेयी ने मेनस्ट्रीम और इंडिपेंडेंट दोनों तरह की फिल्मों में काम किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू नें मनोज बाजपेयी ने बताया कि मैंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनका बजट बहुत कम था। मैंने कई बार ट्रक के पीछे खड़े होकर कपड़े बदले और फिर शॉट दिया। मैंने अपने कैरियर में हर तरह की फिल्मों में काम किया है। मुझे कई फिल्मों में वैन नहीं मिली थी क्योंकि उतना बजट ही नहीं था। इंडिपेंडेंट फिल्मों में इस तरह की चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। मनोज ने कहा, बड़े बजट की फिल्मों में मुझे 5 स्टार होटल्स में रहने का मौका भी मिला।

साहित्य की मुख्यधारा में लुगदी-लेखन

क्लासिक वाले लेखन में कई तरह की संभावनाएं मौजूद थीं। विद्वान पाठक शब्दार्थ के साथ भावार्थ भी ढूंढ़ लेते थे, पर अब क्या होगा? पाठक को पढ़ते समय न चिंतन की जरूरत पड़ेगी और न 'गाइड' की। एक तरफ से पढ़ते जाओ, दूसरी तरफ से निकालते जाओ।

जब यह खबर आई कि एक विश्वविद्यालय ने 'लुगदी-लेखन' को मान्यता दी है तो मुझे अपार खुशी हुई। मैं सीधे अपने स्कूली दिनों में पहुंच गया। उस वक्त शर्मा, पाठक, नंदा और बाजपेयी आदि की ऐसी लत लगी थी कि रसायन विज्ञान और बीजगणित के बजाय दिनभर मैं सस्पेंस और थ्रिलर की दुनिया में खोया रहता था। स्कूली-किताबें जहां काटने को दौड़ती थीं, वहीं घर-परिवार में प्रतिबंधित किताबें छुप-छुप के पढ़ता रहता। सभ्य समाज में यह 'लुगदी-लेखन' वर्जित था।

उस समय अपन को लेखन के किसी टाइप का पता नहीं था। बस रोमांटिक और जासूसी किताबें परमानंद देती थीं। इनकी वजह से पढ़ाई से मन एकदम उचट गया था। नतीजा यह हुआ कि किसी तरह से बस पास भर हो पाया। यदि उस जमाने में आज वाली 'स्कीम' आ जाती तो विद्या-कसम, पूरे प्रदेश में टाप करता, लेकिन यह मेरी सोच थी।

इस फैसले का ताप मापने के लिए मैं इंटरनेट-मीडिया में गया। वहां साहित्य की 'मुख्य-धारा' में जबर्दस्त उबाल आया हुआ था। साहित्य में हुए इस हादसे के बाद से मुख्यधारा के कई लेखक गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें से एक बड़े पाठ्यक्रम-लेखक कुछ ज्यादा ही चोटिल लग रहे थे। अब तक उन्होंने जो लिखा था, कहीं न कहीं 'फिट' हो चुका था। तकरीबन हर विश्वविद्यालय या बोर्ड में उनकी किताबें लगी हुई थीं।

समाज और देश पर जब भी संकट आता है तो मेरे लेखक-मित्र सहजता से आंखें मूंद लेते हैं, पर यह अलग तरह का संकट था। इसलिए वह इंटरनेट-मीडिया पर बेकाबू हो गए, 'यह संकट हम पर नहीं, साहित्य पर गिरा है। हमारे 'क्लासिक-लेखन' को 'लुगदी-लेखन' से 'रिप्लेस' किया जा रहा है। यह गंभीर खतरा है। साहित्य नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। आज लुगदी-लेखन विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ाया जाने लगा है तो कल को पुस्तकालयों में भी इन्हीं का कब्जा होगा।

क्लासिक वाले लेखन में कई तरह की संभावनाएं मौजूद थीं। विद्वान पाठक शब्दार्थ के साथ भावार्थ भी ढूंढ़ लेते थे, पर अब क्या होगा? पाठक को पढ़ते समय न चिंतन की जरूरत पड़ेगी और न 'गाइड' की। एक तरफ से पढ़ते जाओ, दूसरी तरफ से निकालते जाओ। बरसों से जो कृतियां ऐसे पुस्तकालयों में खप रही थीं, वहां से भी उनका पत्ता कट जाएगा। फिर उनके 'लेखक' बने रहने में भी खतरा होगा। वे 'मुख्य-धारा' से ही बह जाएंगे।' उनकी इस लंबी चिंता पर एक वरिष्ठ लेखक ने बड़े मार्के की टीप दर्ज की, 'हमारी सबसे बड़ी चिंता सम्मानों को लेकर है।

अभी कम मारामारी है, जो यह नई विधा भी 'कंपटीशन' में उतार दी गई? यह संकट साहित्य से अधिक हमारे सम्मान का है। निराला, परसाई और मुक्तिबोध को जो मिलना था, मिल चुका। उन्हें हटाकर सरकार ठीक ही कर रही है। वे हटेंगे, तभी हमारे लिए जगह बनेगी, लेकिन यह सरासर गलत है कि 'लुगदी-लेखकों' को हमारे मुकाबले में खड़ा किया जाए। वैसे यदि सरकार को ऐसे लेखन से ज्यादा प्यार है तो यह कमी हम स्वयं पूरी करते हैं। हमारा संपूर्ण लेखन उत्कृष्ट-किस्म की लुगदी से किसी प्रकार भी कम नहीं है।

अभी तक प्रकाशक ने रॉयल्टी नहीं दी, कम से कम सरकार ही हमें इसका मुआवजा दे!' दूसरी टीप एक उभरते हुए कवि की थी, 'सबसे बड़ा संकट कविता में आने वाला है। पारंपरिक साहित्य में कविताई का खूब चांस है। लुगदी में केवल 'क्राइम' है, थ्रिल है, लोकप्रियता है। उपन्यास और कहानियां लिखने वाले तो फिर भी 'सर्वाइव' कर जाएंगे, लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कविता का क्या भविष्य होगा?'

इस टिप्पणी के बाद चर्चा और उत्तेजक हो गई। एक सम्मानित-कवि ने कहा, 'यह केवल समझ का फेर है। हमारी बोरी भर कविताएं आज भी या तो प्रकाशक के यहां या पुस्तकालयों में जमा हैं। सरकार चाहे तो इन्हें 'लुगदी-लेखन' की मान्यता दे सकती है। वे अब न मेरे और न ही जनता के किसी काम की हैं। पाठ्यक्रम में लग जाएं तो प्रकाशक का भी भला हो, हमारा भी। कम से कम 'रद्दी-लेखन' के तमगे से तो मुक्ति मिलेगी!'

जल्द ही यह पोस्ट वायरल होने लगी। आखिरकार एक जिम्मेदार शिक्षाशास्त्री ने स्थिति स्पष्ट की, 'हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। जो उपेक्षित लेखक थे, उन्हें मौका मिला है और केवल असुविधाजनक पाठ हटाए गए हैं। अब सियासत की तरह साहित्य में भी विकल्प है कि आप जिसे चाहें, उसे चुनें।'

● **संतोष त्रिवेदी**

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

युवाओं को हर विधा में पारंगत करने को तैयार शिवराज सरकार

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

क्रियान्वयन कार्य-योजना

शिक्षा और कौशल

- 500 से अधिक संस्थाओं में लगभग 1 लाख छात्रों को इन्क्यूबेटर सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों को NIRF रैंकिंग में लाने के लिए समन्वित कार्यवाही की जाएगी।
- तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य की तकनीकी संस्थाओं में 8 लाख वर्ग फुट में टेक्नोलॉजी Business incubator स्थापित करेगा, जो देश का सबसे बड़ा Business incubator होगा, जिसका नाम [illegible] टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर होगा।
- ई- अध्ययन सामग्री के निर्माण एवं उपलब्धता के लिए डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की जाएगी, जिससे उच्च गुणवत्ता के ई-कंटेन्ट से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।
- [illegible] की उपाधियां अर्जित करने का प्रावधान।
- ई- शिक्षा [illegible] पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को ई-अध्ययन सामग्री (ई-कंटेन्ट) उपलब्ध कराई जाएगी।
- ई - अध्ययन सामग्री के निर्माण एवं उपलब्धता के लिए 10 संभाग मुख्यालय में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना। NEP 2020 के अनुरूप वर्ष 2025 तक पचास प्रतिशत तथा वर्ष 2030 तक सौ प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ना।
- इंजीनियरिंग कॉलेजों को 50 छात्रों की अंतिम वर्ष में पढ़ाई व्यवस्था।
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT), सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SAAS), [illegible] तथा [illegible] का उपयोग कर सभी तकनीकी संस्थानों के [illegible] और कंटेन्ट के Collaboration से exhaustive learning environment तैयार किया जाएगा, जिससे 200 से अधिक संस्थानों के 1 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।
- तकनीकी छात्रों को फिटनेस सेवाएं (Fitness services) प्रदान करने में सक्षम बनाया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन [illegible] की व्यवस्था।
- भारत का पहला सबसे विशाल प्रशिक्षक फ्लीट (Mentor fleet) तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के [illegible] पोर्टल का उपयोग कर शिक्षक और छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- अपने संस्थानों और सरकारी इन्टर्नशिप में छात्रों के लिए [illegible] के उद्देश्य से आईटी/वेब आधारित [illegible] और [illegible] जैसी सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
- राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम का उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन।
- [illegible] - आधारित [illegible] विद्यार्थियों के लिए ई-अध्ययन सामग्री की उपलब्धता।
- विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा का पाठ्यक्रम में समावेश।
- कक्षाओं में 4 C (Critical thinking, Communication, Creativity, Collaboration) पर आधारित गतिविधियों का आयोजन।
- डिजिटल और वित्तीय रूप से जागरूक बनाने के लिए 9-12 की कक्षाओं में सूचना एवं तकनीकी को आधार बनाकर समूह गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट कार्य द्वारा डिजिटल विकास करना, और अंततः कौशल आधारित रोजगार के अवसरों के अनुरूप बनाना।
- नेशनल प्रोफेशनल स्टैन्डर्ड फॉर टीचर्स (NPTS) के अनुसार शिक्षकों का दक्षता संवर्धन किया जाएगा।
- [illegible] व्यावसायिक ट्रेड प्रारंभ किए जाएंगे।
- 9200 उच्च गुणवत्ता वाले सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। इससे प्रदेश के सभी हिस्सों में 15-20 किमी के क्षेत्र की परिधि में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल उपलब्ध होगा।
- हर बच्चे को शिक्षा प्रणाली से बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षित करना।
- [illegible] एवं अन्य माध्यमों से गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश के युवाओं को उनकी क्षमताओं से अवगत कराते हुए संपूर्ण विकास करने के लिए सशक्त करना, जिससे वे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में प्रभावी योगदान कर सकें।

मध्यप्रदेश युवा नीति 2023 को युवा महापंचायत 2022 से प्राप्त सुझावों, राष्ट्रीय युवा नीति (ड्राफ्ट) 2021, विभिन्न देशों की युवा नीति, देश के अन्य राज्यों की युवा नीति एवं मध्यप्रदेश राज्य युवा नीति 2008 के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। यह नीति प्रदेश के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लिया गया कदम है, जिसमें युवा एक अहम भूमिका निभाएंगे। इस नीति से मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनकर उभरेगा, जिसमें युवाओं की ऊर्जा और योग्यता के सभी बहुआयामी सरोकार समाहित होंगे। इसमें क्षेत्रीयता, जातिवाद और लिंग असमानता नहीं होगी।

युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य

- युवाओं को विधान मंडल, कार्यपालिका न्यायपालिका, पंचायत राज संस्थानों/ स्थानीय निकायों तथा शासकीय विभागों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश विकसित किए जाएंगे।
- 30 वर्ष से कम आयु के जन-प्रतिनिधियों को क्रॉस लर्निंग के अवसरों का लाभ उठाने के लिए देश भर में मॉडल पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों में एक्सपोजर भ्रमण करवाया जाएगा, जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपयुक्त सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू कर सकें।
- युवाओं एवं प्रोफेशनल्स के द्वारा सेवानिवृत्त तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑन-ग्राउंड एवं ऑनलाइन स्वयंसेवा को बढ़ावा देने तथा एक मंच प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य स्वयंसेवक कार्यक्रम विकसित किया जाएगा।
- ग्रामीण स्तर पर युवाओं को संगठित कर स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब गठित किए जाएंगे।
- सामाजिक कार्य करने वाले सक्रिय युवाओं को राज्य एवं जिला युवा सलाहकार परिषद में जोड़ा जाएगा।
- यूथ महापंचायत जैसे कार्यक्रमों का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा भ्रमण के लिए संचालित माँ तुझे प्रणाम योजना में जन अभियान परिषद एवं नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को भी जोड़ा जाएगा।
- युवाओं से संबंधित योजनाओं का समय-समय पर सोशल ऑडिट किया जाएगा।

क्रियान्वयन रूपरेखा

- राज्य युवा आयोग का पुनर्गठन।
- जिला स्तर पर युवा संसाधन केंद्रों की स्थापना।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय युवा प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा।
- राष्ट्रीय तथा राज्य युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राज्य एवं जिला स्तर की विभिन्न सलाहकार समितियों में सम्मिलित करना।
- मध्यप्रदेश युवा कल्याण सूचकांक विकसित करना।
- युवा बजट का निर्माण।

रोज़गार और उद्यमिता

- विश्वविद्यालयों, तकनीकी तथा प्रोफेशनल संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में स्टार्ट-अप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेन्ट इनोवेशन फंड बनाया जाएगा।
- स्टूडेन्ट इनोवेशन फंड के उपयोग द्वारा प्रतिवर्ष 100 नवाचारों/ स्टार्ट-अप आईडियाज को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- एमएसएमई विभाग द्वारा स्टार्ट-अप एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। पोर्टल पर उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
- पीएम स्टैंड -अप स्टार्ट-अप और अतिरिक्त लाभों के तहत पेश किए गए विशेष अवसरों का उपयोग कर महिला पॉलिटेक्निक संस्थान में विशेष इन्क्यूबेटर का गठन किया जाएगा। जिससे महिला छात्राएं उनके एवं अन्य महिलाओं के सामने आने वाली विशेष समस्या का समाधान कर सकेंगी। संस्थागत ढाँचे का NOI नेटवर्क बनाया जाएगा।
- रोज़गार केन्द्र के माध्यम से गिग अर्थ-व्यवस्था को मानव संसाधन उपलब्ध करवाना।
- राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी प्लेसमेंट की व्यवस्था करवाना।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना एवं सीड मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- बालिकाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायेगी, जिसमें हैण्डलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोककलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी।
- जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) के प्रभावी उपयोग से परंपरागत बुनकरों एवं कारीगरों के लिये बेहतर बाजार व ऊँचा मूल्य उपलब्ध कराना।
- अप्रेंटिसशिप को पारंपरिक उद्योगों तक सीमित न रख, तकनीकी संस्थाओं को Industry 4.0 और New Age Technology में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का केन्द्र बनाना।
- प्रदेश की महिला हाथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों को NID एवं NIFT संस्थाओं के माध्यम से आधुनिक डिजाइन और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- युवा हाथकरघा/ हस्तशिल्प कारीगरों को माडर्न टेक्सटाईल फैक्टरीज/ एक्सपोर्ट हाउसेज में अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- तकनीकी संस्थानों में छात्रों को स्टार्ट-अप योजना लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बैकवर्ड इंटीग्रेशन को दृष्टिगत रखते हुए डाबी, जेगार्ड, लूम इत्यादि मशीनरी के नवीनतम मॉडलों की मध्यप्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए युवाओं को सरल रूप से ऋण प्रदाय करवाना एवं तकनीकी एजेंसियों से मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग लेना।
- तकनीकी शिक्षा के सभी विषयों के पाठ्यक्रमों में Industry 4.0 व अन्य New Age Technology का समावेश।
- राज्य के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेसमेंट प्राप्त करने के लिए कार्यवाही।

खेल एवं फिटनेस

- जिला स्तर पर खेल अकादमी स्थापित करने के लिए पूर्व खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करना।
- विकासखण्ड स्तर पर खेल अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री खेल अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ की जायेगी।
- अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पहचान बनाने वाले खिलाड़ियों को उनके गृह जिले का स्पोर्टस ब्रांड एंबेसडर बनाया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक खेलों जैसे मलखंभ, कबड्डी, खो-खो, मलखा तथा थांग-टा आदि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाओं की खोज एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।
- विभिन्न खेलों में प्रतिभाओं की मैपिंग के लिए एक खेल प्रतिभा खोज पोर्टल विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा।
- खेल एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिये नवीन डिग्री प्रोग्राम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे।
- पैरा खिलाड़ियों को स्पोर्टस स्कॉलरशिप प्रदान की जायेगी।

स्वास्थ्य

- एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, बीएमआई और अन्य गंभीर बीमारियों की जाँच के लिए समय-समय पर लक्षित स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाये जाएंगे।

पर्यावरण

1. ग्रीन इकोनामी एवं ग्रीन जॉब्स विषय पर केन्द्रित प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जायेगी एवं मास्टर ट्रेनर का एक कैडर विकसित किया जाएगा।
2. इको फिलॉसफी, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य, पर्यावरण प्रदूषण, वेटलैंड्स एवं अपशिष्ट प्रबंधन विषयों पर शोध / अध्ययन के लिये स्टाइपेन्ड के साथ समर एवं विंटर इंटर्नशिप, फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।
3. महाविद्यालय के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रयोगशालाओं एवं निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन जैसी सुविधाओं में शैक्षणिक भ्रमण कराए जाएंगे।
4. पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न विषयों पर केन्द्रित लघु अवधि वाले कार्यक्रम जैसे नेचर वॉक, पक्षी दर्शन एवं गणना, वेटलैंड वॉक इत्यादि को विभिन्न विभाग एवं गैर-शासकीय संगठन के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा।
5. शासकीय विभागों, गैर-शासकीय संस्थानों, अन्य संस्थानों के साथ प्रत्येक वर्ष जिला स्तर पर महाविद्यालय के छात्र- छात्राओं के लिए जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्य, वायु प्रदूषण, भोजन के अपव्यय, मिशन LIFE, वेटलैंड संरक्षण, जैव-विविधता संरक्षण आदि पर केन्द्रित पर्यावरण संगोष्ठियाँ की जाएंगी।
6. एप्को द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए जैविक कृषि, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, संरक्षित कृषि एवं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जैसे विषयों पर कार्यशालाएँ की जाएंगी।

कला-संस्कृति

- इन्क्यूबेशन केंद्रों के रूप में सांस्कृतिक आर्ट स्टूडियो की स्थापना।
- परंपरागत एवं जनजातीय लोक कला को बढ़ावा देने के लिए 50 युवा कलाकारों को फैलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में ग्रामीण जीवन का अनुभव कार्यक्रम के लिए चयनित ग्राम में कारीगरों, शिल्पकारों एवं अन्य कार्यों के लिए ग्रामीण युवाओं को चिन्हित किया जाएगा एवं पर्यटकों का भ्रमण इन ग्रामों में कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों की संतानों के लिए फैशन टेक्नोलॉजी / डिजाइन संस्थानों में स्कालरशिप / सीट रिजर्व करने की व्यवस्था की जाएगी।
- विभिन्न डिजाइन/फैशन टेक्नोलॉजी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए हाथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में इंटर्नशिप की नीति तैयार की जाएगी।
- युवाओं को हाथकरघा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु प्रेरित करने के लिए स्नातक स्तर पर हाथकरघा संबंधी कोर्सेस का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसके छात्रों को एक्सट्रा क्रेडिट प्वाइंट की सुविधा प्रदाय करवाना।
- रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में लगाई जाने वाली प्रदर्शनियों / आयोजनों में प्रमुख पर्यटन स्थलों / आस-पास के ग्रामों के युवाओं के उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के रेस्पॉन्सिबल सोवेनियर कार्यक्रम अंतर्गत कुछ चयनित स्थलों पर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी एवं स्थानीय कला/हस्तशिल्प से संबंधित कार्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन एवं ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम अंतर्गत चयनित ग्रामों में लोक गायन एवं लोक नृत्य से जुड़े युवा समूहों की प्रस्तुतियाँ पर्यटकों के समक्ष एवं विभिन्न आयोजनों/ समारोहों में कराई जाएगी।

D-19089/23

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

सुराज से होंगे जनता के सपने साकार

मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद खाली हुई भूमि पर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिए आवास निर्माण के लिए सुराज नीति-2023 लागू की गई है।

सरकार ने माफिया से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर सुराज कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ लोगों को सभी जरूरी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। नीति का उद्देश्य बिना सरकारी बजटीय सहायता के पुनर्धनत्वीकरण नीति के अनुरूप सुराज कॉलोनी के तहत ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवासहीनों के लिए किफायती आवास प्रदान करना और अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि का शहर के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयोग करना है।

सुराज नीति के मुख्य बिंदु...

- 1 अप्रैल 2020 के बाद अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की योजना।
- अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का एक टुकड़ा निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा, जिसके बदले शेष भूमि में ईडब्ल्यूएस आवास के लिए सुराज टॉवर बनेगा।
- निजी डेवलपर को दिए जाने वाले भू-खंड के आरक्षित मूल्य की गणना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापित नीति के अनुसार खुली निविदाओं के आधार पर की जाएगी।
- छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय पट्टे भी कॉलोनी विकसित कर दिए जा सकेंगे।
- सुराज कॉलोनी में सड़क, जल-प्रदाय, बिजली, बगीचा आदि की सुविधा होगी।
- निर्माण होने के बाद इकाइयों का आवंटन कमजोर आय वर्ग के आवासहीन को नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।
- संबंधित भूमि के एक भाग का उपयोग आवासहीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सुराज कॉलोनी के अंतर्गत भवन/ प्रकोष्ठ/ भूखण्ड के निर्माण के लिए किया जायेगा। सुराज कॉलोनी की अनुमानित परियोजना लागत के अनुरूप मूल्य के सीएलपी को निजी विकासकर्ता द्वारा 'भू-स्वामी अधिकार' में उपयोग किया जायेगा।
- योजना के क्रियान्वयन के लिए अन्य सभी प्रक्रियाएँ राज्य में स्थापित रिडेंसीफिकेशन नीति-2022 के अनुसार की जाएगी।
- सुराज टॉवर/कॉलोनी का निर्माण समय-सीमा और गुणवत्ता से करने के प्रावधान किए गए हैं। सुराज टॉवर कॉलोनी निर्माण के बाद अगले पाँच वर्ष तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का दायित्व और 3 वर्ष तक कॉलोनी का रख-रखाव संचालन एवं मरम्मत का दायित्व निजी डेवलपर का रहेगा।

"मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत गाँव में चिन्हित करके हर परिवार को जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया जाएगा। मध्यप्रदेश में 23000 एकड़ से ज्यादा जमीन माफियाओं से मुक्त कराई गई है। हम उस जमीन पर सुराज कॉलोनी की स्थापना कर गरीबों को उस जमीन पर बसाएंगे।

- शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

35000 लोगों को मिले भूखंड

टीकमगढ़ और सिंगरौली जिले में सरकार ने माफिया से मुक्त कराई जमीन भूमिहीनों को दी है। मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में दोनों जिले में 35 हजार से अधिक लोगों को योजना का लाभ दिया गया है।

सरकार के प्रयासों से बढ़ता मध्यप्रदेश

D-19089/23 जनसंपर्क विभाग